Monday, 23 November, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 6—सोमवार, 23 नवम्बर, 1964 / 2 कार्तिक, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
137	भारत-पाक गृह-कार्य मंत्रियों का सम्मेलन	473—77
138	काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक	477—77
139	भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	479
140	भारत में परमाणु बम का बनाया जाना	480—83
141	शिलांग में पाकिस्तानी सहउच्चायुक्त का कार्यालय	483—85
142	अफ्रीकी देशों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध	486—88
143	संयुक्त राष्ट्र महा सभा की कार्य-सूची	488—91
144	रूस के नेतृत्व में परिवर्तन	492—94

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
136	पीकिंग में विज्ञान सम्बन्धी गोष्ठी	494
145	राष्ट्रीय रक्षा कोष की लापता रसीद बुकें	494—95
146	संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाना	495
147	पुर्तगाल सरकार द्वारा परिचालित नोट	495—96
148	औद्योगिक सन्धि संकल्प	496
149	संयुक्त राष्ट्र महा सभा का अधिवेशन	496—97
150	मूल्य देशनांक	497—98
151	प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा उत्पादन	498
152	टेलीविजन	498—99
154	केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था	499
155	स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा की शर्तें	500
156	विमान दुर्घटना	500
157	नये आयुध कारखाने	501—02
158	सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक संबन्ध	502
159	कमाण्डरों की बैठक	503
160	थुम्बा का राकेट छोड़ने का स्टेशन	503
161	बर्मा में भारतीयों की आस्तियां	504
162	पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग	504

CONTENTS

No. 6. Monday, November 23, 1964/Kartika 2, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
137	Indo-Pak. Home Ministers' Conference	473—77
138	U.N. Observers in Kashmir	477-78
139	Violations of Indian Air Space	479
140	Manufacture of Atom Bomb in India	480—83
141	Office of Pakistan Assistant High Commissioner in Shillong	483—85
142	Diplomatic Relations with African countries	486—88
143	Agenda of U.N. General Assembly	488—91
144	Change in Soviet Leadership	492—94

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
136	Science Symposium in Peking	494
145	Missing N.D.F. Receipt Books	494-95
146	Seating of China in U.N.	495
147	Note circulated by Portugal Government	495-96
148	Industrial Truce Resolution	496
149	U.N. General Assembly Session	496-97
150	Price Index	497-98
151	Defence Research and Production	498
152	Television	498-99
154	Central Staff Training and Research Institute	499
155	Service Conditions of Staff	500
156	Air Crashes	500
157	New Ordnance Factories	501-02
158	Industrial Relations in Public Undertakings	502
159	Commanders' Meeting	503
160	Thumba Rocket Launching Station	503
161	Assets of Indians in Burma	504
162	Use of U.S. Weapons by Pakistan	504

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
318	बाह्य अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय करार	504–05
319	आकाशवाणी का पुनर्गठन	505
320	काश्मीर में युद्धविराम रेखा पर हुई मृत्यु	505
321	टेलीफोन एक्सचेंज	506
322	हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में डाक तथा तारघर	506
323	हिन्दी टाइपराइटर्स	507
324	अमरीका से राडार सेट	507
325	नेपाल में संचार प्रणाली में सहायता देने के लिये भारतीय प्रविधिक	507–08
326	तिब्बत को नेपाल के रास्ते निर्यात	508
327	चीनी आरोप	508–09
328	नौसेना के विमान का अनधिकृत प्रयोग	509
329	बेरोजगार व्यक्तियों के लिए मार्ग दर्शन	509
330	श्री फिज़ो	510
331	उपनगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी	510
332	आर्डिनेन्स फैक्टिरियों के कर्मचारी	510–11
333	इस्पात उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	511
334	पंजाब में नौकरी के लिए वाउचर	511
335	पंजाब में काम दिलाऊ दफ्तर	511
336	श्रम संगठन	512
337	राष्ट्रीय रक्षा कोष	512–13
338	भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेहरू पर पूरी फिल्म	513
339	आणविक अनुसन्धान	514
340	फिजी में भारतीय	514
341	गोलीसह नायलन कपड़ा	514
342	काहिरा दूतावास द्वारा स्वागत समारोह	515
343	क्रिकेट का आंखों देखा हाल	515
344	भारत के बनाये गये विमान	515–16
345	डाक-तार विभाग के बाढ़पीड़ित कर्मचारी	516
346	विभागीय तरक्कियां	516–17
347	अमरावती में रेडियो स्टेशन	517
348	जन-संचार केन्द्र	517
349	जर्मन गणतन्त्र को मान्यता	517–18
350	अणु शक्ति का विकास	518
351	लंका में रेल दुर्घटना	518
352	भटिंडा के पास विमान दुर्घटना	519
353	विदेशी डाकघर, बम्बई	519
354	केरल डाक-तार सर्विस	519–20

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
318	International Agreement on Outer Space .	504–05
319	Reorganisation of A.I.R.	505
320	Casualties on Cease Fire Line in Kashmir .	505
321	Telephone Exchanges . . .	506
322	P. & T. Offices in Hindi Regions .	506
323	Hindi Typewriters . . .	507
324	Radar Sets from U.S.A.	507
325	Indian Technicians for helping tele-communications system in Nepal	507–08
326	Exports to Tibet via Nepal . . .	508
327	Chinese Allegations	508–09
328	Unauthorised use of Navy Plane	509
329	Guidance to Unemployed	509
330	Mr. Phizo	510
331	Unemployment in Urban Areas	510
332	Employees of Ordnance Factories . . .	510–11
333	Wage Board for Steel Industry . . .	511
334	Vouchers for Employment in Foreign Countries .	511
335	Employment Exchanges in Punjab	511
336	Labour Organisations	512
337	National Defence Fund	512–13
338	Full length film on late Prime Minister Nehr	513
339	Atomic Research . .	514
340	Indians in Fiji	514
341	Bullet Proof Nylon Cloth . . .	514
342	Reception by Cairo Embassy . . .	515
343	Cricket Commentary	515
344	India-Built Aircraft	515–16
345	Flood Affected P. and T. Employees . .	516
346	Departmental Promotions	516–17
347	Radio Station at Amravati	517
348	Mass Communication Centre	517
349	Recognition of German Democratic Republic .	517–18
350	Development of Atomic Energy . .	518
351	Railway Accident in Ceylon .	518
352	Air Crash near Bhatinda .	519
353	Foreign Post Office, Bombay	519
354	Kerala P. & T. Circle.	519

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
355	हिन्दुस्तान टलीप्रिंटर्स लिमिटेड	520
356	रूस में भारतीय राजदूत	520
357	सीमेंट उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	521
358	नेफा में बिजली लगाना	521–22
359	माली के राष्ट्रपति	522
360	देवरिया डाकघर	522–23
361	डाकघरों में जमा धन	523
362	सूचना और प्रसारण मंत्री की विदेश यात्रा	523
363	कोयला खानों में कदाचारों के आरोप	524
364	कोयला खान कल्याण निधि	524
365	बर्मा स्थित भारतीयों के लिये आपातकालिक प्रमाणपत्र	524–25
366	बागानों में काम की स्थिति	525
367	नेताजी हाल सोसायटी के मंत्री के साथ प्रधान मंत्री का पत्र-व्यवहार	525–26
368	भारत-पाक सीमांकन	526
369	काश्मीर की स्थिति में परिवर्तन के विरुद्ध पाकिस्तानी विरोध-पत्र	526–27
370	डाक व तार विभाग में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां	527
371	मैंगनीज कामगरों के लिए मजूरी बोर्ड	527
372	मैंगनीज की खानों के लिये औद्योगिक व्यायाधिकरण	528

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) . . . 528–30

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . 530

जनमत संग्रह मोर्चे के नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्य—

श्री प्रकाश वीर शास्त्री . . . 530

श्री हाथी . . . 530

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . 532

विधेयक पर राय . . . 534

निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा उसके बारे में मंत्री का उत्तर . . . 534

अम्बाला जेल में श्री हुकम चन्द कछवाय के साथ किये गये दुर्व्यवहार संबंधी प्रतिवेदन के बारे में—

श्री हुकम चन्द कछवाय . . . 534

श्री हाथी . . . 534

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
355	Hindustan Teleprinters Limited .	520
356	Indian Ambassador in U.S.S.R. .	520
357	Wage Board for Cement Industry	521
358	Electrification in NEFA	521-22
359	President of Mali . .	522
360	Post Office Deoria . .	522-23
361	Deposit in Post Offices	523
362	Tour Abroad of Minister of Information & Broadcasting	523
363	Allegations of Malpractices in Collieries	524
364	Coal Mines Welfare Fund . .	524
365	Emergency Certificates for Indians in Burma .	524-25
366	Employment Position in Plantations . .	525
367	Correspondence with Secretary, Netaji Hall Society	525-26
368	Demarcation of Indo-Pak. Border . .	526
369	Pak. protest against change in status of Kashmir .	526-27
370	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in P. & T.	527
371	Wage Board for Manganese Workers .	527
372	Industrial Tribunal for Manganese Mines	528

Re : Calling Attention Notices—
(Query) . . 528-30

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . 530

Statements by Plebiscite Front Leaders—

Shri Prakash Vir Shastri 530

Shri Hathi 530

Papers Laid on the Table 532

Opinions on Bill 534

Statement by Member uuder Direction 115 and Minister's reply thereto 534

Re: Report on mal-treatment of Shri Hukam Chand Kachhavaiya in Ambala Jail 534

Shri Hukam Chanu Kachhavaiya . . . 534

Shri Hathi 534

विषय	पृष्ठ

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव--

श्री स्वर्ण सिंह	534
श्री मी० रू० मसानी .	540
श्री हनुमन्तैया . . .	544
डा० मा० श्री अणे .	545
श्री भागवत झा आजाद . .	548
श्री नाथ पाई . .	559
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	554
श्री फ्रैंक एन्थनी . . .	556
डा० राम मनोहर लोहिया . .	557
श्री विद्याचरण शुक्ल	559
श्री रा० गि० दुबे	560
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद .	561
श्री शिकरे	563

Motion re : International Situation

Shri Swaran Singh	534
Shri Masani	540
Shri Hanumanthaiah	544
Dr. M.S. Aney	545
Shri Bhagwat Jha Azad . . .	548
Shri Nath Pai	550
Shri Harish Chandra Mathur . . .	554
Shri Frank Anthony	556
Dr. Ram Manohar Lohia	557
Shri Vidya Charan Shukla	559
Shri R.G. Dubey	560
Shri Brajeshwar Prasad	561
Shri Shinkre	563

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीड, श्री (गुडिवाडा)

अजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)

अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)

इम्बोचिबावा, श्री इजुकुढेक्कल (पोन्नाणि)

इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उ—क्रमशः

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पुदुकोट्टै)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापट)

ए

एंथनी, श्री फेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)

कछवाय, श्री हुक्म चन्द (देवास)

कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य प्रदेश)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडाडी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)

कनकसवै, श्री (चिंदाबरम्)

कन्डप्पन, श्री (तिरूचेगोड)

कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)

कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)

कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)

करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)

कर्णी सिहजी, श्री (बीकानेर)

कांबले, श्री तु० द० (लातूर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किशन वीर, श्री (सतारा)

किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

कुमारन, श्री मे० क० चिरयिन्कील)

क—क्रमशः

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)

कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)

कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)

कृष्ण, श्री मं० रं० पद्दपल्लि)

कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)

केदरिया, श्री छ० म० मांडवी)

केप्पन, श्री चेरियन (मुबात्तुपुजा)

केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कोया, श्री (कोजीकोड)

कोलाको, डा० (गोग्रा, दमन, ग्रौर दीव)

कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)

कोजलगी, श्री हे० वी० (बलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)

खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)

खां, श्री उस्मान ग्रली (ग्रनन्तपुर)

खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)

खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)

खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)

गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)

गणपति राम, श्री (मछलीशहर)

गयासुद्दीन ग्रहमद, श्री (धुबरी)

गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)

गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)

गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री काशीराम (ग्रलवर)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)

गुप्त, श्री बादशाह (मनपुरी)

गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)

गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)

गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)

गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)

गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)

घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)

चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)

चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)

चतर सिंह, श्री (चम्बा)

चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)

चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)

चन्द्रभान सिंह, श्री (बिलासपुर)

चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)

चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचर)

चव्हाण, श्री दा० रा० (करोड़)

चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)

चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)

चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)

चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)

चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबलराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेगन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुला राम, श्री (घाटमपुर)

तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)

त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

थेंगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)

थेदगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)

दलजीत सिंह, श्री (उना)

दशरथ देव, श्री (त्रिपुरापुर्व)

दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)

दाजी, श्री होमी (इंदौर)

दास, श्री (तिरुपति)

दास, श्री निगम तारा (जमुई)

दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)

दास, डा० मनमोहन (औग्रासम)

दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्द हार्बर)

दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)

दिनेश सिंह, श्री (सालोन)

दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)

दरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)

देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)

देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)

देशमुख, श्री शिवाजी शंकरराव (परभणी)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)
दोराइ, श्री काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टई)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)
धवन, श्री (लखनऊ)
धूलेश्वर मीन, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)
नम्बियार, श्री आनन्द (तिरूचिरापल्लि)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नायर, श्री दे० जी० (पंचमहल)
नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)
नायक, श्री मोहन (भजनगर)
नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)
निगम, श्रीमती साविली (बांदा)
निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित--अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)
नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)
पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)
पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)
पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)
पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (पाटन)
पटेल, श्री मानसिंह पु० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

प--क्रमशः

परमशिवन, श्री० स० क० (इरोड)

पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाटा)

पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)

पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)

पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)

पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर--दक्षिण)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई--दक्षिण)

पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)

पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (विसलेमपुर)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)

पाराशर, श्री (शिवपुरी)

पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)

पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)

पुरी, श्री दे० द० (कैथल)

पृथवीराज, श्री (दौसा)

पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)

प्रताप सिंह, श्री (सरमूर)

प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली--करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)

बदरुद्दजा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर).

फ--क्रमशः

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, सोनुभाई दागडू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बाकलीवाल, श्री (दुर्ग)

ब

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौसी)

बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बृजराज सिंह--कोटा, श्री (झालावाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)

भ--क्रमशः

भट्टाचार्य (श्री च० का० (रायगंज)

भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)

भवानी, श्री लखमू (बस्तर)

भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)

भार्गव, पंडित मु० बि० ला० (अजमेर)

भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)

मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)

मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)

मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)

मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)

मेनन, श्री (दार्जिलिंग)

मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)

मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)

मरुथैया, श्री (मेलर)

मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)

मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)

मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)

मसूरिया, दीन, श्री (चैल)

महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)

महतो, श्री भंजहरि (पुरुलिया)

महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)

महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)

महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)

महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़--उत्तर)

म—क्रमशः

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता—मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डविड (लोहरदगा)
मूरमू, श्री सरकार (बलरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झूंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद, युसूफ, श्री (सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई—उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मकुन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

म--क्रमशः

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कु० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारावाड़--दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरमैया, श्री को० (गुंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बंसवारा)
रांउत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)

स--क्रमशः

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंडी)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
राम नाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलवर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलेम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा) :
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकट सुब्बा (तिन्डीवनम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजकोट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्भम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फरुखाबाद)

व

बर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
बर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
बर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
बर्मा, श्री सूरजमल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, श्री (विशाखापटनम)

व—क्रमशः

विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटा सुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास, (साबरमती)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)
शास्त्री, श्री लालबहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मुड्या)
शिव नारायण, श्री (बांसी)

श—क्रमशः

शिव प्रधासन, श्री (पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, (श्री दरभंगा)
श्रीनिवासन , डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मी मल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री य० ना० (सुन्दरगढ़)
सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद (छप्परा)
सिंह, श्री स० टी० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

स—क्रमशः

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्बारामन, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह, नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)
स्वर्णसिंह, श्री (जलन्धर)
स्वामी, श्री मड्लावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम-स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)

ह—क्रमशः

हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी. श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोण्डा)
हिम्मतसिंहका, श्री (कच्छ)
हुक्म सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री
गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी
वैदेशिक कार्य मंत्री —श्री स्वर्ण सिंह
रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल
विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री —श्री अ० कु० सेन
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चह्वाण
इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर
संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला
श्रम और रोजगार मंत्री—श्री संजीवय्या
पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह
असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री रघुरामैया
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन
रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह
शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री—श्री हजरनवीस
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव
योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत
प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री— श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चह्वाण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री— श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

सामजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री—श्री भगवती

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० श० नास्कर

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव—श्री शिन्दे

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री डा० एरिंग

सिचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव —श्री सै० अ० मेहदी

प्रधान मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित सेन

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री स० चु० जमीर

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव—श्री तिम्मय्या ।

तृतीय माला, खंड 35, अंक 6 सोमवार, 23 नवम्बर, 1964/2 अग्रहायण, 1886 (शक)

Third Series, Vol. XXXV, No. 6 Monday, November 23, 1964/Agrahayan 2, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 23 नवम्बर, 1964/2 अग्रहायण, 1886 (शक)

Monday, November, 23, 1964/Agrahayana 2, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-पाक गृह कार्य मंत्रियों का सम्मेलन

\+

*137. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्रकाश बीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री र० वैंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र बर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत–पाकिस्तान गृह-कार्य मंत्रियों की वार्ता शीघ्र ही होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तानी नेताओं के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सम्मेलन की कार्यसूची में वार्ता का मुख्य विषय भारत में अवैध रूप से आये हुए

पाकिस्तानियों का जिन को वह आसाम से पाकिस्तान में आये हुए भारतीय कहते हैं, प्रत्यावर्तन होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) भारत तथा पाकिस्तान के गृह-कार्य मंत्रियों का एक सम्मेलन 23 से 25 नवम्बर, 1964 तक रावलपिंडी में होना था। तथापि पाकिस्तान सरकार के कहने पर उसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कोई नई तारीख नहीं बताई है।

(ख) भारत सरकार का ध्यान पाकिस्तानी अखबारों में छपे इस तरह के कुछ समाचारों की ओर गया है। आशा थी कि सम्मेलन में चर्चाधीन आने वाले अनेक विषयों में अवैधरूप से आये लोगों का प्रत्यावर्तन भी होगा।

(ग) इस विषय पर भारत सरकार का रवैया पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। किसी भारतीय राष्ट्रजन को निकाला नहीं गया है और न ही निकालने का कोई प्रश्न है। केवल उन्हीं लोगों को जो अवैधरूप से आये हुए प्रमाणित हो जाते हैं, भारतीय कानून के अनुसार यहां से चले जाने को कहा जाता है।

श्री हेम बरुआ : जिस मुख्य उद्देश्य से यह भारत-पाक गृह मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाना था वह था हमारे देश में अवैध रूप से आये पाकिस्तानियों का प्रत्यावर्तन और वह उद्देश्य पूरा हो चुका है क्योंकि हमारी सरकार ने देश के पूर्वी राज्यों से प्रत्यावर्तन का काम बन्द कर दिया है। क्या सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारियों से सुनिश्चित किया है कि क्या वे सम्मेलन में वस्तुतः कोई रुचि रखते हैं या नहीं ? श्री भुट्टू तथा राष्ट्रपति अयूब खां ने ऐसे वक्तव्य दिये हैं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सवाल काफी साफ है। अब माननीय सदस्य यहीं रुक जायें।

श्री स्वर्ण सिंह : सम्मेलन स्थगित हो गया है और हमें इसकी खुशी नहीं है। परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद अच्छा होगा यदि दोनों गृह-मंत्री मिलें और इस प्रश्न पर तथा अनेक दूसरी बातों पर चर्चा करें।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि यदि वे कहें कि केवल इसी विषय पर बातचीत होगी तो क्या सरकार फिर भी सम्मेलन बुलायेगी अथवा सरकार ने उनसे कहा है कि दूसरे विषयों पर भी चर्चा हो।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तो अन्य विषयों पर भी बातचीत होगी।

अध्यक्ष महोदय : जब वे कहें कि केवल इसी विषय पर चर्चा होगी ?

श्री स्वर्ण सिंह: इसका यह अर्थ नहीं कि हम दूसरे विषय उठा ही नहीं सकते। हमारा इरादा अनेक दूसरे विषयों पर भी बातचीत करने का है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत-पाक गृह-कार्य मंत्रियों के प्रस्तावित सम्मेलन का कोई लाभ नहीं होगा और यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रपति अयूब खां से सुनिश्चित किया है कि उनकी इसमें कोई रुचि है या नहीं ? यदि वह समझते हैं कि इसका कोई लाभ नहीं होगा तो सम्मेलन बुलाने और हमारे लोगों के व्यर्थ में रावलपिंडी जाने का क्या फायदा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के अखबारों में छपे जिस भाषण का हवाला दिया है, हमने उसे देखा है और वह वक्तव्य उत्साह बढ़ाने वाला नहीं था क्योंकि दोनों गृह-कार्य मंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत के परिणाम के सफल होने के बारे में एक तरह से सन्देह व्यक्त किया गया था । परन्तु इन सब बाधाओं के बावजूद दो पड़ोसी देशों के बीच मंत्री स्तर पर बातचीत होने के अवसरों की आशा छोड़ नहीं देनी चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । यदि दूसरा पक्ष बातचीत में रुचि ही नहीं रखता--और यह बात राष्ट्रपति अयूब के वक्तव्य से स्पष्ट है--तो क्या सरकार का इरादा एकपक्षीय बातचीत चलाने का है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना रवैया बता दिया है ।

Shri Prakash Vir Shastri : On his way home from the Conference of the Non aligned Nations the Prime Minister had a brief holt at Karachi where he met Gen. Ayub after which he had made this announcement that the Home Ministers of the two countries would discuss matters of mutual interest. May I know whether the Prime Minister had mentioned to Gen. Ayub same subjects for discussion and if so, what was his reaction?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): It is a fact that I met him and talked to him on various matters and he was also of the opinion at that time that Home Ministers meeting would be useful. That was why we had also said that such a meeting should be there. It is not possible that we should discuss there only one subject, the subject which they like. All matters which are important in the opinion of both the parties can be taken up.

Shri Prakash Vir Shastri : I wanted to know the points you had discussed with him. They may be enumerated broadly.

Shri Lal Bahadur Shastri : There was some discussion but that need not be detailed here.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन में मुख्य रूप से जिस विषय पर चर्चा होनी थी वह है युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन ? जब हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कराची में मिले थे तो क्या राष्ट्रपति ने सभी मामलों पर बातचीत करने के लिये अपनी सहमति प्रकट की थी ? यदि हां, तो युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन के प्रश्न पर बातचीत करने से पाकिस्तान सरकार के इन्कार पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और . . . .

अध्यक्ष महोदय : एक ही सवाल में वह इतनी बातें इकट्ठी न कर दें ।

श्री प्र० चं० बरुआ : युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन के प्रश्न पर बातचीत करने से पाकिस्तान के इन्कार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जब एक ही अनुपूरक में बहुत से प्रश्न जोड़ दिये जाते हैं तो मंत्री द्वारा एक ही का उत्तर देना काफी होगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाली घटनायें, विशेषतः पूर्वी पाकिस्तान में, ऐसे मामले हैं जिन से सरकार बहुत चिन्तित है और इन पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मंडलों में बातचीत होनी थी । वस्तुतः इस विषय पर भी चर्चा की तारीख पक्की हो गई थी परन्तु दुर्भाग्यवश उसे भी पाकिस्तान सरकार के कहने पर रद्द कर देना पड़ा ।

डा० रानेन सेन : प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री दोनों ने अभी कहा है कि अवैध रूप से आये लोगों के प्रत्यावर्तन के प्रश्न के इलावा अन्य विषयों पर भी बातचीत होगी । पाकिस्तान सरकार के सामने और किन विषयों का प्रस्ताव रखा गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : एक तो मैंने अभी बताया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई कार्य-सूची तैयार की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं ।

श्री रंगा : उनके चुनाओं तथा अन्य घटनाओं को देखते हुए, जिनमें दंगों में बहुत से लोगों का मारा जाना भी सम्मिलित हैं, क्या यह दोनों सरकारों के हित में नहीं होगा कि इस मीटिंग को जल्दी करने पर दबाव न डाला जाए, चुनावों के समाप्त होने की प्रतीक्षा की जाये और दोनों सरकारों के बीच बातचीत के दरवाजे बन्द न कर दिये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो किसी ने नहीं कहा ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने यह तो नहीं कहा कि बातचीत के दरवाजे बन्द कर देने चाहियें ।

श्री हेम बरुआ : एक व्यवस्था का प्रश्न है । वैदेशिक कार्य मंत्री ने अभी कहा है कि अवैध रूप से आये पाकिस्तानी लोगों को आसाम से निकालने के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य चीजों पर भी बातचीत होगी । अब वह कहते हैं कि कोई कार्य-सूची नहीं है । यह कैसे हो सकता है—एक ही सांस में दो बातें ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दिया है कि जो बातें हम चाहते हैं और जो वह चाहते हैं उन सब पर चर्चा की जायेगी । इसलिये इसमें कोई विरोधाभास नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : परन्तु कार्य-सूची कोई नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली कोई भी बातचीत अन्त में काश्मीर के प्रश्न पर टूट जाती है और यदि हां, तो इस प्रश्न पर कब तक एक अन्तिम, स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रवैया अपना लिया जाएगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य जैसी सुन्दर भाषा का तो प्रयोग नहीं कर सकता परन्तु यह ठीक है कि अन्य बहुत से मतभेदों के परस्पर मान्य समाधान के मार्ग में काश्मीर की समस्या बाधक हो जाती है । इसमें तो कोई सन्देह नहीं है परन्तु प्रश्न केवल हमारे रुख का है तो वह बिल्कुल साफ है । फिर भी हमें आशा है कि मतभेदों को दूर करने का कोई तरीका निकल आयेगा जिससे यह कंटीली समस्या बाधक न हो सके ।

श्री जयपाल सिंह : भाग (ख) के बारे में क्या हम जान सकते हैं कि क्या उन्होंने हमें बताया है कि हमारे कितने लोग अवैध रूप से वहां चले गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान सरकार ने आंकड़े दिये तो हैं, परन्तु कुल मिला कर नहीं; समय समय पर उन्होंने आंकड़े दिये हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिये गये हैं ।

श्री जयपाल सिंह : वर्तमान कुल संख्या क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : वह ज्यादा जरूरी नहीं है । हम केवल उन विषयों की चर्चा कर रहे हैं जो वहां उठाये जायेंगे ।

श्री राम नाथन् चेट्टियार : गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन में संभाव्य विलम्ब को देखते हुए क्या कुछ छोटी छोटी बातों के हल के लिए हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्री का पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य मंत्री से मिलना ठीक न होगा और. . . . .

अध्यक्ष महोदय : हमने गृह-कार्य मंत्रियों की बैठक की बात मान ली हैं । पहले उसे हो जाने दीजिये ।

श्री जं० ब० सिं० विष्ट : क्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति के प्रतिकर का मामला भी सरकार उठायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है । इस प्रश्न को भी उठाने का हमारा इरादा है ।

काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक

+

*138. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में युद्ध-विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने की भारत की मांग को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई है ; और

(ग) इस उपाय से पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन की घटनाओं को कम करने में कहां तक सफलता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या 5 तक बढ़ाना सिद्धान्त रूप में मान लिया है । यह वृद्धि 5 प्रेक्षकों की उस वृद्धि के अतिरिक्त है जो दिसम्बर, 1963–जनवरी 1964 में की गई थी ।

(ख) गत जनवरी से कोई वृद्धि नहीं की गई है क्योंकि सामान्य औपचारिकताओं तथा व्यक्तियों के चयन में कुछ समय लगने की संभावना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या ये संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक वास्तव में कभी सीमा पार पाकिस्तानी हमलों को रोकने में सफल भी हुए हैं या उनका मुख्य काम केवल दोनों देशों की शिकायतें दर्ज करना ही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर सभा में बहुत बार दिया जा चुका है ।

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां । आप ठीक कहते हैं क्योंकि इस विषय को स्पष्ट किया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : कई बार बताया जा चुका है कि उनका काम क्या है, वे करते क्या हैं और अन्त में उसका परिणाम क्या होता है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक सभी अवसरों पर पूरी तरह निरपेक्ष रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमें ऐसी आशा रखनी चाहिए ।

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां । आपका कहना ठीक है । उन से यह आशा रखी जाती है कि इन घटनाओं की जांच करते समय वे निष्पक्ष दृष्टिकोण रखें । उन के लिये यह कठिन काम है और जो वे निर्णय देते हैं या जांच का जो परिणाम निकलता है कभी वह हमें पसन्द नहीं होता और कभी पाकिस्तान को पसन्द नहीं आता ।

श्रीमती सावित्री निगम : संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या बढ़ने के बाद उल्लंघन की घटनायें बढ़ी हैं या कम हुई हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : ये घटनायें कुछ समय से अधिक हो रही हैं परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या तथा युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघनों की संख्या बढ़ने में परस्पर कोई सम्बन्ध है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : यदि हमारे विरोध को केवल दर्ज ही कर लिया जाता है और हमारे देश में ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाये जाते तो संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या को बढ़वाने का क्या लाभ है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात पर कोई वाद-विवाद नहीं करना चाहता । युद्ध-विराम रेखा का अतिक्रमण न हो, यह देखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रेक्षकों को रखना . . . (**अन्तर्बाधायें**) लाभ की बात है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि उनकी संख्या अधिक होगी तो वे अधिक जगहों पर जा सकेंगे, थोड़े प्रेक्षक थोड़ी जगहों पर ही जा सकेंगे ।

Shri R. S. Tiwary : I want to know how many times the observers have decided against Pakistan and how many times against India.

Shri Swaran Singh : I can reply if a separate notice is given.

Shri Yashpal Singh : May we know whether the expenses on the U.N. Observers are borne by the U.N.O. or by the Government of India?

Shri Swaran Singh : I do not have that information. If the hon. Member likes, I can give the information later on.

भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

+
*139. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री विश्व नाथ पांडेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अक्तूबर, 1964 से पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघनों की घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) तथा (ख). 1 अक्तूबर, 1964 के पश्चात्, अपनी पूर्वी सीमा के नज़दीक, दो बार विमानों की आवाज़ सुने जाने की रिपोर्टें मिलीं थीं। अब तक प्राप्य सूचना के अनुसार इन विमानों की गति को वास्तविकता से निर्धारित करना संभव नहीं हो सका। आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं और अधिक विस्तार प्रकट करना लोक-हित में नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या हमारी वायु सेना को हिदायतें दी गई हैं कि जो विमान, सैनिक अथवा असैनिक, हमारी वायु सीमा का उल्लंघन करें उसे गोली मार कर नीचे गिरा दिया जाए।

डा० द० स० राजू : इसके लिये मानी हुई अन्तर्राष्ट्रीय संविदायें हैं; यदि अतिक्रमण करने वाला कोई विमान सैनिक विमान हो तो उसे चेतावनी देने के बाद नीचे गिराया जा सकता है। असैनिक विमानों के लिये कतिपय संविदायें हैं : उन्हें अपने निश्चित मार्गों पर उड़ान करनी होती है अन्यथा वह एक राजनयिक मामला बन जाता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या हमारी सीमा पर गश्त हाल ही में बढ़ा दी गई है या कम कर दी गई है ?

डा० द० स० राजू : वायु सीमा का उल्लंघन बहुत बार नहीं होता; ऐसी घटनायें कभी-कभार होती हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं गश्त के बारे में पूछ रहा हूं; उसे बढ़ाया गया है या घटा दिया गया है। क्या स्थिति है ?

डा० द० स० राजू : मैं नहीं समझता कि उसे बढ़ाया गया हो।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या वायु सीमा का उल्लंघन उस क्षेत्र में हुआ है जहां हमने रडार लगाये हैं ?

डा० द० स० राजू : जी नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : यदि वायु सीमा के उल्लंघन की घटनायें बढ़ रही हैं तो क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र से इस बारे में शिकायत करने का है ?

डा० द० स० राजू : जी नहीं, हम शिकायत करना नहीं चाहते ?

Manufacture of Atom Bomb in India

+

*140. Shri Vishram Prasad :
Shri Bagri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Naval Prabhakar :
Shri Buta Singh :
Shri Solanki :
Shri Gulshan :
Shri Kapur Singh :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Atomic Energy Commission has stated that India could explode an atomic bomb within 18 months, if so desired ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Parliamentary Secretary to the Prime Minister (Shri Lalit Sen):

(a) Yes.

(b) It is the policy of the Government to utilise atomic energy for peaceful purposes only.

Shri Vishram Prasad : I want to know why Government is purchasing submarines, planes, tanks, etc. when it is determined to utilise atomic energy for peaceful purposes only. Why is Government reluctant to make an atom bomb when all other things are being procured ?

Mr. Speaker : You are now arguing the point.

Shri Vishram Prasad : I am not arguing . When we are to utilise atomic energy for peaceful purposes only, what is the point in buying tanks and fighters ?

Mr. Speaker : When the hon. Member thumps his hand so forcefully that shows that he is arguing.

Shri Vishram Prasad : I want to know why Government is reluctant to make the atom bomb.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : There is no question of reluctance. We have a policy of our own and that is not any new policy. We set up the Atomic Energy Commission and thereafter we have been constantly striving to augment atomic energy. It is not essential that it must be meant for destructive purposes. This energy can do much good to the world, to India, to the society and that is why we want to increase it and we shall do so.

Shri Vishram Prasad : May I know whether India would depend upon America or resort to some other means in the event of China using the atom bomb against us ?

Mr. Speaker : It is a hypothetical proposition. You have brought in the question of the policy as a whole.

Shri Bade : The hon. Prime Minister had said in one of his statements that one of the reasons for not producing the atom bomb is that it would mean an expenditure of Rs. 24 crores per bomb. Dr. Bhabha, on the other hand, has said that the expenditure would be to the tune of Rs. 25 lakhs only. Mr. Menon is of the opinion that it would be Rs. 40 crores. Is that the reason for not making an atom bomb?

Shri Lal Bahadur Shastri : It is not correct to give any figures of expenditure in this regard yet. I had also said something and others have also expressed their opinion. Somebody has put it as Rs. 25 crores and others say that it would be Rs. 50 crores. I myself do not know anything in this connection. One cannot say which of these is the final figure. Leaving aside the expenditure on the bomb, much would have to be spent on its project. If you take all these things, the expenditure would be enormous. In view of all these facts, I think it is not possible for anybody to quote the final figures. Something can be said about it only when all the details have been gone into.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The Prime Minister repeats time and again that we shall not produce the atomb bomb . Would it not imperil the security of India and dishearten the people?

Shri Lal Bahadur Shastri : I do not subscribe to this view.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Why ?

श्री कपूर सिंह : हम यह जानने के लिये उत्सुक हैं कि भारत को चीन के आणविक खतरे से वास्तविक तथा प्रभावी ढंग से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाना चाहती है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं नहीं समझता कि इस समय इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। भारत सरकार ...

श्री कपूर सिंह : क्या आपको इस समस्या का ज्ञान है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें पूरा ज्ञान है और यह सोचना सरकार का काम है कि किस समय क्या कदम उठाने चाहिये ।

श्री कपूर सिंह : यह सोचना तो सरकार का काम है परन्तु सरकार क्या सोच रही है क्या यह जानना सदस्यों का विशेषाधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी पूरी चीज को प्रकट न करना सरकार का विशेषाधिकार होता है।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने वह विशेषाधिकार जताया तो नहीं है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बावजूद इस बात के कि अणुशक्ति को शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल करने की हमारी पुरानी नीति है, क्या सरकार ने चीन द्वारा अणुबम के विस्फोट के बाद मंत्रिमंडल स्तर पर उस नीति के बारे में कोई निर्णय किया है जो भविष्य में अपनाई जायेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी, नहीं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : जहां तक अणुशक्ति का सम्बन्ध है, क्या उन लोगों में, जिन से युद्ध छेड़ने की संभावना हो, शक्ति का संतुलन बने रहना विश्वशांति को बनाये रखने में बहुत बड़ा सहायक नहीं होता तथा क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : नीति , मत तथा सुझाव सब को मिला दिया है । श्री भागवत झा आजाद ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार का निर्णय अब भी वही है जबकि इस देश पर चीन जसी अणुशक्ति ने आक्रमण किया है, जब इस देश की प्रभुसत्ता पर आणविक शस्त्रों से लैस विदेशी शक्तियों ने हमला किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं समझ नहीं पाया ।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश न बड़ा सीधा है । मैं जानना चाहता हूं कि जब चीन जैसे देश ने आणविक शस्त्रों के साथ इस देश की प्रभुसत्ता पर हमला किया है, तब भी सरकार का निर्णय वही पहले वाला है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नीति वही है । कोई यह नहीं कह सकता या आश्वासन नहीं दे सकता कि आगे क्या होगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Prime Minister has just now stated that this decision was taken long ago that we would not produce a destructive bomb like the atom bomb ? · Did we not take this decision when China had not made any atom bomb ? Now conditions have changed as a result of the explosion of atom bomb by China. Is the Government of India prepared to reconsider its old decision in the light of these changed circumstances?

Mr. Speaker : You are arguing the case as to why this has not been done. This cannot be done during the question hour. You can mention all these things during the Course of a discussion. We are shortly going to have a debate on external affairs and then you may raise this issue.

Shri Prakash Vir Shastri : I will put my question in another way.

Mr. Speaker : You may wait now.

श्री खाडिलकर : जब हम ने अणु परीक्षण बन्द करने की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, क्या उसका अर्थ यही था कि यदि चीन ने अणुबम का विस्फोट किया तो हम अपने हस्ताक्षर वापिस ले लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह काल्पनिक प्रश्न है । श्री हेम बरुआ ।

श्री हेम बरुआ : क्या प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये अणुशक्ति का विकास न करने का फैसला विशेषज्ञों के जांच आयोग के निष्कर्षों के आधार पर किया गया है या सरकार की अधपकी नैतिकता की कल्पित धारणाओं के आधार पर ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार का कथन है कि यह सरकार की नीति है इतनी जानकारी दे दी गई है । सदस्य अब दलीलें दे कर उस नीति को बदल देना चाहते हैं । उनकी राय में यह नीति ठीक नहीं है और इसे बदलना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri : This policy was framed when China had not produced an atom bomb. Now when she has produced such a bomb, we ought to change this policy.

Mr. Speaker : This is again arguing the case as to what the policy was at that time and what it should be now.

Shri Prakash Vir Shastri : We want to know whether Government has decided to change its policy after China has made an atom bomb.

श्री हेम बरुआ : जहां तक मेरे प्रश्न का सम्बन्ध है, श्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उतना ही पता है जितना मेरे जसे साधारण व्यक्ति को। अतः मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या यह निर्णय विशेषज्ञों के किसी जांच आयोग के निष्कर्षों पर आधारित है ?

अध्यक्ष महोदय : नीतियों का फैसला सरकार ने करना है। यदि उस नीति पर कोई कार्यवाही करनी है तो तब विशेषज्ञों की बात आती है।

श्री कपूर सिंह : श्री हेम बरुआ का प्रश्न बड़ा स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। वह जानना चाहते हैं कि क्या यह निर्णय नैतिक है अथवा राजनैतिक ?

अध्यक्ष महोदय : यह नैतिक फैसला है या राजनैतिक ? क्या सरकार इस पर कुछ कहना चाहती है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसके लिये न तो नैतिक विशेषज्ञों की आवश्यकता है, न वैज्ञानिक विशेषज्ञों की और न ही श्री हेम बरुआ जैसे प्रोफेसरों की। कोई भी कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में केवल सरकार ही निर्णय ले सकती है और वह आवश्मक निर्णय लेगी।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया कि यह नैतिक निर्णय है या राजनैतिक निर्णय है या आपकी नैतिकता पर आधारित है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Office of Pakistan Assistant High Commissioner in Shillong

+
*141. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K.N. Tiwary :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 83 on the 1st June, 1964, and state whether any decision has been taken on the question of closing down the office of the Assistant High Commissioner of Pakistan in Shillong and if so, the particulars thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : At the insistence of the Government of Pakistan, the Assistant High Commission of India at Rajshahi was closed on 14-12-1963. Government of India would be fully justified if only as a matter of reciprocity to ask for the closure of the Assistant High Commission of Pakistan in Shillong.

We are taking up the question of reopening the Rajshahi office again with the Government of Pakistan.

Shri Bibhuti Mishra : May I know on what new grounds our Government wants to negotiate with Pakistan Government when the latter had once closed our office in Rajshahi?

Shri Swaran Singh : We feel that they were not fully justified in closing our office. If another Assistant High Commissioner office is opened at Rajshahi it would be in the mutual interest of both the countries.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that Pakistan's High Commissioner in Shillong indulges in political manoeuvring in many things there? If so, whether Government has decided to close down that office?

Shri Swaran Singh : No such thing has come to our notice in particular. If there is any such complaint, we will go into it and take necessary action.

श्री हिम्मतसिंहका : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि पाकिस्तान का सहायक उच्चायुक्त का यह कार्यालय पाकिस्तानियों को अवैध रूप से आसाम में आने में सहायता करता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक न होगा कि शिलांग में एक सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के होने से लोगों को अवैध रूप से भारत में आने में सुविधा मिलती होगी। विभिन्न स्तरों पर राजनयिक मिशन आपसी सलाह से खोले जाते हैं और उनसे आशा रखी जाती है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अनुरूप परिसीमाओं के अन्तर्गत काम करें।

Shri K.N. Tiwary : Did the Government of Assam report to the Central Government that the office of the Assistant High Commissioner of Pakistan in Shillong is associated with espionage activities and, if so what stands in the way of the Government to close down that office?

Shri Swaran Singh : If there is any apprehension about spying or some material in that connection is available Government would have absolutely no hesitation in closing down that office but before bringing this charge of spying the hon. Member should think out it carefully because this is a very serious charge and unless he can substantiate it, it would not be fair on his part to mention such a thing.

Shri K.N. Tiwary : Is it a fact that the Assam Government had sent a report to the Central Government that this office there was the centre of spying and if so, why is Government reluctant to close it down?

Shri Swaran Singh : The hon. Member has repeated the same question. What am I to reply?

Mr. Speaker : He wants to know whether the Assam Government has sent any report to the Central Government.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : No sir, the Assam Government have recently sent a few complaints to the Government of India but not regarding spying. The Chief Minister of that State had also talked to Pandit ji and to me.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान सरकार ने राजशाही में हमारे सह-उच्चायुक्त के कार्यालय को जबरदस्ती बन्द कर दिया जब कि वहां जनवध हो रहा था, क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि पाकिस्तान को होश में लाने का एक ही तरीका है और वह है शिलांग में उनके मिशन को बन्द कर देना ?

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही के लिए सुझाव है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि राजशाही में सह-उच्चायुक्त के कार्यालय को पुनः खोलने के बारे में कुछ बातचीत चल रही है। वह कार्यालय इसलिये बन्द किया गया था क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया था कि वहां हमारा सह-उच्चायुक्त हिन्दू अल्पसंख्यकों को निकालने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। क्या इस चीज को ध्यान में रख कर वर्तमान बातचीत की जा रही है और इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सभी पहलुओं पर निश्चय ही विचार होगा परन्तु मैं प्रश्न को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। यदि इसे बन्द करने के पाकिस्तान सरकार के पास कोई कारण हैं तो हम समझते हैं कि वे कारण पर्याप्त नहीं थे और मिशन को पुनः खुलवाने के लिए गंभीर प्रयास करने का हमारा इरादा है।

श्री हेम बरूआ : क्या अब सरकार इस बात से प्रभावित हो गई है कि शिलांग में पाकिस्तानी सह-उच्चायुक्त का यह कार्यालय नागा विद्रोहियों के पाकिस्तान जाने तथा वहां से हथियार लाने के लिए जिम्मेदार है। क्या मैं माननीय मंत्री को याद दिला सकता हूं कि श्री नेहरू ने इस सभा में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वे घटना-चक्र को देखेंगे और जरूरी हुआ तो वह शिलांग में उनके कार्यालय को बन्द कर देंगे। क्या सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और उसे इस कार्यालय की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों का विश्वास नहीं हुआ है?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं कहूंगा कि स्थिति को भांपा जा रहा है। सवाल यह है कि एक कार्यालय को बन्द किया जाए या एक और कार्यालय खोलने के लिए कहा जाये। हम यह पसन्द करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान में कार्यालय खोला जाये बजाय इसके कि शिलांग में यह कार्यालय बन्द करने पर जोर दिया जाए। परन्तु यदि शिलांग में सह-उच्चायुक्त की गतिविधियां आपत्ति-जनक हुईं तो हम अवश्य इन्हें रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। कार्यालय को बन्द करने के इलावा इन कार्यवाहियों को रोकने के और भी तरीके हैं। मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखा जाये कि ऐसी स्थिति में हमारा रवैया यह है कि एक और कार्यालय को खुलवाने का प्रयास किया जाये। यदि हम सफल न हुए तो परिणाम बिल्कुल स्पष्ट हैं।

श्री बसुमतारी : पवित्र बाल की चोरी के बाद आसाम में कई राष्ट्र-विरोधी घटनाएं हुई थीं। गृह-कार्य मंत्री आसाम गये थे और कई लोगों ने उन्हें शिलांग स्थित हाई कमिशन की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के बारे में सूचना दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह उन सूचनाओं से सन्तुष्ट हैं और क्या उन्होंने इस बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री को बताया है। आसाम में राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों की जांच के बाद क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को...

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भाषण पन्द्रह मिनट तक जारी रहेगा?

श्री बसुमतारी : मुझे अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से करना है?

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न क लम्बे वक्तव्य के रूप में हो तो उसे समझा कैसे जा सकता है?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रश्न को समझा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो स्वाभाविक ही है। अगला प्रश्न।

अफ्रीकी देशों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध

+

*142. { **श्री यशपाल सिंह :** **डा० मां० श्री अणे :** **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** }

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई नये स्वतन्त्र अफ्रीकी देशों ने, जहां भारत ने अपने कूटनीतिक दूतावास स्थापित कर दिये हैं, अभी तक भारत में अपने दूतावास स्थापित नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इसके कारण पता लगाने की कोशिश की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, सेनेगल, कांगो (लियोपोल्डविल), मलावी, कीनिया, मदागास्कर और सोमालिया ।

(ग) प्रत्येक प्रभुसत्तात्मक राष्ट्र के अधिकार में है कि वह किसी भी विदेश में रांजनयिक मिशन खोले लें । फिर भी, मिशन न खोलने का कारण आमतौर से धन और प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होता है ।

Shri Yashpal Singh : Is it not one of the reasons for those countries not opening their embassies here that they are more under the Chinese influence?

Shri Swaran Singh : I do not agree that they should not set up their embassies here due to the Chinese influence.

Shri Yashpal Singh : Has Government taken some concrete steps so that they should have their embassies here?

Shri Swaran Singh : Concrete steps? I do not know what to reply. It is an international practice that when a country's Government is recognised, both the countries are entitled to open their missions in the other country. It is as essential for them to open their diplomatic missions here as it is for us to have our missions there. They are expected to open their missions here but it is not customary to write again and again to them or make it a grievance.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच नहीं है कि अफ्रीकी देशों का हमारे साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उत्सुक न होने का एक कारण अफ्रीकी देशों में हमारी कूटनीति में एक भूलभूत त्रुटि है अर्थात् वहां पर हमरे कूटनीतिज्ञ अधिक बल सदा चीन-विरोधी प्रचार पर देते हैं और उन विकासोन्मुख देशों की वास्तविक समस्याओं को समझने में वे असफल रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस आरोप को स्वीकर नहीं करता । अफ्रीका में हमारे मिशनों ने अच्छा काम किया है । जिन देशों का इस प्रश्न में उल्लेख है, यदि उन्होंने हमारे देश में अपने मिशन नहीं खोले हैं तो इस तरह का लांछन लगाना गलत होगा ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अफ़्रीकी देशों में ऐसी शिकायतें की गई हैं। उन देशों की सहायता करने की बजाय भारत चीन-विरोधी प्रचार में अधिक लगा रहता है। इस प्रश्न का अफ़्रीका के सभी देशों से सम्बन्ध है।

श्री जोकीम आल्वा : अफ़्रीका में हमारे मिशनों के सर्वोच्च अधिकारियों के बारे में आप जानते हैं कि चीन ने इन पदों पर अपने विदेश कार्यालय के बहुत ही दक्ष व्यक्ति भेजे हैं जिससे उन्हें बड़ा लाभ पहुंचा है। क्या अफ़्रीका में हमारे मिशनों में दक्ष और सक्रिय व्यक्ति भेजने की कोई ठोस नीति है . . .

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

श्री जोकीम आल्वा : और केवल भूतपूर्व आई० सी० एस० व्यक्तियों को भेज कर ही सन्तोष न कर लिया जाये जो केवल नील नदी के किनारे ही रहना चाहते हैं, जो केवल काहिरा ही जाना चाहते हैं, अफ़्रीका के अन्य भागों में नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रयोजन पूरा हो गया है ; उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि भारत सरकार की विदेश नीति के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में अफ़्रीका के कुछ देश आलोचनात्मक प्रवृत्ति रखते हैं अतः उन्होंने भारत में अपने दूतावास स्थापित नहीं किये ?

श्री स्वर्ण सिंह : नहीं यह ठीक नहीं है। पता नहीं ऐसी सब बातें कहां से आती हैं। यह तो सरल सी बात है। बहुत से अफ़्रीकी देशों ने अभी हाल में स्वतन्त्रता प्राप्त की है। हम उनके साथ अधिकाधिक अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहते हैं। हमने उनकी स्वतन्त्रता के लिये लगातार और धैर्य के साथ काम किया है। किन्तु उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं वित्त की दृष्टि से और कर्मचारियों की दृष्टि से भी, ताकि वे भारत में दूतावास खोल सकें। हमें इससे ऐसा मतलब नहीं निकालना चाहिये कि उन देशों की आलोचना की जाये।

श्री पु० र० पटेल : हमने अफ़्रीका के विभिन्न देशों में दूतावास स्थापित किये हैं और फिर भी उन देशों में से अनेक भारतीय निकाल दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे दूतावासों ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिये क्या किया है।

श्री स्वर्ण सिंह : सामान्यतः अफ़्रीका में स्थिति इतनी चिन्ताजनक नहीं है जितनी माननीय सदस्य कहते हैं। वास्तव में अफ़्रीका के विभिन्न देशों में भारतीय भली प्रकार से हैं वे अन्य ऐसे काम भी कर रहे हैं जिनमें मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए दोनों देश रुचि रखते हैं।

Shri Kishan Patnaik : Whether the countries which have their missions in China have not set up missions in India?

Shri Swaran Singh : If the hon. Member gives a notice for that I can collect the information.

Shri Kishan Patnaik : Does not the Minister of External Affairs has this much information?

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि अफ्रीका के इन देशों में भारतीय अच्छी प्रकार हैं । उनका यह इतना बड़ा दावा इस वास्तविकता के प्रति कहां तक अनुकूल है कि अफ्रीका के देशों में नित्य प्रति भारतीयों को घोरतम कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ रहा है और जंजीबार में जो टांगानीका का भाग बन गया है बिल्कुल मामूली कारण से कि भारतीयों ने एक जलूस में भाग नहीं लिया था उन्हें संक्षिप्त आदेश दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति . . .

श्री नाथ पाई : प्रायः उन्हें तथ्यों का पता नहीं होता । मैं यह बताना चाहता हूं कि एक व्यवस्था के प्रश्न के रूप में मैंने वह प्रश्न उठाया था कि पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत की है और मुझे उस समय बताया गया था कि उन्हें तथ्य का पता नहीं और अगले ही दिन सारी दुनिया को उसका पता लग गया था । अतः मुझे प्रश्न को स्पष्ट करना है क्योंकि उन्हें तथ्यों का पता नहीं होता । अतः यह बात एक दावे के अनुकूल कैसे है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे पता है कि जंजीबार में भारत मूलक लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था किन्तु मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न जंजीबार अथवा टांगानीका के बारे में नहीं पूछा गया ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि वित्त के कारण और उपयुक्त प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण ये देश यहां अपने दूतावास नहीं खोल सकते, क्या उन्होंने कोई ऐसी प्रार्थना भेजी है कि कोई अन्य देश उनका प्रतिनिधित्व करे जैसा कि जिन देशों के साथ हमने अपने राजनयिक सम्बंध तोड़ लिए हैं वहां हमारा प्रतिनिधित्व अन्य देश करते हैं ? इससे पैसा बच जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जा चुका है । मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बात इस सरकार को पत्र आदि द्वारा नहीं कहनी है ।

श्री स्वर्ण सिंह : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं । यह पहलकदमी उस देश को करनी है जो राजदूत या राजनयिक सहित पूरा राजदूतावास स्थापित करने की बजाय कोई अन्य प्रबंध करना चाहता हो ।

श्री अन्सार हरवानी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि अलजेरिया और ट्यूनेशिया के स्वतंत्र होने से पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि इस देश में थे ? यदि वे स्वतंत्रता से पहले अपने प्रतिनिधि यहां रख सकते थे तो अब क्यों नहीं ? अब उनके प्रतिनिधि न होने का क्या कारण है ?

श्री स्वर्ण सिंह : उनके स्थान पर मैं उत्तर नहीं दे सकता । मैंने सामान्य बात कही थी । सामान्य कारण यही है ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्यसूची

*143. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से प्रार्थना की है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्य-सूची में एक विषय यह रखा जाये कि वह देश जिनके पास परमाणु हथियार अभी नहीं हैं, उनको बनाने से किस प्रकार रोका जाये ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत सरकार की प्रार्थना पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र की कार्य-सूची में 'अणु अस्त्रों का उत्पादन न करना' विषयक मद सम्मिलित कर लिया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात पर बल देने के लिए तैयार है कि जिन नये राष्ट्रों ने अणुशस्त्र प्राप्त कर लिए हैं उन्हें जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन नहीं लाया जाता तब तक उन्हें पूरे या आंशिक अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के लिए नहीं मनाया जा सकता ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह भी एक तर्क है और मान्य आधार है जिसे ध्यान में रखा जायगा।

श्री भागवत झा आजाद : क्या भारत सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव रखने वाली है कि जिन राष्ट्रों के पास अणु शस्त्र नहीं या जो अणु शस्त्र प्राप्त नहीं करना चाहते उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से गारंटी प्राप्त हो और शक्तिशाली राष्ट्र उन्हें अण्विक आक्रमण से संरक्षण प्रदान करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस समय हमारी कोई योजना नहीं।

श्री हेम बरूआ : चूंकि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं और किसी भी राष्ट्र ने चीन की इस बात की निन्दा नहीं की कि वह विनाश के प्रयोजन के लिए अणु शस्त्र बना रहा है और रूस ने इसे महान घटना कह कर इसका स्वागत किया है ऐसी स्थिति में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय की चर्चा उठा कर क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा का महत्व है क्योंकि यह विश्व शांति की स्थापना के हित में होगा और यदि इस उद्देश्य को स्वीकार कर लिया जाता है कि अणुशस्त्रों का विस्तार नहीं होना चाहिये तो तनाव का फैलाव रुकेगा। चीन के अलावा अन्य भी अनेक देश हैं।

श्री हेम बरूआ : उन्होंने कितना झूठा बहाना प्रस्तुत किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर तो सुनना ही है।

श्री हेम बरूआ : ये मंत्री इस सारे अधिवेशन में ऐसे ही बहाने सुनाते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चाहे वे झूठा बहाना ही समझें उन्हें सुनना तो है ही।

श्री हेम बरूआ : मैंने उन्हें सुन लिया है। वे उत्तर समाप्त कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं।

डा० रानेन सेन : कुछ दिन पहले भारत के प्रधान मंत्री ने एक आम सभा में कहा था कि वे अणु शस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में हैं और भूमिगत, भूमि पर और अन्तरिक्ष में सभी कहीं अणु परीक्षण पर प्रतिबंध चाहते हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य-सूची में यह विषय रखवाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जैसा मेरे साथी ने अभी कहा है यह विषय संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है और इस पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ही उपयुक्त मंच है। जैसा मैंने कहा हमारी आम राय यह है कि इसके लिए आवश्यक जनमत तैयार किया जाए, जिससे लोग . . . .

श्री हेम बरुआ : जिसे आप किसी भी समस्या के संबंध में अभी तक तैयार नहीं कर सके।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : . . अणु शस्त्रों के लिए अणु शक्ति के निर्माण का विरोध करें और मुझे आशा है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर विचार किया गया तो वे इन सब बातों पर और विशेषतः भारत के लिए उपस्थित खतरे पर विचार करेंगे।

2031 (Ai) LSD—2

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा की कार्यसूची में शामिल कर दिया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा से पहले सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिससे सब राष्ट्रों को अणु बम पर पूरा प्रतिबंध का समर्थन करने के लिए तैयार किया जा सके चाहे वह बम चीन बनाये या अन्य देश, पूर्वी या पश्चिमी।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम इस सम्बंध में कुछ कर रहे हैं। हमने कुछ कदम उठाये हैं किन्तु मैं उनकी चर्चा अभी नहीं करना चाहता।

श्री हेम बरूआ : एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री यह प्रश्रय ले सकते हैं कि लोक हित में सभा को यह जानकारी नहीं देना चाहते क्योंकि आपने इसका निर्णय पहले दिया था। किन्तु प्रधान मंत्री यह कहे जा रहे हैं कि वे जानकारी देना नहीं चाहते इसलिए नहीं दे रहे। यह कैसी बात है। उन्होंने 'लोकहित' शब्द का प्रयोग नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझत कि उनका यही अभिप्राय है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं समझता था कि श्री हेम बरुआ तो सभा के योग्यतम सदस्यों में से हैं अतः वे अर्थ को समझ लेंगे। यह स्पष्ट है कि जो जानकारी मैं नहीं दे रहा वह लोकहित के कारण नहीं दे रहा।

श्री हेम बरूआ : मैं तनिक मूर्ख भी हूं . . . .

श्री लाल बहादुर शास्त्री : निस्संदेह मुझे बहुत खेद है।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री ने लोकहित में प्रश्रय मांगा है। किन्तु सभा यह जानने के लिए उत्सुक है। मैं तो जानना चाहता हूं कि चूंकि यह कार्यसूची में शामिल कर दिया गया है अतः अन्य राष्ट्रों की राय तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। प्रधान मंत्री का कथन है कि सरकार के मन में कुछ है जो वे नहीं बताना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सरकार इस दिशा में कुछ कर रही है किन्तु जो कुछ किया है वे नहीं बताना चाहते।

श्री स० मो० बनर्जी : अन्य देश अणु विस्फोट कर रहे हैं और फिर भी हमें नहीं बताया जाता कि क्या किया जा रहा है।

Shri Rameshwaranand: Government of India is against the manufacture of atom bomb. There can be two reasons for that, one is that they are incompetent to manufacture one and second is that they are wise and strong and understand atom bomb should not be used. Which of these reasons is true.

Mr. Speaker : This has been replied.

श्री कपूर सिंह : चूंकि चीन अणु बम बना चुका है, क्या मैं जान सकता हूं कि वह उपाय क्या हो सकता है जिस से अणु बमों का और विस्तार रोकने से भारत के राष्ट्रीय हित की रक्षा होगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि शांति बनाये रखना सारे विश्व के हित में है और भारत के भी हित में है। यदि अणु शस्त्रों का विस्तार न होने से विश्व, विश्व व्यापी युद्ध से बच सकता तो निश्चय ही इस बात में बहुत रुचि है।

अध्यक्ष महोदय : उनका यह मत है कि चीन हमारा निकटतम शत्रु है और उससे हमें सीधा खतरा है। जब उस देश ने अणु बम का विस्फोट कर दिया है . . .

श्री कपूर सिंह : . . . तो हम अपना समय और शक्ति क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : उस स्थिति में भी इस दिशा में प्रयत्न का काम है क्योंकि जिन देशों के पास चीन से कहीं अधिक बम हैं उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि अणु परीक्षण करना और बमों की संख्या बढ़ाना बन्द कर दें ।

श्री कपूर सिंह : क्या प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है ? उन्होंने केवल टाल दिया है । संयुक्त राष्ट्र संघ सभा द्वारा अणु बम का विस्तार रोकने के लिए व्यर्थ के प्रयत्नों से भारत के समान्य राष्ट्रीय हितों को क्या लाभ होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मैं यह विश्लेषण स्वीकार नहीं करता । यह गलत विश्लेषण है ।

श्री कपूर सिंह : यहां विश्लेषण का प्रश्न कहां है ? मैंने तो केवल जानकारी मांगी है कि राष्ट्रीय हित को क्या लाभ होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जब दो सदस्यों में मतभेद हो तो मैं उसे नहीं निबटा सकता ।

श्री नाथ पाई : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि भारत के प्रतिनिधि मंडल या भारत सरकार का यह प्रयत्न होगा कि संयुक्त राष्ट्र की विषय सूची में इस प्रश्न को लिया जाए । क्या हमारा प्रयत्न केवल चर्चा करना ही होगा या हमारा प्रतिनिधि मंडल यह प्रयत्न करेगा कि मास्को संधि के उपबंधों का उल्लंघन करने और विश्व के जनमत की अवहेलना करके अणु परीक्षण करने के लिए चीन की निन्दा की जाए या हमें यह चिंता होगी कि ऐसा करने से हम चीन को नाराज कर लेंगे ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी ऐसी चिंता का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नाथ पाई : सामान्यतः आप चिंतित रहते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सुझाव देना ठीक नहीं है कि इस पर बल न देने का यह कारण हो सकता है चाहे हम अनुभव करें कि इसे पूरा समर्थन मिलेगा या हम दूसरों को किसी कार्यवाही के लिए मना सकते हैं ।

श्री हेम बरुआ : आप क्या सुझाव देने वाले हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा प्रधान मंत्री सभा को बता चुके हैं अन्य देशों की सरकारों से यह अनुरोध करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वे देखें कि चीन के पास अणु बम होने से क्या खतरा है . . .

श्री हेम बरुआ : और चीन की निन्दा करवाने के लिए नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : और इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया जायगा कि सरकार ने जो विचार स्पष्ट रूप में बताया है उसके पक्ष में विभिन्न राष्ट्रों को तैयार किया जाए ।

श्री नाथ पाई : उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं किन्तु मेरे स्पष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : किसी और अवसर पर सही । अगला प्रश्न ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस ओर भी देखा करें ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों के लिए सभी सदस्यों को इस ओर से बुलाया गया है फिर भी वे कहते हैं कि उस ओर नहीं देखा गया । मुझे आश्चर्य होता है, इस पर अनुपूरक, प्रश्न पूछने वाले सभी सदस्य इस ओर के थे ।

श्री रंगा : आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि दूसरी ओर के सदस्य प्रश्न पूछेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु उनकी शिकायत यह थी कि मैं ने विरोधी पक्ष की ओर नहीं देखा।

रूस के नेतृत्व में परिवर्तन

*144. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री शना० चतुर्वेदी :
श्री राम सेवक यादव :
श्रीमती रेणुका राय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री गुलशन :
श्री ह० चं० सोय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ब० कु० दास :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री नम्बियार :
श्री हेम राज :
श्री किशन पटनायक :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी नेतृत्व में परिवर्तन का भारत-रूसी सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार को कूटनीतिक रूप से यह आश्वस्त कर दिया गया है कि रूस के वर्तमान नेता भारत के प्रति अपनी मौजूदा नीति का ही पालन करते रहेंगे ; और

(ग) क्या नयी रूस सरकार भारत को दिये गये राजनीतिक, आर्थिक अथवा सैनिक सभी वचनों को पूरा करेगी ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ग सिंह) : (क) सोवियत नेतृत्व में हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बावजूद सरकार को विश्वास है कि भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता और सहयोग बना रहेगा।

(ख) जी हां । राजनयिक सूत्रों से भारत सरकार को यह आश्वासन दिलाया गया है कि सोवियत संघ की भारत सम्बन्धी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ग) नई सोवियत सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं, उन्हें देखते हुए यह आशा की जाती है कि सोवियत संघ ने भारत से जो वायदे किए हैं, नई सरकार उन्हें पूरा करेगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री चौ० एन० लाई के रूस जाने के बाद जब उसने रूस को चेतावनी दी थी कि कि वे ख्रुश्चेव के बगैर वे ख्रुश्चेववाद को न अपनाएं अर्थात् शांतिपूर्ण अस्तित्व का सिद्धांत न अपनाएं और भारत के प्रति मित्रता का व्यवहार न करें, रूस का रुख बदल गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : नहीं, चीन के प्रधान मंत्री के दौरे के बाद भी भारत के प्रति रूस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस प्रसंग में कि श्री जय प्रकाश नारायण ने यह उत्कट इच्छा प्रकट की है कि उनकी आवाज प्रधान मंत्री और संसद् तक पहुंचनी चाहिये, मैं जान सकता हूं कि उसके इस वक्तव्य के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कि एक के बाद एक भारतीय नेता देश को जो आश्वासन दे रहा है कि रूस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस बात से भारत को भ्रम में डाला जा रहा है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि इसमें से कोई भी यह नहीं सोच सकता कि देश को भ्रम में डाला जाए । रूस के नेताओं ने हमारे मंत्रियों और दूतावास को जो आश्वासन दिये हैं और खुले आम जो कुछ कहा है उससे हमने यह अनुमान लगाया है । मैं समझता हूं कि हमारे लिए उनके दृष्टिकोण के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना जो हमारे मित्र रहे हैं, उचित नहीं है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या रूस के नेतृत्व में परिवर्तन के बाद हमारी सरकार ने रूस की सरकार से निश्चित आश्वासन मांगा है कि वे भारत को शस्त्रास्त्र और सैनिक सहायता देते रहेंगे या रूस के नेताओं ने हमारे राजदूत को और वहां जाने वाले मंत्रियों को जो आम आश्वासन दिया है, हम उसी पर निर्भर कर रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : दो सरकारों के बीच मंत्री स्तर पर जो आश्वासन लिये या दिये जाते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें मामूली नहीं समझना चाहिये और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ऊंचे स्तर पर दिये गये आश्वासनों के सम्बन्ध में ऐसी बात कहना ठीक नहीं है । जैसा मैंने बताया हमें यह आश्वासन दिया गया है कि आर्थिक क्षेत्र में या सैनिक सामान के सम्भरण के मामले में उनके जो वचन हैं उन्हें पूरा किया जाएगा ।

श्री रंगा : इस उत्तर से जो प्रश्न उत्पन्न होता है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू को चीन के प्रधान मंत्री श्री चौ० एन० लाई ने जो आश्वासन दिये थे उनको क्या हुआ था । इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि जहां तक सम्भव हो--मैं सावधानी के भाव से कह रहा हूं--इन आश्वासनों को लिखित रूप दिया जाए ताकि हम अधिक स्थिर आधार पर खड़े हो सकें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा क्या यह सम्भव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि आर्थिक सहायता के बारे में और सैनिक सामान के संम्भरण के बारे में मूल करार लिखित रूप में है । वे पक्के दस्तावेज हैं, अंतः यह सामान्य धारणा है करार करने वाले पक्ष ऐसे करारों का पालन करेंगे । यदि उसके अलावा उच्चतम स्तर पर यह आश्वासन दिया गया है कि किसी करार को वापस नहीं किया जायगा या रद्द नहीं किया जायगा तो मैं समझता हूं कि यह काफी है और उसके बावजूद और लिखित करार करना अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पीकिंग में विज्ञान सम्बन्धी गोष्ठी

*136. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कजरोलकर :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चीन के साथ विज्ञान में सहयोग करने से इन्कार कर दिया है और विज्ञान संबंधी पीकिंग गोष्ठी में भाग लेने का निमंत्रण ठुकरा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). 29 अप्रैल, 1964 को नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक कार्यकर्ता संघ (ऐसोसियेशन आफ सांइटिफिक वर्क्स आफ इंडिया) को निमंत्रण दिया था कि वह पीकिंग में अगस्त 1964 में होने वाली विज्ञान गोष्ठी में भाग लेने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों को भेजें। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने 4 मई को चीनी राजदूतावास को लिखा कि "इस बात को देखते हुए कि चीनी सेनाओं ने भारतीय प्रदेश पर कब्जा कर रखा है और चीन भारत की प्रादेशिक अखण्डता का निरन्तर उल्लंघन कर रहा है, भारत के किसी भी प्रतिनिधि के लिये 1964 की पीकिंग गोष्ठी में भाग लेना संभव न होगा। भारतीय वैज्ञानिक कार्यकर्ता संघ ने भी चीनी राजदूतावास को लिख कर पीकिंग गोष्ठी में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। इस के बाद के एक पत्र में चीनी राजदूतावास को लिख दिया गया था कि "भारत की सरकार और जनता परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के हिमायती हैं और वह चीन के साथ 'वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान' की बात तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह युद्ध जैसे उद्देश्यों के लिए परमाणु-शक्ति के प्रयोग का खुले तौर पर पक्ष लेता है ।"

राष्ट्रीय रक्षा-कोष की लापता रसीद बुकें

***145. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या दिल्ली में महापौर परिषद् द्वारा राष्ट्रीय रक्षा-कोष के लिये धन जमा करने की 80 लापता रसीद बुकों के प्रश्न को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया है;

(ख). यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया; और

(ग). देश भर में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन एकत्रित करने के लिये दी गई ऐसी कितनी रसीद बुकों का अभी तक हिसाब नहीं मिला है ?

प्रधान मंत्री और अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). मेयर की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्, दिल्ली, द्वारा जारी की गई 2610 रसीदी किताबों में से अंतिम तौर पर सिर्फ 107 रसीदी किताबें ऐसी हैं जो लापता हैं अथवा शेष हैं। समाचार-पत्रों में सूचना और आपत्ति की मांग के विज्ञापन निकाल देने के बाद मेयर की परिषद् ने फैसला किया कि इस मामले को समाप्त समझा जाय। फिर भी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि की कार्यकारी समिति ही अपनी अगली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

(ग) दिसम्बर, 1963 में सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि के निमित्त धन जमा कराने के लिए जो रसीदी किताबें जारी की गई थीं, वे वापस ले ली जायें और सम्बद्ध खातों का परीक्षण करा लिया जाय। वे इस संबंध में पहले ही आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन चूंकि विभिन्न स्तरों पर ताल्लुके के स्तर तक धन जमा किया गया था, इसलिए तमाम देश भर में रसीदी किताबों की स्थिति का पता लगाने में कुछ समय लगेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाना

*146. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया ने प्रस्ताव पेश किया है कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा के आगामी अधिवेशन की कार्य सूची में चीन के जनवादी गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के विषय को शामिल किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यदि आम समिति (जनरल कमेटी) ने इस मद पर स्वीकृति दे दी, तो इस पर विचार कर लिया जाएगा और उस के बाद महासभा के प्रारम्भिक सत्र में इस पर विचार होगा। जब यह मामला बहस के लिए आएगा, तब भारत सरकार अपने विचार व्यक्त करेगी।

पुर्तगाल सरकार द्वारा परिचालित नोट

*147. **श्री उमानाथ :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री ब० कु० दास :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अक्तूबर में संयुक्त राष्ट्र संघ में पुर्तगाल के प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् के सदस्यों में भारत के विरुद्ध एक शिकायत परिचालित की थी जिसमें गोआ निवासियों पर अत्याचार करने का अभियोग भारत पर लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). पुर्तगाल सरकार ने सुरक्षा परिषद् के प्रधान को एक पत्र लिखा था जिसके साथ सुरक्षा परिषद् के सदस्यों के पास भेजने के लिए एक नोट था ; इस में यह आरोप लगाया गया था कि गोआ में धार्मिक स्वतन्त्रता का दमन हो रहा है और लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है । भारत सरकार ने भी सुरक्षा परिषद् के प्रधान को पत्र लिखा जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के पास भेजा गया था । भारत के उत्तर में यह कहा गया था कि अंगोला, मोजम्बीक और अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों में लोगों का बर्बरतापूर्ण दमन करने के लिए पुर्तगाल दोषी है और उसे अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिये । पुर्तगाल के पत्र और भारत के उत्तर की प्रतियां सदन का मेज पर रख दी गई हैं । [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये एल० टी० 3421/64]

औद्योगिक संधि संकल्प

*148. श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कार्मिक संघ केन्द्रों ने औद्योगिक संधि संकल्प को मानने से इन्कार कर दिया है;

(ख) सन्धि संकल्प न मानने वाले संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक सन्धि संकल्प पर पुनर्विचार करने का है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) किसी केन्द्रीय मजदूर यूनियन संगठन या उससे सम्बद्ध यूनियन ने औद्योगिक संधि संकल्प को मानने से इन्कार नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

संयुक्तराष्ट्र महासभा का अधिवेशन

*149. डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अफ्रीकी एशियाई तथा लैटिन-अमरीकी देशों ने संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों से प्रार्थना की है कि महा सभा के आगामी अधिवेशन को स्थगित किया जाये;

(ख) इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). कुछ अफ्रीकी एशियाई देशों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अनुरोध किया था कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अक्तूबर में काहिरा में गुटों से अलग देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों का दूसरा सम्मेलन हो रहा है, महा सभा का

आगामी अधिवेशन नवम्बर की किसी उपयुक्त तारीख तक के लिये स्थगित कर दिया जाए। इस के बाद, कुछ अफ्रीको-एशियाई और लातीनी अमरीकी देशों ने महा सचिव से इसे पहली दिसम्बर तक के लिए स्थगित कर देने की प्रार्थना की, क्योंकि उन के विचार से ऐसा करना इस संगठन के बहुत हित में होगा और इस से सदस्य राज्य महा सभा के काम में निश्चित रूप से अधिक सृजनात्मक सहयोग दे सकेंगे ।

(ग) अधिवेशन को स्थगित करने के लिए पहली बार जो प्रार्थना की गई थी उस पर औरों के साथ भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किए थे । उसने दूसरी प्रार्थना का भी समर्थन किया था ।

मूल्य देशनांक

*150. डा० सारादीश राय :
श्री दिनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में श्रमिक निर्वाह व्यय देशनांकों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है कि इस वृद्धि के अनुसार श्रमिकों को उचित राहत तथा मुआवजा मिले ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 1949=100 के आधार पर पिछले तीन महीनों के अखिल भारतीय (अन्तरिम) श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे दर्शाये गये हैं :—

जुलाई 1964—154
अगस्त 1964—156
सितम्बर 1964—159

(ख) मंहगाई भत्ते का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से समंजन के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी :

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय पहले ही मंहगाई भत्ते पर पुनर्विचार कर रहा है ।

औद्योगिक कामगर :

उन उद्योगों और केन्द्रों में जहां मंहगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाता है, कामगरों को स्वतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलता है। और सहायता के रूप में सरकार उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, जिनमें 300 और उससे अधिक कामगर काम करते हों, उचित मूल्य की दुकानें और उपभोक्ता भण्डार स्थापित करने के लिये कानून बनाने का विचार कर रही है ।

प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा उत्पादन

*151. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा प्रतिरक्षा उत्पादन के फलस्वरूप किये गये आविष्कारों तथा अन्य सफलताओं को, प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल करने के अतिरिक्त फार्मों तथा फैक्टरियों में जहां भी ऐसी अनुमति है असैनिक आवश्यकताओं के लिये भी उपलब्ध किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये क्या पद्धति तथा एजेंसी अपनाई गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां, यद्यपि प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास और उत्पादन प्रयास प्रतिरक्षा सेवाओं की अवश्यकताएं जुटाने के लिए अभिस्थापित किया जाता है, ऐसे आविष्कार और परिणाम जनता के लाभ के लिए प्राप्य कर दिए जाते हैं, जिन का असैनिक खपत के लिये लाभ सहित प्रयोग किया जा सकता है ।

(ख) प्रक्रिया ऐसी है, कि प्रतिरक्षा अनुसन्धान और विकास संस्था के आविष्कारों में से जो वर्गीकृत किस्म के नहीं होते, उन के पेटेण्ट लेकर, राष्ट्रीय अनुसन्धान तथा विकास निगम के लिए विमुक्त कर दिये जाते हैं कि असैनिक क्षेत्र उस से लाभ उठा सकें ।

टेलीविजन

*152. **श्री पं० वेंकटासुब्बया :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सेझियान :
श्री धर्मलिंगम :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में टेलीविज़न का जाल बिछाने के बारे में कुछ ब्रिटिश टेलीविज़न कम्पनियों ने एक योजना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ब्रिटिश और गैर-ब्रिटिश कम्पनियों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) भारत में टेलीविज़न सेवाओं के विस्तार का सारा प्रश्न अभी विचाराधीन है । इसलिये इस अवस्था में न तो योजनाएं जो हमें मिली हैं, उनकी मुख्य बातें और न ही उनके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया प्रकट की जा सकती हैं ।

केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्था

*154. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० द० पुरी :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री रामपुरे :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रोजगार सेवा में अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण के लिए एक संस्था स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य-क्षेत्र तथा स्थापना उद्देश्यों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) यह संस्था अक्टूबर, 1964 से चालू हो गई है ।

(ख) इसका कार्य-क्षेत्र द्विमुखी है ।

(1) रोजगार अधिकारियों के लिए रोजगार कार्यालयों की कार्यपद्धति और तकनीक समझाने का लगातार प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम चलाना ।

(2) रोजगार सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम जैसे रोजगार कार्यालयों की कार्यपद्धति में सुधार, व्यावसायिक मार्ग दर्शन, व्यावसायिक अनुसंधान, रोजगार के अवसरों की जानकारी इकट्ठा करना, चुने हुए उम्मीदवारों और रिक्त स्थानों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था, से सम्बधित मामलों का अध्ययन और अनुसंधान करना ।

स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा की शर्तें

*155. श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों को सेवा की अच्छी शर्तें देने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाहियों की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जा रहा है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3422/64]

विमान दुर्घटना

*156. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 14 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति का इस बीच प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति पटल पर रख दी जायेगी तथा क्या सरकार ने उस में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) समिति ने अपनी रिपोर्ट संपूर्ण करली है, और वह अभी ही सरकार को समर्पित की गई है ।

(ख) सरकार यह फैसला रिपोर्ट के निरीक्षण के पश्चात् करेगी ।

नए आयुध कारखाने

*157. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकर लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री हेम राज :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 के चीनी आक्रमण के पश्चात् नए आयुध कारखाने स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक कारखाने को स्थापित करने में विदेशों से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त हुई है और किन-किन देशों से यह सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ग) सभी प्रस्तावित आयुध कारखाने कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) : आपात घोषणा के पश्चात्, सरकार ने देश में 6 नये आयुध कारखाने स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। उन कारखानों के सम्बन्ध में प्रगति तथा अन्य विस्तार इस प्रकार हैं :—

वरंगांव में आयुध कारखाना

कारखाने ने 15 अक्तूबर, 1964 से उत्पादन शुरू कर दिया है। इस कारखाने के लिए, अधिकतर संयंत्र और मशीनें, अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई हैं।

अम्बाफरी का इंजीनियरी कारखाना

असैनिक इमारतें खड़ी करने का काम प्रगतिशील है। इस कारखाने के लिए अमरीकी सैनिक ऋण-क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत, संयंत्र और मशीनों की सप्लाई के सम्बन्ध में, भारत सरकार और अमरीकी सरकार में बातचीत हुई है। अमरीकी सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाली, परामर्श-दाता फर्म द्वारा, शीघ्र ही इंजीनियरी अध्ययन किया जाएगा। इस अध्ययन के पश्चात्, प्रायोजना आगे प्रगतिशील होगी।

चाण्डा का पूरक कारखाना

असैनिक इमारतें खड़ी करने का कार्य हो रहा है। इस कारखाने के लिए आवश्यक संयन्त्र तथा मशीनें जुटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। यू० के० सरकार ने तकनीकी सहायता देना, तथा इस कारखाने पर व्यय होने वाली राशि का कुछ भाग भी देना स्वीकार कर लिया है।

तिरूचिरापल्ली में छोटे हथियारों का कारखाना

इस कारखाने के लिए संयंत्र तथा मशीनें जुटाने के लिए इण्डेण्ट भेज दिये गये हैं। असैनिक इमारतें खड़ी करने का काम हो रहा है। इस कारखाने के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं ली जा रही, और आशा है कि 1966-67 में निर्माणकार्य आरंभ हो जाएगा।

बुरला में भारी विस्फोटक कारखाना और पान्वेल में प्रणोदक कारखाना

जैसेकि सभा में 20 नवम्बर, 1964 को दिए गये वक्तव्य में कहा गया है, फिल्हाल सरकार ने इन दोनों कारखानों की स्थापना न करने का फैसला किया है।

सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध

*158. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच विवाद के कारणों के बारे में, समुचित सर्वेक्षण किया है, क्योंकि विवाद के फलस्वरूप सार्वजनिक धन का भारी अपव्यय हो रहा है ;

(ख) क्या सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में सरकार ठोस नीति बना सकी है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में स्वस्थ कार्मिक संघ गतिविधियों को बढ़ावा देने और समुचित रूप से उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों का व्यक्ति अध्ययन किया है।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति यह है कि श्रम कानून सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूर्णतः लागू किये जाने चाहियें और इस सम्बन्ध में निजी तथा सरकारी क्षेत्र में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिये।

(ग) भारतीय मज़दूर यूनियन अधिनियम, 1926 और संबंधित राज्य-अधिनियमों के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं और अनुशासन संहिता में मान्यता के लिए व्यवस्था के अलावा सरकार ने कामगर शिक्षा योजना चालू की है, जिसके अन्तर्गत कामगरों को मज़दूर संघ पद्धति तथा उद्योग के बारे में अन्य सम्बन्द्ध मामलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिससे स्वावलम्बन और स्वस्थ, सुदृढ़ एवं प्रबुद्ध मज़दूर युनियन आंदोलन के विचार को बढ़ावा मिले।

कमाण्डरों की बैठक

*159. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काश्मीर की युद्धविराम रेखा पर वर्तमान तनाव को समाप्त करने के लिए कमाण्डरों के स्तर की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव पाकिस्तान सरकार को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया था तथा यदि हां, तो इसके लिये क्या कारण बताये गये हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं। सैनिक कमाण्डरों के स्तर की बैठक का सुझाव, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सैनिक प्रेक्षक के मस्तिष्क की उपज थी, जिसने कुछ मास हुए भारत और पाकिस्तान दोनों को इस बारे में लिखा था। हमने इस सुझाव को झट ही मान लिया था। सच पूछिये, सो तनाव को कम करने के लिए, और युद्धविराम रेखा पर घटनाओं को कम करने के लिए, हम स्वयं मुख्य सैनिक प्रेक्षक पर ज़ोर देते रहे हैं, कि वह अपने असर रसूख से शीघ्र ही प्रस्तावित बैठक की व्यवस्था करे।

(ख) हमें जान पड़ता है, कि अभी तक मुख्य सैनिक प्रेक्षक का पाकिस्तान से कोई उत्तर नहीं मिला।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

थुम्बा का राकेट छोड़ने का स्टेशन

*160. **श्री हेम बरुआ :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुवा :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रधान मंत्री 7 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र बाह्य अन्तरिक्ष समिति की वैज्ञानिक तथा तकनीकी समिति की सिफारिश के अनुसार थुम्बा के राकेट छोड़ने के स्टेशन को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन देने के बारे में निणय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). संयुक्त राष्ट्र महा सभा अपने आगामी अधिवेशन में इस सिफारिश पर विचार करेगी।

बर्मा में भारतीयों की आस्तियां

*161. { **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से अब तक लौटने वाले भारतीयों ने अनुमानतः कुल कितनी आस्तियां वहां पर छोड़ी हैं और इस में अचल सम्पत्ति कितनी है;

(ख) क्या ऐसे भारत लौटने वालों से उन की आस्तियों के प्रत्यावर्तन के दावों के लिये आवेदनपत्र मांगे गये हैं, यदि हां, तो कुल दावे कितनी रकम के हैं; और

(ग) इन आस्तियों के प्रत्यावर्तन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बर्मा में भारतीयों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का ठीक अनुमान बताना सम्भव नहीं है। यह समझा जाता है कि अधिकांश भारतीय राष्ट्रजनों के वहां से रवाना होने से पहले राजदूतावास को अपनी सम्पत्ति के विवरण दे दिये थे।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) बर्मा सरकार के साथ इस सम्पत्ति को भारत लाने के प्रश्न पर बातचीत की जा रही है। इस बारे में शीघ्र निर्णय के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है।

पाकिस्तान द्वारा अमरीकी शस्त्रों का प्रयोग

*162. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री महानन्द :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अमरीकी शस्त्रों का प्रयोग युद्ध-विराम रेखा पर काफी समय से करता रहा है और क्या इस आशय के प्रमाण उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई या की जाने वाली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राजनयिक साधनों से कार्यवाही की जा रही है।

वाह्य अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय करार

318. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने यह मांग की है कि वाह्य अन्तरिक्ष में छोड़ी गयी वस्तुओं से हुई क्षति का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए राष्ट्र संघ एक अन्तर्राष्ट्रीय करार का प्रारूप तैयार करे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). महासभा के संकल्प 1963 (xviii) अनुसरण में वाह्य अन्तरिक्ष के लाभप्रद प्रयोग सम्बन्धी राष्ट्र संघ की कानून उप-समिति इस मामले पर करार का प्रारूप तैयार करने का काम कर रही हैं। भारत उन देशों में से एक था, जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया था और भारत ने इसके पक्ष में वोट भी दिया था। भारत इस कानूनी उप-समिति का भी सदस्य है और जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं उनके सम्बन्ध में भारत ने कुछ सुझाव भी दिये हैं। समिति इस मामले पर अभी विचार कर रही है।

आकाशवाणी का पुनर्गठन

319. **श्री उटिया : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आकाशावणी के पुर्गठन के सम्बन्ध में राय देने के लिए सरकार ने कोई विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये हैं;

(ख) क्या उन विदेशी विशेषज्ञों ने अपना काम शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो वे अपनी रिपोर्ट सरकार को कब देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). आकाशवाणी सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों (media units) के कार्य की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की जा रही है। यह समिति विदेशी या भारतीय विशेषज्ञों की सेवायें आवश्यकतानुसार परामर्शदाता के रूप में जन संचार के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में लेगी। आशा है कि यह समिति 6 महीने के भीतर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे देगी।

काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर हुई मृत्यु

320. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हेम बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1964 में काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर मरे व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, पाकिस्तान ने उसका खण्डन किया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान का कथन कहां तक सही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सरकार ने पाकिस्तान के अखबारों में प्रकाशित इस आशय का समाचार पढ़ा है।

(ख) पाकिस्तान ने मरे हुए व्यक्तियों की संख्या तोड़ मरोड़ कर बताई है। 28 सितम्बर, 1964 को सभा में दी गई जानकारी सही है।

1031 (ai) LSD—3.

Telephone Exchange

321. Shri M.L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S.C. Samant :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether Government have formulated any scheme to make such of the Telephone exchanges automatic where power has been made available after these exchanges were set up or was available even before ;

(b) if so, when it will be implemented ; and

(c) whether Government propose to give telephone connections in the rural areas at concessional rate ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagwati) : (a) Adequate supply of power is an essential condition for setting up an automatic telephone exchange at any place. The question of setting up automatic telephone exchange, however, depends on certain other factors such as availability of equipment and suitable building for putting up the equipment, etc.

(b) The General scheme for setting up automatic telephone exchange has been referred to in the Third Five Year Plan of the Post and Telegraph Department. The general policy of the Post and Telegraph Department is to make the whole net-work of telephones as automatic telephones gradually, although it is likely to take sufficient time.

(c) The rates for the telephone connections being given by such of the Telephone exchanges having a capacity of three hundred or less lines situated in the small towns and rural areas, are already fixed on the concessional rates in comparison to the connections being given by huge telephone exchanges.

Post and Telegraph Offices in Hindi Speaking Areas

322. Shri Vishram Prasad :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of such posts and telegraph offices in Hindi Speaking areas wherein noting on the files can be done in Hindi according to the instructions of the Ministry of Home Affairs ; and

(b) the number of such of the posts and Telgraph offices to which permission for this has not been given and when such permission will be given ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagwati) :

(a) 10 (Ten).

(b) None, the question does not arise.

Hindi Typewriters

323. { **Shri Vishram Prasad:**
Shri Bagri:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Posts and Telegraph circles, Divisional offices and Head Post Offices situated in Hindi Speaking States where Hindi typewriters have been obtained and

(b) the number of such of the above mentioned offices where Hindi typewriters have not been made available and the arrangements being made to make them available?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagwati): (a) 111.

(b) 126. Out of these for 76 offices indents have been sent for supply of typewriters.

अमरीका से राडार सेट

324. { **श्री यु० सिं० चौधरी:**
श्री प्र० चं० बरुआ:
महाराजकुमार विजय आनन्द:

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष संयुक्त हवाई अभ्यास के लिए जो अस्थायी राडार सेट लगाये गये थे उनके स्थान पर अमरीका ने जो स्थायी राडार सेट देने का वायदा किया था क्या वे राडार सेट आ गये हैं;

(ख) यदि उत्तर नकारात्मक है, तो कब आयेंगे?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) अमरीका सहायता कार्यक्रम के अधीन अमरीका से राडार उपकरण प्राप्त हो गये हैं। 1965 के उत्तरार्द्ध में यह उपकरण चालू कर दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल में संसार प्रणाली में सहायता देने के लिए भारतीय प्रविधिक

325. { **श्री विभूति मिश्र:**
श्री क० ना० तिवारी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दूर-संचार प्रणाली को आरम्भ में चलाने के लिए भारतीय प्रविधिक नेपाल की सहायता करेंगे और नेपाल की ओर से लेखे रखने का काम भी करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जो करार किया गया है, उसकी मोटी रूपरेखा क्या है?

संचार विभाग में उपमंत्री श्री भगवती): (क) जी हां, भारतीय प्रविधिक इण्डियन एड मिशन में डेपुटेशन पर काठमण्डू जाकर काम करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय तार तथा टेलीफोन नियमों के अन्तर्गत सामान्य दृष्टि से यह भारत का ही उत्तरदायित्व है, क्योंकि यह मध्यवर्ती राज्य है, कि नेपाल से आरम्भ होने वाले सचारों के अलावा अन्य सब संचारों का लेखा रखे। परन्तु नेपाल के राजा की सरकार के कहने पर भारत सरकार सब प्रकार के संचारों—वहां समाप्त होने वाले और वहां से होकर जाने वाले—का लेखा दो वर्ष तक रखने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) नेपाल के राजा की सरकार और भारत सरकार के बीच हुए दूर-संचार करार के अनुच्छेद iv के खण्ड 2(ख) और अनुच्छेद Vi के खण्ड 1, 2 और 3 (ख) के उद्धरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3427/64]

Export to Tibet via Nepal

326. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K.N. Tiwary:
Shri S.N. Chaturvedi:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that iron, cement, Petrol, kerosene oil, torches and other essential commodities are exported to tibet via Nepal ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swarn Singh): (a) These commodities are not exported to Tibet but it is rumoured that the commodities exported to Nepal for consumption in that country somehow reach on that side of border in Tibet.

(b) H.M. Government of Nepal, on the request of Government of India has, by issuing notifications, banned the export of iron, cement, petrol, kerosene oil, torches and other essential commodities to Tibet or other places. These things are exported to Tibet for consumption in that country.

चीनी आरोप

327. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री प्र० चं० बरुआ:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 सितम्बर, 1964 को पेकिंग में भारत के कार्यवाहक राजदूत को चीन की सरकार ने एक नोट (टिप्पण) दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि 12 और 14 अगस्त, 1964 को भारतीय सेनायें सिक्किम सीमा को पार करके तिब्बत में घुस गई थीं और उन्होंने नाथूला दर्रे के दक्षिण-पूर्व के उस पार तिब्बती क्षेत्र में आक्रमण के लिए 18 सैनिक ढांचे बनाये; और

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और क्या उत्तर भेजा गया ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) 28 सितम्बर, 1964 का चीन सरकार का नोट, जिसमें सिक्किम की सीमा पार करके भारतीय सैनिकों के तिब्बत में घुसने का आरोप लगाया गया है, बिल्कुल निराधार है और भारत सरकार के 6 नवम्बर, 1964 के नोट में उसका उत्तर दे दिया गया है। दोनों नोटों की

एक-एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल०टी० 3423/64] चीन सरकार का 28 सितम्बर, 1964 वाला नोट और उसके उत्तर में भारत सरकार का 8 नवम्बर, 1964 वाला नोट दोनों 8 नवम्बर, 1964 को भारतीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं ।

नौसना के विमान तथा अनधिकृत प्रयोग

328. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ब्रजराज सिंह—कोटा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 28 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना के एक विमान को एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा मद्रास से उड़ा कर ले जाने, जिससे विमान की हानि हुई, की दुर्घटना की जांच करने वाले बोर्ड की कार्यवाही का परीक्षण सरकार ने कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई या की जाने वाली है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) नौसेना के उस अनधिकृत नाविक पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और उसे दो वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया; वह जेल में दूसरी श्रेणी में रखा जायेगा; नौसेना की नौकरी से उसे हटा दिया गया और अन्य आनुषंगिक जुर्माने भी उसे भुगतने होंगे ।

ऐसी घटनायें आगे न होने पायें, इस दृष्टि से उपयुक्त उपाय कर दिये गये हैं ।

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन

329. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तरों में बेरोजगार व्यक्तियों को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए हाल में जो उपाय अपनाये गये थे, क्या वे संतोषजनक ढंग से चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां तक सफल रहे हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) बेरोजगार व्यक्तियों तथा श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले नये व्यक्तियों को अच्छा मार्गदर्शन देने के उपाय अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री फ़िज़ो

330. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा नेता मि० फिज़ो पूर्वी पाकिस्तान से नागा विद्रोहियों का मार्ग दर्शन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ बात की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अखबारों में हम ने इस आशय की खबरें देखी हैं : परन्तु इन खबरों की पुष्टि करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Unemployment in Suburban Areas

331. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Planning Commission have issued instruction to the National Sample Survey department of the Central Statistical Organisation that they should undertake a comprehensive survey of unemployment in the suburban areas with the assistance of the Labour and Employment Directorate ;

(b) if so, when this survey is likely to be completed ; and

(c) the nature of information being collected in this regard ?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) the National Sample Survey Department propose to undertake a survey ;

(b) By the end of December 1965.

(c) It is proposed to collect information pertaining to the number of persons employed and unemployed, their age, sex and their names entered into the current registers of the Employment Exchanges.

Workers in the Ordnance Factories

332. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether Government are making provision to make cheap and hot mid-day meals available to the workers in the Ordnance factories;

(b) if so, the number of ordnance factories wherein it has been introduced; and

(c) the cost of mid-day meals fixed in various factories ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) : (a) Under the provisions of the Factories Act Government opens canteens in the Ordnance factories ; these canteens distribute hot meals ;

(b) 23 such canteens ;

(c) It varies from 37 Paise to 56 paise depending upon the items demanded.

Wage Board for Steel Industry

333. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state as to when the Central Wage Board on the Iron and Steel Industry will submit its report ?

The Minister of Labour and Employment (**Shri D. Sanjivayya**) : The Board is trying to complete its work as early as possible, but it is not possible to say when the Board will submit its report.

विदेश में नौकरी के लिए वाउचर

344. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963–64 में कितने भारतियों को कनाडा, आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सरकारों ने नौकरी के वाउचर दिये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 30-3-1963 से 27-3-1964 की अवधि के दौरान ब्रिटेन की सरकार ने 8912 नौकरी वाउचर भारतियों को दिये। कनाडा और आस्ट्रेलिया की सरकारें नौकरी के वाउचर नहीं देती, अतः इन सरकारों ने भारतियों को कोई वाउचर नहीं दिये।

Employment Exchanges in Punjab

335. { **Shri Daljit Singh :**
Shri Sadhu Ram :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) The number of employment exchanges functioning in Panjab ;

(b) the number of persons registered under various categories in these exchanges ; and

(c) the number of persons for whom employment was secured during the last one year ?

The Minister of Labour and Employment (**Shri D. Sanjivayya**) : (a) to (c).

Number of Employment exchanges functioning as on the 30th Sept. 1964	Number of Candidates as registered in the current registers of these Exchanges on the 30th Sept. 1964	Number of persons who secured employment with the help of Employment Exchanges between the period from the 31st oct. 1963 to 30th Sept. 1964
1	2	3
32	1,08,001	60,064

श्रम संगठन

336. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के संघ ने सरकार से मांग की है कि वह श्रम संगठनों की एकाधिकार-वादी परिपाटियों पर रोक लगायें ;

(ख) सरकार कहां तक आवश्यक समझती है कि संगठित श्रमिकों की गतिविधियों और एकाधिकारवादी पूंजी की गतिविधियों को, जिसकी छानबीन एकाधिकार जांच आयोग ने की है, समान स्तर पर रखा जाये; और

(ग) कर्मचारियों के संघ ने कलकत्ते में 6 अक्तूबर, 1964 को अपना जो वक्तव्य जारी किया था, उस में उठाई गई बातों पर क्या सरकार ने अपना दृष्टिकोण प्रकट किया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है ।

(ग) सरकार को ऐसे किसी वक्तव्य के बारे में जानकारी नहीं है ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

337. { श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री हेम राज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष के केन्द्रीय खाते में अब तक कुल कितना नकद चंदा आया है ;

(ख) इस में ब्रिटेन, अमरीका, रूस और अन्य देशों से कितना धन आया है ;

(ग) कितना चन्दा सोना और सोने के आभूषणों के रूप में आया है; और

(घ) राष्ट्रीय रक्षा कोष के धन में से कितना धन खर्च हो चुका है और अब कितना शेष है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) राष्ट्रीय रक्षा कोष के केन्द्रीय खाते में 31 अक्तूबर, 1964 तक कुल नकद चन्दा 59.10 करोड़ रु० प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस सारे चन्दे में से 90,91,346 रु० की राशि निम्नलिखित ढंग से विभिन्न देशों से प्राप्त हुई है :—

	रुपये
ब्रिटेन	28,19,564
अमरीका	5,97,486
रूस	19,648
अन्य देश	56,54,648
योग	90,91,346

(ग) इसी अवधि में सोने, सोने के आभूषणों तथा अन्य मूल्यवान धातुओं के रूप में इस प्रकार चन्दा प्राप्त हुआ :—

सोना/सोने के आभूषण	24,00,007 ग्राम
चांदी/चांदी के आभूषण	13,83,294 ग्राम
जवाहरात/कीमती पत्थर	2,537 कैरेट

(घ) अब तक कुछ 33.20 करोड़ रुपये का खर्च का प्राधिकार दे दिया गया है परन्तु वास्तव में लगभग 24 करोड़ रु० ही खर्च हुये हैं। 31 अक्तूबर, 1964 को इस कोष के केन्द्रीय लेखे में लगभग 35.10 करोड़ रु० की राशि शेष थी।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेहरू पर पूरी फिल्म

338. श्री हे० वी० कौजलगी :
श्री हेम बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार स्वयं इस फिल्म को बनायेगी या यह काम किसी निजी निर्माता को सौंपा जायेगा ;

(ग) कब फिल्म बन जाने की आशा है और इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(घ) क्या यह फिल्म देश में जनता को निःशुल्क दिखाई जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां।

(ख) अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

(ग) और (घ) इस मामले में अभी कुछ भी कहना समय से पूर्व होगा।

आणविक अनुसंधान

339. श्री हेडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अणुशक्ति संबंधी हमारे अनुसंधान तथा उस के शांतिपूर्ण उपयोगों का प्रचार करने के लिए क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अणुशक्ति विभाग अपनी गतिविधियों के बारे में प्रतिवर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट छापता है और "न्यूक्लियर इण्डिया" नाम का एक मासिक पत्र भी निकलता है । देश में तथा देश के बाहर होने वाली प्रदर्शनियों में भी यह विभाग भाग लेता है, जिस में इस के कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है । इस विभाग से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण बात होने पर अखबारों और रेडियो से भी उसका प्रचार किया जाता है । जो विदेशी मेहमान बम्बई आते हैं उन्हें ट्राम्बे की अणुशक्ति संस्थान दिखाया जाता है ताकि उन्हें पता लग सके कि अणुशक्ति के क्षेत्र में भारत में कितनी प्रगति की है ।

फिजी में भारतीय

340. श्री दे० द० पुरी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिजी में भारतीय उद्भव के जो गन्ना उत्पादक हैं, वे उस देश को छोड़ना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से वे इसके लिए मजबूर हैं;

(ग) क्या सरकार ने फिजी के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को एसी किसी बात की खबर नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

Bullet Proof Nylon Cloth

341. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Chairman of Silk and Art Silk Research, Bombay has disclosed that they have been able to develop bullet proof nylon cloth; and

(b) if so, whether Government have examined this cloth so as to use it for defence personnel ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) On the basis of the information available with the Director General of Inspection, the chairman of the Silk and Art Silk Manufacturing Industries Research Association, Bombay was asked to produce experimental samples of nylon cloth according to given technical details. By itself this cloth is not bullet proof. It contains some other elements which give some protection against shells, bombs and particles of nives.

(b) Yes, Sir, the samlpes are under examination.

Reception by Cairo Embassy

342. Shri Brij Raj Singh:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Hem Barua:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Indian Embassy at Cairo gave a reception in honour of Prime Minister on the occasion of the Conference of the Non-aligned nations:

(b) whether the ambassadors of Pakistan and China were also invited to the party; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Yes Sir, this reception was organised on the 3rd. October 1964.

(b) Yes Sir,

(c) According to the general practice of the host country *i.e.* U.A.R., the ambassador of China was invited in his capacity as a doyen of the diplomatic Corps. We have our diplomaic relations with Pakistan, the ambassador of Pakistan was, therefore, invited like those of such countries having diplomatic relations with India.

Cricket Commentary

343. Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 18th October 1964 the commentary on the Third Cricket Test Match at Calcutta, being relayed from the All India Radio was suddenly interrupted at 2.15 P.M. by the words, "a very important announcement is to be made;"

(b) whether it is also a fact that immediately after the interruption music was relayed and four or five minutes later the commentary was resumed;

(c) if so, the reasons for the interruption?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) No Sir,

(b) and (c). questions do not arise.

भारत में बनाये गये विमान

344. श्री ब्रजराज सिंह कोटा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बने एक जेट ट्रेनर विमान को अभी हाल में पहली बार उड़ाया गया है, ; और

(ख) यदि हां, तो इस विमान की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) यह एक इंजन वाला, वायु में करतब दिखाने वाला ट्रेनर विमान है जिसका नाम एच० जे० टी०--16 (हिन्दुस्तान जेट ट्रेनर -16) और यह जेट विमान की शिक्षा पालेयटों को देने के लिए बनाया गया है ।

डाक-तार विभाग के बाढ़ पीड़ित कर्मचारी

345. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की हाल की बाढ़ों से डाकतार विभाग के कितने कर्मचारी प्रभावित हुये; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों को किस प्रकार की सहयाता दी गई या दी जानेवाली है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) लगभग 1500 अधिकारियों ने बाढ़ सहायता अग्रिम धन के लिए आवेदन पत्र दिये हैं। बाढ़-पीढ़ितों की संख्या ठीक-ठीक पता नहीं है ।

(ख) 540 कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर अग्रिम धन स्वीकार किया गया है जो अर्द्ध वार्षिक किश्तों में वापस लिया जायेगा । अन्य मामलों में अभी विचार हो रहा है । उनकी सत्यता का पता लगा लेने के बाद इस प्रकार की अग्रिम सहायता राशि स्वीकार की जायेगी ।

जिन मामलों में उचित होगा, उन में डाकतार कल्याण कोष में से 50 रु० प्रति मामले के हिसाब अनुग्रह राशि दी जायेगी। इस संबंध 217 आवेदन पत्र आ गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

विभागीय तरक्कियां

346. **श्री नरसिम्हा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चपदों पर तरक्की देने के लिए विभाग के अफसरों को चुनने के मामले में विभागीय तरक्की समिति की, जिस में संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिनिधि होता है, राय हमेशा ली जाती है :

(ख) क्या ऐसी समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है यदि किसी सीनियर अफसर का हक मार कर किसी जूनियर अफसर को तरक्की दी जाये और यह अपील किस अधिकारी के पास की जाती है ; और

(ग) जब तक अपील पर विचार होता रहता है और उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक जूनियर अफसर की तरक्की स्थगित रखी जाती है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) गृह-कार्य मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार प्रत्येक विभाग में चुनाव के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर तरक्की देने के लिए विभागीय तरक्की समितियां बना दी गई हैं । डाक-तार विभाग की नौकरियों के संबंध में प्रथम श्रेणी के पदों पर और उस में पदोन्नति के मामले में विभागीय तरक्की समिति में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि की राय ली जाती है ।

(ख) विभागीय तरक्की समितियां केवल सलाहकार होती हैं और नियुक्त करने वाला अधिकारी उसकी सिफारिशों को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है । अतः इस समिति की सिफारिशों के विरुद्ध अपील करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

(ग) ऊपर (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अमरावती में रेडियो स्टेशन

347. **डा० मा० श्री अणे : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ डिवीजन के पश्चिमी जिलों की जनता ने अमरावती में एक रेडियो स्टेशन खोलने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अमरावती में रेडियो स्टेशन खोलना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अमरावती में रेडियो स्टेशन खोलने की कोई मांग नहीं है । हां यह मांग अवश्य है कि विदर्भ के किसी पश्चिमी जिले में एक सहायक प्रेषण केन्द्र खोल दिया जाये ताकि आकाशवाणी के नागपुर स्टेशन का क्षेत्र बढ़ाया जा सके ।

(ख) भारत में प्रसारण के विकास के बारे में जब चौथी पंचवर्षीय योजना या बाद की पंच-वर्षीय योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा ।

जन-संचार केन्द्र

348. **श्री प० कुन्हन :**
श्री नम्बियार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 7 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड फाउण्डेशन दल के विशेषज्ञों ने जन-संचार का गहन अध्ययन करने के लिए एक केन्द्र खोलने की जो सिफारिश की थी, क्या उसके संबंध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

जर्मन गणतंत्र को मान्यता

349. **श्री नम्बियार :**
डा० सारादीश राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार जर्मन गणतंत्र को मान्यता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 17–8–1961 को लोक सभा में विदेशी मामलों संबंधी वाद-विवाद में बोलते समय भूतपूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी और परिस्थितियों में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है कि भारत सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करे ।

अणु शक्ति का विकास

350. **श्री राम सेवक यादव** :
श्री रा० स० पांडे :
श्री रा० बरूआ :
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति संस्थान, ट्राम्बे के उपनिदेशक ने अक्तूबर, 1964 में काहिरा में संयुक्त अरब गणराज्य के अणु शक्ति संस्थान के महासचिव से बातचीत की थी कि दोनों देशों में अणु उद्योगीकरण के क्षेत्र में सहयोग होना चाहिए ;

(ख) क्या उक्त दोनों सज्जनों ने दोनों देशों के बीच विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण की संभावनाओं पर भी बातचीत की थी ;

(ग) क्या इस मामले में कोई करार हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) ट्राम्बे के अणुशक्ति संस्थान में कोई उप-निदेशक नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) 1962 में पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग के लिए एक करार हो गया था । इन पत्रों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में देखी जा सकती हैं ।

(घ) इस करार में अन्य बातों के साथ वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण का भी उपबंध है । हमने ट्राम्बे में अपने अणु शक्ति संस्थान में संयुक्त अरब गणराज्य के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पहले भी प्रशिक्षण दिया है और अधिकाधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं ।

श्रीलंका में रेल दुर्घटना

351. **श्री सेझियान** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 अक्तूबर, 1964 को श्रीलंका में मिरीगामा में जो रेल दुर्घटना हुई थी, उसमें कितने भारतीय मरे और घायल हुये ; और

(ख) इन व्यक्तियों और इनके परिवारों की जरूरतों तथा उनके हितों की देखभाल करने के लिए श्रीलंका स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). एक भारतीय राष्ट्रजन को चोट आई थी । उसकी चोट अच्छी हो गई है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है ।

Air Crash Near Bhatinda

352. **Shri Gulshan:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn towards an air crash which took place near Bhatinda in Punjab during September 1964 ; and

(b) if so, the causes of the accident ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas): (a) Yes Sir, This accident took place on the 23rd Sept. 1964 at a place about seven mile west of Bhatinda.

(b) A court of Enquiry has been ordered to enquire into the accident. The details will be available only after the report of the court of Enquiry is received.

विदेशी डाकघर बम्बई

353. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अक्टूबर, 1964 को जो आग लगी थी, उसमें बम्बई कामर्शियल सेन्टर में विदेशी डाकघर बिल्कुल नष्ट हो गया था ;

(ख) यदि यहां, तो कितनी हानि हुई ; और

(ग) आग लगने का क्या कारण था. ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं। केवल विदेशी पत्र विभाग, विदेशी पंजीयन विभाग और सीमा शुल्क परीक्षण विभाग (पत्र अनुभाग) जो स्वदेशी मिल्स एस्टेट के अहाते के भीतर थे, आग के कारण बिल्कुल नष्ट हो गये ।

(ख) अभी यह नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि कुल कितनी हानि हुई है क्योंकि अभी वहां मलबा हटाने का काम हो रहा है ।

(ग) आग लगने का कारण मालूम नहीं हो सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

केरल डाक-तार सर्किल

354. { **श्री पोट्टेकाट :**
श्री अ० व० राघवन : }

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल डाक-तार सर्किल का ग्रेड बढ़ाने के मामले में क्या कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो नया सर्किल कब बनाया जायेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) मामले पर जोरों के साथ विचार किया जा रहा है ।

(ख) कोई तिथि नहीं बताई जा सकती परन्तु आशा है कि निकट भविष्य में इसका अन्तिम निर्णय हो जायेगा ।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड

355. { श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास के उत्पादन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए किसी विदेशी फर्म के साथ बड़े पैमाने पर विस्तार की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) मोटी रूपरेखा यह है :—

(एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड का उत्पादन एक शिफ्ट में प्रतिवर्ष 1326 से 5400 टेलीप्रिंटर्स मशीन और दो शिफ्ट में 8500 मशीन प्रतिवर्ष तक बढ़ाना ; और

(दो) उपरोक्त विस्तार कार्यक्रम के सिलसिले में इटली से मिलने वाले 171.64 लाख रुपये के ऋण के अन्तर्गत बाद में पैसे देने के आधार पर पुर्जे, मशीनरी आदि खरीदना ।

रूस में भारतीय राजदूत

356. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ख्रुश्चेव के प्रधान मंत्री पद से त्याग पत्र देने और रूस में होने वाले दूरगामी परिवर्तनों के समय रूस में भारत के राजदूत रूस से बाहर गये हुए थे ;

(ख) उनके अनुपस्थित रहने का क्या कारण था और परिवर्तनों को सुनने के कितने दिन बाद वे अपने पद पर पहुंच गये ; और

(ग) क्या इस घटना से यह प्रतीत होता है कि हमारे राजदूत घटनाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । श्री ख्रुश्चेव के त्याग पत्र के समय राजदूत छुट्टी पर थे ।

(ख) भारत सरकार ने पहले राजदूत की 43 दिन की अर्जित छुट्टी मंजूर कर दी थी जो 2 अक्टूबर, 1964 से आरम्भ होती थी । राजदूत 17 अक्तूबर, 1964 को प्रातः वापस मास्को पहुंच गये थे ।

(ग) श्री ख्रुश्चेव के त्याग पत्र से लगभग सभी सरकारों को आश्चर्य हुआ था । उस समय और भी कई विदेशी राजदूत मास्को से अनुपस्थित थे । अतः ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि भारतीय राजदूत की मास्को से अनुपस्थिति घटनाओं के प्रति सजग न रहने के कारण हुई थी ।

सीमेंट उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

357. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग के मजूरी बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि सीमेंट के कर्मचारियों को कोई अन्तरिम सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की सिफारिशें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवेय्या) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेफा में बिजली लगाना

358. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नेफा (पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी) के कुछ क्षेत्रों में बिजली लगाने की एक योजना स्वीकार की है ; और

(ख) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं और अनुमित लागत क्या होगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी की 25 जगहों पर बिजली लगाने की एक योजना, जिस पर 36.13 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है, निम्नलिखित रूप में स्वीकार हुई है :

क्रमांक	जगह का नाम	अनुमित लागत लाखों में
		रुपये
1	चायेंगताजो	1.76
2	खनवा	1.76
3	निआौसा	0.67
4	सेपला	1.69
5	मेचुका	1.02
6	खेलोंग	1.11
7	जयराम्पुर	3.65
8	विजयनगर	0.97
9	बामेंग	1.04
10	कलकतंग	1.48
11	मेबो	1.17

क्रमांक	जगह का नाम	अनुमित लागत लाखों में
		रुपये
12	टूटिंग	1.17
13	बासर	1.35
14	नामसई	1.31
15	दामरो	1.49
16	तवांग	1.84
17	चोखम	1.20
18	न्यापिन	1.55
19	बालोंग	1.50
20	टकसिंग	1.53
21	हायुलियांग	1.60
22	अनीनी	0.95
23	कोलोरियांग	1.80
24	पासीघाट	1.11
25	डाम्बुक	1.41
	कुल योग	36.13

माली के राष्ट्रपति

359. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माली के राष्ट्रपति वीयतनाम जाते हुए 17 अक्तूबर, 1964 को या उसके लगभग बम्बई से गुजरे थे ;

(ख) क्या यह सच है कि हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिये सरकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं था ;

(ग) क्या इस बात का पता लगा लिया गया है कि यह किसकी गलती थी ; और

(घ) इस विषय में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । राष्ट्रपति और उनके दल के खाने-पीने, ठहरने और परिवहन के लिये प्रबन्ध कर दिया गया था और महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने उनका स्वागत किया था ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Post Office, Deoria

360. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) when the Post Office at Deoria (U.P.) is expected to start functioning in its newly constructed building ;

(b) the total amount spent on it ; and

(c) whether any quarters have also been constructed for the employees working in the G.P.O. and if so, the amount spent thereon.

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagwati) : (a) The work of water and electric installations is in progress. The post office is likely to function in the newly constructed building by the last week of December, 1964.

(b) Rs. 1,64,587 so far.

(c) Yes, Sir. Two units of quarters have been constructed at a cost of Rs. 16,830.

डाक-घरों में जमा-धन

361. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्प बचत आन्दोलन योजना के अन्तर्गत 31 अक्तूबर, 1964 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न डाक-घरों में कुल कितना धन जमा किया गया ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): विभिन्न अल्प-बचत योजनाओं अर्थात् डाक-घर बचत बैंक [सी० टी० डी० (क्रमिक जमा-धन) सहित], राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-पत्र, प्रतिरक्षा जमा-पत्र और प्रीमियम पुरस्कार बंध-पत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश परिमण्डल के डाकघरों में 1–4–1964 से 30-9-1964 तक कुल जमा की राशि 30,83,62,710 रुपये थी और उक्त अवधि में शुद्ध जमा-राशि अर्थात् डाक-घर बचत बैंक से निकलवाये गये धन और बजत प्रमाणपत्रों का भुगतान करने पर दी गई राशि को निकाल कर, 5,88,48,699 रुपये थी ।

अक्तूबर, 1964 मास के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

सूचना और प्रसारण मंत्री की विदेश यात्रा

362. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्री को हाल में विभिन्न देशों का, जिनमें रूस भी शामिल है, दौरा करने के लिये भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विदेश परिभ्रमण का विशिष्ट प्रयोजन क्या था और उसका क्या परिणाम रहा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्री यूनेस्को के महासम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की एक सदस्या के रूप में हाल ही में पेरिस गई थीं । उन्होंने इस अवसर से लाभ उठा कर कुछ अन्य देशों का, जिनमें रूस भी शामिल है, दौरा किया जिससे वे अन्योन्य रुचि की बातों पर चर्चा कर सकें । उनकी उन देशों में जो बातचीत हुई वह उन्होंने वहां से लौट कर प्रधान मंत्री को बता दी है ।

कोयला-खानों में कदाचरण के आरोप

363. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल-रानीगंज कोयला पट्टी की विभिन्न कोयला खानों अर्थात् ; बनकोला, नई-जमाहारी खास, बबीसोल तथा अन्य खानों में गम्भीर कदाचरण के आरोपों के बारे में भारतीय खान कर्मचारी संघ के महामंत्री से 25 सितम्बर, 1964 को सरकार को एक पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां, किन्तु यह केवल बनकोला, बबीसोल और नई-जमाहारी खास कोयला-खानों के सम्बन्ध में है ।

(ख) विभिन्न श्रमिक विधियों के अन्तर्गत अनियमितताओं को दूर करने और कामगरों की शिकायतों के निराकरण के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है या आरम्भ की जा रही है ।

कोयला खान कल्याण निधि

364. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बनकोला कोयला-खान के प्रबन्धकों द्वारा कोयला-खान कल्याण निधि के क्वार्टरों के दिये जाने के सम्बन्ध में कोयला-खान मजदूर सभा से भेद-भाव के गम्भीर आरोप प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) और (ख). कोयला-खान श्रम कल्याण आयुक्त को एक शिकायत मिली है जिसकी जांच की जा रही है ।

बर्मा स्थित भारतीयों के लिये आपात्कालिक प्रमाण-पत्र

365. **श्री कजरोलकर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा स्थित भारतीय दूतावास ने 28 अक्तूबर, 1964 को यह घोषणा की कि वे उन भारतीय राष्ट्रजनों से, जो भारत जाना चाहते हैं, आपात्कालिक प्रमाण-पत्रों के लिये आवेदन-पत्र लेना उस दिन से जनवरी, 1965 के अन्त तक स्थगित कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दूतावास द्वारा भारत आने के इच्छुक प्रवासियों को जुलाई, 1964 से अब तक कितने आपात्कालिक प्रमाण-पत्र दिये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) रंगून स्थित भारतीय दूतावास ने बर्मा में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को, जो समुद्र के रास्ते डेक के यात्रियों के रूप में भारत आना चाहते हैं, आपात्कालिक प्रमाण-पत्र जारी करना जनवरी 1965 के अन्त तक स्थगित कर दिया है ।

(ख) चूंकि एक आपात्कालिक प्रमाण-पत्र केवल छै मास तक वैध होता है इसलिये यह समझा गया कि इस प्रकार के प्रमाण-पत्र केवल तब जारी किये जायें जब आवेदकों को अगले कुछ मासों में समुद्र से डेक पर भारत जाने के लिये स्थान मिलने का आश्वासन मिल जाये । इस समय दूतावास की प्रतीक्षा-सूची में बहुत से लोग आने के इच्छुक हैं और समुद्र के रास्ते डेक की श्रेणी में भारत आने के लिये आपात्कालिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले नये आवेदकों को कुछ मास तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

(ग) दूतावास 1 जुलाई, 1964 से 15 नवम्बर, 1964 तक 59,691 आपात्कालिक प्रमाण-पत्र जारी कर चुका है ।

बागानों में काम की स्थिति

366. **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान उद्योग समिति ने यह सिफारिश की है कि बागानों में काम की स्थिति का पता लगाने के लिये एक तथ्य अन्वेषण समिति नियुक्त की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां । 30-31 अक्तूबर, 1964 को नई दिल्ली में हुए बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के ग्यारहवें अधिवेशन ने यह सिफारिश की थी कि बागानों में काम के प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच करने और छै मास के अन्दर सरकार को रिपोर्ट देने के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की एक व्यक्ति की तथ्य अन्वेषण समिति बनाई जाये ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये मंत्रालय का एक वरिष्ठ पदाधिकारी चुन लिया गया है ।

नेताजी हाल सोसाइटी के मंत्री के साथ प्रधान मंत्री का पत्र-व्यवहार

367. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री त्रिदीव कुमार चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु के प्रश्न के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने की आवश्यकता के बारे में उन्होंने नेताजी हाल सोसाइटी, कलकत्ता के मंत्री के साथ पत्र-व्यवहार किया है ; और

(ख) इस विषय में उनका निर्णय क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में यायिक जांच करवाने के लिये नेताजी हाल सोसाइटी, कलकत्ता के महा-मंत्री श्री अमिय बोस के सुझाव के सम्बन्ध में उनसे प्रधान मंत्री का कुछ पत्र-व्यवहार हुआ था ।

(ख) यह अनुभव किया गया है कि आगे और जांच करने से कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने पहले जो समिति नियुक्त की थी उसके सामने सम्बन्धित जानकारी यथोचित रूप में रख दी गई थी ।

भारत पाक सीमांकन

368. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा के चटगांव पहाड़ी प्रदेश और मिज़ो पहाड़ी क्षेत्र के सीमांकन के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में एक करार हुआ है और यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ख) इस करार की शर्तों के अनुसार कर्णफूली बांध बनाने के बारे में दोनों देशों के बीच झगड़े को किस प्रकार सुलझाया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत के सर्वेक्षण विभाग और पाकिस्तान के केन्द्रीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधियों की बैठक 3 और 4 नवम्बर, 1964 को हुई थी और वे आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा के चटगांव पहाड़ी प्रदेश तथा मिज़ो पहाड़ी क्षेत्र का सीमांकन करने के लिये आसाम सरकार द्वारा विभाजन से पूर्व जारी की गई सम्बन्धित गजट अधिसूचनाओं और विभाजन पूर्व के नक्शों को आधार मानने के लिये सहमत हो गये थे ।

(ख) जब इस क्षेत्र का सीमांकन पूरा हो जायेगा तो यह पता लगेगा कि भारत का ठीक-ठीक कितना प्रदेश सीमा के पार की इस पाकिस्तानी परियोजना में डूब जायेगा । उसके बाद पाकिस्तान सरकार पर मुआवज़ा देने के लिये जोर डाला जायेगा । भारत सरकार ने इस विषय में पाकिस्तान सरकार को जो पत्र पहले भेजे हैं उनमें मुआवाज़ा मांगने और अन्य उपयुक्त कार्यवाही करने के बारे में अपनी स्थिति सुरक्षित रखी गई है ।

काश्मीर की स्थिति में परिवर्तन के विरुद्ध पाकिस्तानी विरोध-पत्र

369. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जेना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में पाकिस्तान से कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें काश्मीर की स्थिति में कोई परिवर्तन करने के विरुद्ध भारत को चेतावनी दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। सरकार को पाकिस्तान सरकार से दो विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं, एक तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के बारे में लोक सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी विधेयक के विरुद्ध और दूसरा कुछ केन्द्रीय अधिनियमों के जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू किये जाने के विरुद्ध ।

(ख) इस प्रश्न का उत्तर सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने पूरी तरह से दे दिया है। पाकिस्तान ने जो प्रश्न उठाया है वह भारत का बिल्कुल घरेलू मामला है और उसका सम्बन्ध केवल भारत से है और उसके सम्बन्ध में पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने या दखल देने का कोई अधिकार नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत इसे संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्राधिकार से स्पष्ट रूप से निकाल दिया गया है ।

इस प्रकार का उत्तर शीघ्र ही पाकिस्तान सरकार को भेज दिया जायेगा ।

डाक व तार विभाग में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियां

370. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग के कार्यालयों में विशेष रूप से नागपुर में सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व के लिये रजिस्टर नहीं रखा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार के रजिस्टर के बिना इन जातियों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मैंगनीज कामगरों के लिये मजूरी बोर्ड

371. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मैंगनीज़ की खानों में काम करने वाले कामगरों के लिये एक मजूरी बोर्ड नियक्त करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) अभी इन कामगरों के लिये मजरी बोर्ड स्थापित करने का विचार नहीं है ।

मैंगनीज की खानों के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण

372. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज़ की खानों में काम करने वाले कामगरों के औद्योगिक विवादों के लिये जबलपुर या नागपुर में औद्योगिक न्यायाधिकरण को बैठाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीव्या) : (क) कुछ समय पहले यह सुझाव दिया गया था कि नागपुर में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये अथवा वर्तमान न्यायाधिकरणों के लिये नागपुर में मुकदमे सुनने की व्यवस्था कर दी जाये ।

(ख) चूंकि विवादों की संख्या बहुत थोड़ी थी इसलिये नागपुर में एक न्यायाधिकरण स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया । परन्तु बम्बई का केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण समय-समय पर नागपुर में बैठता रहता है और इस प्रथा को जारी रखा जा रहा है । और कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

12—00 बज

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

Re : CALLING ATTENTION NOTICE—(Query)

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr. Speaker, Sir, I had given a Calling Attention Notice regarding a bomb explosion in the room of Pandit Prem Nath Dogra. It was disallowed. When we ask questions regarding explosions at other places, they are replied to. What is the reason that when an explosion took place in the room of a great leader no order was issued for enquiring into that ? How far is it improper to protest against that ? This should be enquired into.

Shri Bade (Khargaon) : We were told for the last four days that it was under consideration. Now we have been told that it has been disallowed.

An hon. Member : What is the reason therefor ?

Mr. Speaker : The one reason for it might be that when the notice was received it was considered as to whether we should admit it or not. The hon. members should have come to me, as happens here daily and I would have called for the file and explained the reasons for its disallowance, but it cannot serve any purpose by raising the matter here.

Shri Onkar Lal Berwa : Every day explosions take place and the House is informed about them, how far is it justified that an explosion has taken place in the house of a big leader and it has not been enquired into ?

Mr. Speaker : If any hon. Member has any grievance he can come to me. I am prepared to reconsider the matter. He may convince me how that matter could be taken up in Parliament. I have no objection about that even now. As regards giving permission, I want to repeat before Parliament what I said to the Minister of Parliamentary Affairs in the morning. Shri Banerji had also raised this matter earliar that when a Calling Attention Notice is given members consider the matter very urgent. But when I refer the matter to the Minister for facts it takes 3-4 days and sometimes five days and even after that the reply is not received. The hon. Members object to that. I go on waiting for the information and the work is accumulated. I would request the Government that since the matters referred to in the Calling Attention Notices are urgent it should not take more than twenty four-hours to reply. It should reach me so that I may reply to the members. I do not get replies from the Ministries and people criticise me.

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narain Sinha): As you have been pleased to observe I had a talk with some of the ministers in this regard. They do say that sometimes it takes more time to collect the information regarding the matters raised in the Calling Attention Notices. We are trying our best to minimise the time, but it might be difficult to receive the replies in twenty-four hours in all the cases. Sometimes you may have to give some more time.

Mr. Speaker : Everybody has to carry out his responsibility. I am grateful to the hon. Minister for telling that they would send the replies as early as possible. But I may point this out that if he considers that there is a *prima facie* case, then the Minister may reply that he has not received the information which he had asked for and that he could not reply immediately otherwise the misunderstanding is created that I was withholding the matter.

श्री रंगा (चित्तूर) : श्रीमान, मुझे प्रसन्नता है कि आपने कृपा करके ये बातें कही हैं और सरकार को यह सलाह दी है। मुझे यह भी आशा है कि प्रधान मंत्री जी, जो यहां बैठे हैं, मंत्रालय के विलम्ब के करण सदस्यों में विद्यमान इस असन्तोष की ओर ध्यान देंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : This notice was given on the 18th and we were informed that it was under consideration. Again when we enquired on the 21st, we were told that the notice had been admitted and that it would be taken up on Monday or Tuesday. I want to know that why this has been disallowed now.

Mr. Speaker : I have been told that it was not said that it has been admitted but it was told that it was under consideration. You may see the file.

श्री स० **मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमन्, हमने जम्मू और काश्मीर के प्रधान मंत्री श्री सादिक का वक्तव्य पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि किस प्रकार पाकिस्तानी सीमा पार करके घुस आये हैं और तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां कर रहे हैं और गड़बड़ फैला रहे हैं। मैंने इसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण सूचना दी थी। उसको तो अस्वीकार कर दिया गया है किन्तु इसी विषय पर एक और सूचना आज स्वीकार कर ली गई है। इन दोनों को मिला देना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग है। ध्यानाकर्षण सूचना के समय मैं उसे भी लूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I and Shri Banerji had given notice of an Adjournment Motion regarding the statement made by Shri Jayaprakash Narayan in which he has referred to Nagaland as an independent entity leaving aside the Constitution. Even regarding Indian Parliament he has described it as intolerant. This could very well form the basis for a motion of privilege. This matter must be discussed here. A similar statement was made by him earlier regarding Aksai-chin. I would submit that if a person talks like this against the country D.I.R. could be used against him . . .

Mr. Speaker : Order, Order. I have told you that such things should not be made the subject matter of Adjournment Motions and Call Attention Notices. But Shri Shastri, though he is a prudent and wise parliamentarian has made a grievance thereof. How a particular statement made by Shri Jayaprakash Narayan. could form a subject matter of an Adjournment Motion here ?

श्री स० मो० बनर्जी : इसके गम्भीर परिणाम होंगे। उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिये या नहीं, इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्हें हिरासत में रखा जाये (**अन्तर्बाधा**)।

श्री रंगा : ये भाषण की स्वतंत्रता के पोषक हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने सारी लोक-सभा की खिल्ली उड़ाई है और माइकेल स्काट का समर्थन किया है जिसने सारे मामले की जांच की मांग की है।

अध्यक्ष महोदय : चाहे जो कोई भी वक्तव्य दे क्या वह स्थगन प्रस्ताव का विषय बन सकता है कि सरकार इसमें असफल रही है? क्या सरकार बोलने से पहले ही किसी का मुख बन्द कर सकती है?

एक माननीय सदस्य : वह मिशन के एक सदस्य हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO NOTICE OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जनमत संग्रह मोर्चे के नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्य

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him that he may make a statement in regard thereto:—

Recent statements made by the leaders of the Plebiscite Front in Jammu and Kashmir giving out threats of agitation against the Government of India.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : Government have seen the press reports about the utterances of certain leaders of the Plebiscite Front at the Annual Session of the Front held at Sopore on the 15th November, 1964. Some of these reported utterances are no doubt objectionable. In regard to Kashmir, the legal and constitutional position as well as the view point of the Government are quite well known and there is no question of making any change in them. Requisite action would be taken if there is a threat of disorder or of lawlessness.

The question of law and order is primarily the concern of the State Government. The Prime Minister of Jammu and Kashmir has made a statement recently giving a warning to these elements that if any struggle which transgresses law and order is launched the State Government would deal with it very firmly. The State Government are watching the situation.

Shri Prakash Vir Shastri : The leaders of the Plebiscite Front Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg, who had called the conference, are openly threatening the Government of India of revolting against it and are throwing challenges to the Government. Their supporters had stoned the Kashmir Prime Minister recently at Baramullah. There serious developments could not be dismissed simply as "some utterances". I want to know why such persons have not been put behind the bars ?

श्री रंगा (चित्तूर) : यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया तो क्या होगा ? (**अन्तर्बाधा**)

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : As regards their arrest, if some action is to be taken, that is the responsibility of the Jammu and Kashmir Government. As far as the statement of Home Minister is concerned that shows that he has been very careful about it and Shri Sadiq has unequivocally said that if some mischievous agitation is engineered severest possible action will be taken against it.

Shri Prakash Vir Shastri: That is not the question. Rather the question is as to whether the Government of India is determined to take action under D.I.R. or some other law to arrest the Indian Citizen who acts for the disintegration of a part of the country. When these persons since their release from the prison, why Government of India are not enforcing their law against them ?

Shri Lal Bahadur Shastri: No Sir, no such declaration has been made. The position is clear. Action is to be taken keeping in view the whole situation. At that time when this was said China's aggression against us was continuing. If anybody had said such thing on that occasion, we would have taken the severest action against him, but if on some other occasion some-body had said such thing we would not have strangulated him. We would fight him on the political level and if the need arises we would fight on government level as well.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला ने अपने एक भाषण में कश्मीर को नेपाल और बर्मा के समान बताया है और यदि ऐसा है तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे पता नहीं । मैंने भाषण नहीं पढ़ा । उसने और बातें कहीं जिन्हें मैंने देखा है किन्तु जिस बात का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसे मैंने नहीं देखा कि उसने बर्मा और नेपाल को एक ही श्रेणी में रखा है । इस बारे में कुछ कहने से पहले हमें इसकी जांच करनी होगी ।

Shri Kachhavaiya (Dewas): There have been several bomb explosions in Jammu and Kashmir. Just four or five days back a bomb was exploded at the house of Shri Prem Nath Dogra, the President of Bhartiya Jan Sangh with an object to kill him. How many persons have been arrested by the Government in this connection? Whether Sheikh Abdullah had a hand in it? If so, what action is being taken by the Government against him ?

Shri Hathi: As I have already said law and order is the responsibility of Jammu and Kashmir Government and they are taking action in this connection and they have also arrested some persons.

Shri Bade (Khargone) **:** Whether it is a fact that since the convention of plebiscite front and the speeches made by the leaders of the front, there has been an increase in the bomb explosions and there have been disturbances at Baramula and other places. Under these circumstances why these persons are not being arrested under the Defence of India Act ?

Shri Hathi: As the Prime Minister has said, it is the responsibility of Jammu and Kashmir Government to make arrests under the Defence of India Act. The Prime Minister of Jammu and Kashmir has again said yesterday that if the need arises he would take severe action against them. He has warned them and some persons have been arrested there.

Shri Bade: I had asked that whether it is a fact that after the speeches had been made in the convention of Plebiscite Front, there has been an increase in the incidence of bomb explosions?

Shri Hathi: The statement of the Hon. Member is true to some extent and that is why the Prime Minister of Jammu and Kashmir has given such warning.

अध्यक्ष महोदय : अब अगला विषय लिया जाए ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैंने दिल्ली के हाउस सर्जनों की हड़ताल के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय उस पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

Dr. Ram Monohar Lohia (Farrukhabad): There is a point of order.

Mr. Speaker: No point of order can be raised at this juncture.

Dr. Ram Monohar Lohia: I had sent censure motion against the Prime Minister.

Mr. Speaker: For that the Hon. Minister should contact me.

Dr. Ram Mohnohar Lohia: Sir, you are trying to side track the matter. The speaker has, as a matter of fact, no right to give permission or withhold it for a censure motion.

Mr. Speaker: He may write to me and I would reply him forthwith. Now this question cannot be raised here. If I allow to raise all such matters we cannot proceed with the other business of the House.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान मैं विभिन्न सत्रों में जैसा कि प्रत्येक के सामने बताया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1 . नवां सत्र, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 3 . आठवां सत्र, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 6 . सातवां सत्र, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 9 . छटा सत्र, 1963 (तीसरी लोक-सभा)

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 11 . पांचवां सत्र, 1963 (तीसरी लोक-सभा)

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 14 . चौथा सत्र, 1963 (तीसरी लोक-सभा)

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 21 . पहला सत्र, 1962 (तीसरी लोक-सभा)

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या 19 . बारहवां सत्र, 1960 (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3412/64 से एल० टी० 3419/64]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैं इन आश्वासनों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह बात डा० लोहिया ने निन्दा प्रस्ताव के रूप में उठाई थी। प्रधान मंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा था कि सामुदायिक विकास खण्डों से सब जीपें वापस ले ली जायेंगी। डा० लोहिया और मेरी जानकारी के अनुसार वे जीपें अभी तक नहीं हटाई गईं। इस प्रकार उस आश्वासन का पालन नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : वे इस बारे में आश्वासन समिति को लिख सकते हैं। समिति इस बारे में रिपोर्ट देगी।

श्री स० मो० बनर्जी : वह वक्तव्य प्रधान मंत्री जैसे महान व्यक्ति ने दिया था।

अध्यक्ष महोदय : तो भी उसका अध्ययन करने के लिए आश्वासन समिति है।

When I have not allowed other twenty persons to raise it how can I decide in a different way for your sake.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, there is a censure motion and not an adjournment motion or any other type of motion, so you are not doing proper in side tracking it.

Mr. Speaker: He might not like my act which is a part of duty but under the democratic set up he will have to obey me.

Dr. Ram Manohar Lohia : For me it is impossible to allow a bad act to continue and to let the house proceed.

Mr. Speaker : Hon. Member cannot be allowed to interfere the proceedings.

Dr. Ram Manohar Lohia: You may do your duty and I would do mine. I do not wish that the Government should develop their habit of giving assurances and of not carrying them out.

Mr. Speaker: I cannot allow any member to abstract the business of the House.

Dr. Ram Manohar Lohia: I am proceeding according to rules and you may please allow me to have my say.

Mr. Speaker: Dr. Sahib you are not proceeding according to rules. If you intend to obey the rules you may sit down and contact me when I am off from here. When I have not allowed twenty others members how can I act differently in your case.

Dr. Ram Manohar Lohia: My motion is different. It is censure motion.

Mr. Speaker: You may now sit down, and contact me. If I find necessary I might allow you to raise it even today.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं समझता था कि मैंने ठीक अवसर पर यह प्रश्न उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु किसी आश्वासन का प्रश्न इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता।

श्री बड़े (खारगोन) : जब सभा में कोई आश्वासन दिया जाता है तो क्या हम यह नहीं पूछ सकते कि वह आश्वासन है या नहीं और क्या उसे कार्यान्वित किया गया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को संदेह हो कि कोई आश्वासन कार्यान्वित किया गया है या नहीं तो वे आश्वासन समिति को लिख सकते हैं कि वे उस बारे में प्रतिवेदन दें । उसके बाद यदि वे सदस्य चाहे तो उस प्रतिवेदन पर चर्चा हो सकती है।

Dr. Ram Manohar Lohia: Sir there is a difference between an assurance and a declaration. This is a declaration which was made by the Prime Minister. It is improper to consider it as an assurance.

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी को डा० लोहिया से उत्तर मिल रहा है ।

Dr. Ram Manohar Lohia: Your laughter and falsehood has done much wrong to the country.

विधेयक पर राय

OPINIONS ON BILL

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी पत्र संख्या 5, जो 13 सितम्बर, 1963 को सभा के निदेश द्वारा जनमत जानने के लिये परिचालित किया गया था, सभा पटल पर रखती हूं ।

निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा उसके बारे में मंत्री का उत्तर

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND MINISTER'S REPLY THERETO

अम्बाला जल में श्री हुकम चन्द कछवाय के साथ किये गये दुर्व्यवहार सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Sir I lay on the table the enquiry report of District Magistrate, Ambala regarding the allegations of maltreatment meted out to me in the Ambala Central Jail and the Governments statement in regard thereto which was laid on the table on the 15th, April, 1964. **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3420/64]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, इसे सदस्यों में परिचालित किया जाए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं इसके उत्तर में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3420/64]**

अन्तराष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: INTERNATIONAL SITUATION

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाए ।"

श्रीमन् इस मास की 17 तारीख को मैंने सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें विश्व की उन महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा प्रस्तुत की थी जो गत अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच की अवधि में घटी हैं। इस काल में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं घटी हैं। एक तो निर्गुट राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ है जिसमें विश्व के सभी महाद्वीपों से अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था।

यूरोप के दो महत्वपूर्ण देशों में शासन व्यवस्था बदल गई है। एक तो रूस में श्री खुश्चेव के सेवा निवृत्त होने पर नये नेताओं ने कार्य भार संभाल लिया है। इंगलैंड में लेबर पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और शासन की बागडोर संभाल ली है। रूस के नये नेताओं ने हमें आश्वासन दिया है कि वे खुश्चेव की नीति का पालन करेंगे अर्थात् शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और निर्गुटता का समर्थन और भारत के साथ मैत्री।

इंग्लैंड में लेबर पार्टी ने चुनाव में जिन उद्देश्यों की घोषणा की थी उनके लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिये हैं। उनका सम्बन्ध उनके आन्तरिक मामलों से है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे प्रतिरक्षा मंत्री अभी इंग्लैंड से लौटे हैं और सभा को उसके बारे में बतायेंगे। हमें आशा है कि इंग्लैंड के साथ हमारे मैत्री सम्बन्ध और सुदृढ़ होंगे।

अमरीका में राष्ट्रपति जानसन का बहुमत से जीतना इस बात का प्रतीक है कि अमरीका के लोग शान्ति की नीति का समर्थन करने में दृढ़ निश्चयी हैं और अतिवादी शक्तियों के विरूद्ध हैं। ये सब घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस सभा ने चीन के अणु विस्फोट की निन्दा करके अच्छा ही किया। मैं इन सब बातों का उल्लेख कर चुका हूं और अब माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद अपने विचार व्यक्त करूंगा। किन्तु उससे पहले कुछ बातों पर बल देना चाहता हूं।

काहिरा सम्मेलन ने यह बता दिया है कि भले ही विश्व में दुर्भाग्यवश अभी झगड़ालू शक्तियां हैं किन्तु अधिकांश राष्ट्र समझौते की नीति के पक्ष में हैं। सम्मेलन की चर्चा में इन पांच सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है

(1) निर्गुटता।

(2) शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व।

(3) शान्ति के उपायों से राज्यों के मतभेदों का निबटारा।

(4) राष्ट्रों की स्वतंत्रता के समय उनकी जो सीमाएं थीं वे अपरिवर्तनीय हैं।

(5) पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करना।

श्री नाथ पाई : आप उन्हें नये सिद्धांत क्यों कहते हैं। ये तो वही सिद्धांत हैं जिन्हें पंचशील का नाम दिया गया था।

श्री स्वर्ण सिंह : आप इन्हें जो भी नाम देना चाहें दें, किन्तु यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय के ये सर्वोत्तम नियम हैं और इन्हीं की सहायता से विश्व को संघर्ष और युद्ध से बचाया जा सकता है।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों में सदस्यों को निश्चय ही बहुत रुचि है और उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम ईमानदारी से इन सम्बन्धों में सुधार करना चाहते हैं । इसी उद्देश्य से हम पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने का प्रयत्न करते रहे हैं ।

सभा को विदित है कि जब हमारे प्रधान मंत्री निर्गुट राष्ट्रों के सम्मेलन से लौटे थे तो वे करांची में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले थे और एक संयुक्त विज्ञप्ति में यह आशा प्रकट की गई थी कि दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और सहयोग की स्थापना की जायगी । दुर्भाग्यवश हाल ही में पाकिस्तानियों ने कश्मीर और त्रिपुरा में सीमोल्लंघन की गतिविधियां बढ़ा दी हैं और पाकिस्तान के समाचारपत्रों में भारत निन्दा का प्रचार बढ़ गया है । ये काम मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में बाधक हैं । हमने प्रस्ताव रखा था कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलकर बातचीत करें और ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सीमोल्लंघन की घटनाएं न हों और दोनों देशों के जन धन की व्यर्थ हानि न हो । 2 नवम्बर को वह बैठक होने वाली थी किन्तु पाकिस्तान की प्रार्थना पर उसे स्थगित करना पड़ा । इसी तरह दोनों देशों के गृह मंत्रियों की बैठक 23 नवम्बर को होने वाली थी किन्तु पाकिस्तान की प्रार्थना पर उसे भी स्थगित करना पड़ा है । आशा थी कि इन दो बैठकों में दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण करार हो जायेंगे । अब भी हमें आशा है कि दो बैठकें शीघ्र ही हो सकेंगी ।

पाकिस्तान के समाचारपत्र भारत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के चुनाव में विरोधी दल को सहायता दे रहा है । ये आरोप न केवल निराधार हैं बल्कि निन्दनीय भी हैं । खेद की बात है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और सूचना मंत्री जैसे उत्तरदायी लोगों ने भी इस प्रकार के निराधार आरोप लगाये हैं । चुनाव पाकिस्तान का निजी और आन्तरिक मामला है और हमारे मन में उनके प्रति शुभ कामना है किन्तु हमें इस बात पर बहुत खेद है कि जिस समय हम परस्पर सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील थे वे भारत के विरुद्ध भावनाओं को भड़काने लगे हैं ।

पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है और हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हों किन्तु इसके लिए पाकिस्तानी नेताओं के सहयोग की आवश्यकता है ।

श्री लंका के साथ भारत मूलक लोगों के सम्बन्ध में जो करार हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं एक दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहता हूं ।

इस करार के अनुसार हम श्रीलंका के 5,25,000 भारत मूलक भागों को पन्द्रह वर्ष की अवधि में लेंगे । 1,30,000 लोगों को उन्होंने नागरिकता प्रदान कर दी है और लगभग $4\frac{1}{2}$ लाख लोगों को वे नागरिकता प्रदान करेंगे । इस करार की दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि एक तो इन लोगों को पन्द्रह वर्ष की अवधि में लिया जायगा ।

Shri Rameshwara Nand (Karnal) : why 5,25,000 people are being taken when they have been resident of that country for several decades ?

श्री स्वर्ण सिंह : वे धैर्य रखें । मैं उस ओर भी आ रहा हूं । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका सरकार इन भारतीयों को अपनी सम्पत्ति लाने की अनुमति देंगे और उसके लिए उन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा देंगे ।

श्री जी० भ० कृपालानी : क्या सरकार इन भारत मूलक लोगों को श्रीलंका के नागरिक मानती थी या अब तक उन्हें भारतीय नागरिक समझती थी?

श्री स्वर्ण सिंह : उनकी कानूनी स्थिति के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच बहुत समय से विवाद चल रहा था। भारत का यह मत था कि वे लोग भारत के नागरिक नहीं। उन्हें नागरिकता विहीन कहा जा सकता था।

श्री रंगा (चित्तूर) : हम उन्हें नागरिकता विहीन क्यों स्वीकार करते हैं?

श्री जी० भ० कृपालानी : हमने कभी इस मत को स्वीकार नहीं किया। हम उन्हें सदा श्रीलंका के नागरिक समझते रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : करार के गुणावगुणों के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। वास्तविक स्थिति यह है कि उन लोगों को श्रीलंका ने नागरिकता प्रदान नहीं की थी। यह उचित है या अनुचित किन्तु स्थिति यही थी।

श्री रंगा : भारत सरकार का क्या रवैया था?

श्री स्वर्ण सिंह : वह भी मैं बता दूंगा। 1954 या 1955 में लंका की संसद् ने एक कानून पारित किया था जिससे लंका सरकार को भारतीय तथा पाकिस्तानी उद्भव के लोगों को लंका की राष्ट्रीयता देने आधिकार मिला था और उसके बाद भारतीय उद्भव के बहुत से लोगों ने लंका की नागरिकता के लिये प्रार्थना-पत्र दिए। इसलिए यह कहना कि वे पहले ही वहां के नागरिक थे, तथ्य नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि वे लोग बहुत लम्बे समय से वहां बसे हुए हैं इसलिए उन्हें वहां से उखाड़ा न जाए। परन्तु जो तथ्य न हो, उस पर जोर देना ठीक नहीं है।

पिछले 20 या 25 वर्षों में कई बार आपस में बातचीत हुई है जिसमें लंका सरकार ने यही कहा है कि चाहे ये व्यक्ति लंका में रहते हैं परन्तु वे भारतीय नागरिक हैं। हमने यह कहा है कि कई पीढ़ियों से ये लोग वहां हैं और उन्होंने लंका को ही अपना घर बना लिया है। इतना कहने पर भी हम उन्हें विवश नहीं कर सकते क्योंकि बाहर के लोगों को नागरिकता देना किसी देश के कानूनों और संविधान पर निर्भर है। अतः यह तथ्य है कि इन लोगों को वहां की नागरिकता नहीं दी गई, वहां के चुनावों या राजनैतिक जीवन में इन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं था और हम नहीं चाहते थे कि इनका भविष्य सदा अनिश्चित ही रहे।

हमने सदा इसे एक मानवीय समस्या माना है और समझा है कि जो लोग वहां बस गये हैं उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध उखाड़ा न जाए परन्तु जो किसी कारण आना चाहते हैं उनके लिये हमने कभी अपने द्वार बन्द नहीं किये। 130,000 व्यक्तियों के अतिरिक्त भारतीय उद्भव के शेष व्यक्तियों को लंका की नागरिकता नहीं दी गई है और बातचीत के दौरान हमने कभी यह नहीं जताया कि वे वहां के नागरिक हैं। हमने यह कहा था कि क्योंकि वे लोग वहां रहते रहे हैं इसलिये वे भारत के नागरिक नहीं हैं और यहां की नागरिकता के लिये उन्हें अभ्यावेदन करना होगा।

इस पृष्ठभूमि में हमें यह फैसला करना था कि इस अनिश्चित स्थिति को चलने दिया जाए या कोई ऐसा हल निकाला जाए जो दोनों सरकारों तथा उन लोगों को स्वीकृत हो और जिससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सकें।

2031 RSD—5.

श्री रंगा : क्या उन्हें स्वीकार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब मैं वहां गया था तो भारतीयों के नेताओं से बातचीत की थी और यह सच है कि हमारे बहुत से लोग भारत लौटना चाहते हैं ।

श्री नम्बियार : क्या पांच के पांच लाख व्यक्ति आ जाना चाहते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह नहीं कहता कि सारे के सारे 5,35,000 व्यक्ति वापस आ जाना चाहते हैं परन्तु लाखों की संख्या है जो आना चाहते हैं । भारत लौटने के लिये वहां हमारे हाई कमीशन से जो मांग की गई है उससे यह स्पष्ट हो जाता है । इसीलिये हमने यह समझौता किया है ताकि सारी चीज नियमित रूप से हो सके । ऐसा समझौता लेन-देन के भाव से ही हो सकता है और साथ ही हमें एक पड़ौसी तथा मित्र देश की कठिनाइयों का भी ध्यान रखना है । इसमें हठधर्मी से काम नहीं हो सकता । एक बार मैं फिर कह दूं कि प्रत्यावर्तन पन्द्रह वर्षों में होगा और वे अपनी चीजें साथ ला सकते हैं ।

श्री सेझियान : वे हमारे लोग नहीं हैं । लंका सरकार उन्हें हम पर लादना चाहती है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लंका के प्रतिनिधिमण्डल ने बातचीत के दौरान कभी यह नहीं कहा... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को महसूस करना चाहिये कि केवल एक ही सदस्य बोल सकता है । एक दूसरे के प्रति इतना शिष्टाचार तो होना ही चाहिये ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं बता रहा था कि बातचीत के दौरान इस प्रश्न का उल्लेख नहीं हुआ था कि लंका की नागरिकता जिन व्यक्तियों को मिलेगी उन्हें अलग चुनाव रजिस्टर में रखा जायेगा या नहीं । जिन 1.30 लाख व्यक्तियों को आठ-नौ वर्ष पहले वहां की नागरिकता दी गई थी, वे सामान्य चुनाव रजिस्टर में दर्ज थे तथा हम समझते थे कि नये व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं होगा । परन्तु अब जब यह बात हमारे ध्यान में आई है तो हमने इस पर चिन्ता व्यक्त की है और हमारे प्रधान मन्त्री लंका की प्रधान मन्त्री के साथ इस प्रश्न को उठा रहे हैं । लंका सरकार इसे एक घरेलू मामला समझती है परन्तु इस तरह के मामले में जहां नागरिकता के अधिकार के बारे में दो देशों में समझौता हो गया हो, यदि वह अधिकार अपने सामान्य रूप से भिन्न हो तो वह इस समझौते से सम्बन्धित हो जाता है । इस समझौते के बारे में मैं यही बातें सभा को बताना चाहता था ।

अब मैं अफ्रीका के बारे में कुछ मुख्य बातें कहूंगा । जम्बिया, मलावी तथा माल्टा के स्वतन्त्र होने और राष्ट्रमण्डल के सदस्य होने का हम स्वागत करते हैं । डा० कैनेथ कुआंदा के जम्बिया के पहले राष्ट्रपति बनने का भी हम स्वागत करते हैं । दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण रोडेशिया तथा पुर्तगाली बस्तियों में अब भी उपनिवेशवाद अपने घिनौने रूप में विद्यमान है । श्वेत अल्पसंख्यकों की सरकार बनने की सम्भावना से दक्षिण रोडेशिया में जो स्थिति पैदा हो गई है उससे हमें बड़ी चिन्ता है । अफ्रीकी लोगों की महत्वाकांक्षाओं का मान करते हुए हम स्पष्ट घोषणा कर चुके हैं कि हम स्वतन्त्रता की एक पक्षीय घोषणा को मान्यता नहीं देंगे । हम चाहते हैं कि अफ्रीकी नेताओं को छोड़ दिया जाए और एक व्यक्ति को एक वोट के आधार पर वहां आम चुनाव किये जायें । ब्रिटिश सरकार ने धमकी देने तथा संसार के दबाव डालने

से श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने अपना एक-पक्षीय निर्णय टाल दिया है और हम आशा करते हैं कि दक्षिण रोडेशिया की समस्या का कोई सन्तोषजनक समाधान हो जायेगा ।

कुछ दिन पहले ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका भेजने वाले हथियारों पर रोक लगा दी है जिसका हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि अन्य देश भी इसी तरह का कदम उठा कर संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के अनुरूप कार्य करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाए ।"

अनेक स्थानापन्न प्रस्ताव हैं ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : श्रीमान, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : श्रीमान, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमान, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : श्रीमान, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : श्रीमान, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री किशन पटनायक : श्रीमान, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव के साथ साथ ये सभी संशोधन विचार के लिये सभा के सामने हैं ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : श्रीमान, चीन द्वारा अणुबम का विस्फोट तथा श्री खुश्चोव का विस्थापन हाल ही की दो ऐसी महान घटनायें हैं जिनका सारे विश्व के लिये तथा विशेषतः भारत के लिये बड़ा महत्व है । इनके परिणामों को समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम 15 अक्तूबर, 1964 को जो स्थिति हमारे पड़ौस में थी उस पर एक दृष्टि डाल लें। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ काश्मीर का प्रश्न अभी हल नहीं हुआ है और पाकिस्तान हमारे शत्रु चीन के साथ सांठगांठ कर रहा है । उत्तर में 1962 की हमारी पराजय के बाद से चीनी सेनायें हिमालय की चोटियों पर अपनी तोपों का मुंह हमारी ओर किए हुए हैं । उत्तर ही में नेपाल हमारे तथा चीनी साम्यवादियों के बीच तटस्थता बरत रहा है । पूर्व में हम पिछले 10 वर्षों से नागाओं के साथ उलझे हुए हैं और मुझे खुशी है कि इस सम्बन्ध में हमने सुलह-सफाई का मार्ग अपनाया है और मन्त्री महोदय के कथनानुसार उस पथ से विचलित नहीं होंगे । पूर्व में कुछ आगे चलिये तो बर्मा हम से बिगड़ता जा रहा है । चीन के पिछलग्गू लाओस तथा वियतनाम को साम्यवादी साम्राज्यवाद के घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं और अकेला अमरीका ही उनका सामना कर रहा है । दक्षिण में हम देखते हैं कि इण्डोनेशिया ने मलयेशिया पर हमला कर दिया है और साम्यवादी चीन तथा रूस उसे थपथपा रहे हैं । यदि साम्यवादी अपनी चालों में सफल हो जाते हैं तो हम अपने आपको कराची से लेकर सिंगापुर तक दुश्मनों से घिरा हुआ पायेंगे ।

यह सब हमारी गलत नीतियों का परिणाम है। हमने अपने पड़ौसी देशों की ओर से आंखें मूंदे रखीं। मुझे खुशी है कि वर्तमान प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री इन देशों से मैत्री स्थापित करने के लिये अधिक प्रयत्नशील हैं परन्तु इसका एक नमूना यदि हाल का भारत-लंका समझौता है तो यह शुभारम्भ नहीं है। हम इस समझौते को नहीं मानते क्योंकि यह मनुष्य की मूलभूत स्वतन्त्रता और अधिकारों पर कुठाराघात है। 17 नवम्बर के "ओपीनियन" में कहा गया है कि यह एक अपमानजनक समझौता है जिससे लंका की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरे दर्जे के नागरिक बन जायेंगे क्योंकि लंका की प्रधान मन्त्री ने उन्हें अलग चुनाव रजिस्टर में रखने की बात कहनी शुरू कर दी है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि अब जबकि लंका की प्रधान मन्त्री ने ऐसी बात कह कर समझौते की जड़ को ही काट दिया है तो इस समझौते को रद्द कर देना चाहिये।

इस पृष्ठ भूमि में श्री खुश्चेव को निकाला गया और चीन ने बम विस्फोट किया। हमें इन दोनों घटनाओं के परिणामों को देखना है। चीनी विस्फोट के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। यह विस्फोट संसार के लिए एक चेतावनी है कि चीन में आक्रमण करने की शक्ति है और भारत के लिये एक धमकी है कि यदि उसने अपनी खोई हुई भूमि पाने की कोशिश की तो उसका जवाब अणु शक्ति से दिया जायेगा। 1962 की चीन की विजय के बाद से एशिया तथा अफ्रीका के अधिकतर नये देश चीन से डरने और उसका मान करने लगे हैं और अब तो वहां चीन का बोलबाला हो जाने की सम्भावना है।

इसके मनोवैज्ञानिक तथा राजनैतिक पहलू और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। चीनी साम्यवादी दावा करेंगे कि उन्होंने आणविक हथियारों पर श्वेत एकाधिकार को समाप्त करने में पहल की है। परन्तु यह सच नहीं है क्योंकि 1955 से 1959 तक रूस चीन को बम बनाने के लिये तकनीकी तथा आर्थिक सहायता देता रहा है और वास्तव में यह एक रूसी बम है परन्तु एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों तक यह बात नहीं पहुंचेगी और चीन को इस बम के सहारे भारत तथा एशिया के अन्य स्वतन्त्र देशों की स्वतन्त्रता को धक्का पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

श्री खुश्चेव को निकाल देने के बारे में मैं इस मत को नहीं मानता कि वह तथाकथित स्टालिनवादियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। यह बिल्कुल गलत है। वह लड़ रहे थे नये मध्यम वर्ग के उन लोगों के विरुद्ध जो उनकी तानाशाही को समाप्त कर देना चाहते थे। वह अपना शासन बनाये रखने के लिये अपनी तानाशाही को संवैधानिक राजशाही का रूप दे रहे थे।

श्री नाथ पाई : यह ठीक दिशा में कदम था।

श्री मी० रु० मसानी: मैं मानता हूं और यह भी कह दूं कि नये शासक इस दिशा में और भी आगे जायेंगे। हो सकता है कि श्री कोसीगिन रूस के आर्थिक ढांचे को और भी अधिक उदार और आधुनिक बनायें। अभी पिछले दिनों उन्होंने किसानों को वह भूमि लौटा दी है जो श्री खुश्चेव ने साल दो साल पहले उनसे छीन ली थी।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सम्बन्ध है वह सुखद नहीं है। श्री खुश्चेव के विस्थापन पर मार्शल चेन-यी ने ठीक ही कहा है कि इससे समाजवादी शिविर में एकता के फिर से स्थापित होने की सम्भावनायें बढ़ गई हैं। दूसरे शब्दों में साम्यवाद की टूटी हुई दीवार के पुनः खड़े हो जाने की सम्भावना पैदा हो गई है। तथ्यों को जानने वाले लोग जानते हैं कि मास्को तथा पीकिंग के आपसी मतभेद सैद्धान्तिक होने के साथ साथ व्यक्तिगत भी थे। खुश्चेव और माओ त्से-तुंग एक दूसरे से घृणा करते थे और उनके होते हुए ये मतभेद दूर नहीं हो सकते थे। एक के चले जाने से अब ऐसा सम्भव

हो गया है। पूरी तरह से मतभेद भले ही दूर न हों परन्तु यह समझ लेना कि रूस की नई सरकार भी पीकिंग के उतना ही विरुद्ध होगी अपनी और लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। नई सरकार चीन से मित्रता बढ़ाने की प्रत्येक कोशिश करेगी। हमें आश्वासन दिए गए हैं परन्तु साम्यवादी तानाशाही के आश्वासनों का कोई अर्थ नहीं होता। अब हमें यह देख कर अपना मार्ग बनाना है कि मास्को में एक ऐसी नई सरकार है जो भारत की मित्रता की बजाय चीन के "भाई चारे" को अधिक महत्व देगी।

ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने तीन ही रास्ते हैं। पहला यह कि हम संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व मत से अपील करें कि चीन को अणु बम के परित्याग के लिये विवश किया जाए। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि चीन विश्व मत की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। जब उसने तिब्बत पर हमला किया, भारत पर चढ़ाई की या अणु परीक्षण बन्द करने की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से साफ इन्कार किया तो क्या उसने संसार की परवाह की थी? इसलिये मैं प्रधान मन्त्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि केवल विश्व मत पर भरोसा करके हम अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे सरकारी प्रवक्ता कहते हैं कि यदि आणविक युद्ध छिड़ता है तो सभी उसमें ग्रस्त होंगे। इसलिये भारत के पास बम हो या न हो, कोई अन्तर नहीं पड़ता। यह बहुत बड़ा भ्रम है। एक तटस्थ देश को यह आशा रखने का कोई अधिकार नहीं है कि उसके लिये कोई दूसरा देश अपने अस्तित्व को खतरे में डालेगा। मान भी लीजिए कि एक बम गिरा कर दिल्ली, बंगाल, बिहार आदि को भस्मीभूत कर दिया जाता है और उसके बाद अमरीका पीकिंग पर बमबारी करता है तो क्या हमारी नीति का यही मुख्य उद्देश्य है कि हमारे साथ कोई दूसरा भी तबाह हो? अब हमारी अणु नीति का उद्देश्य बदला ही नहीं बल्कि दूसरे को युद्ध से रोकना होना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब हम किसी बड़ी शक्ति से समझौता करलें कि हम पर आणविक आक्रमण होने पर वह हमारी सहायता करेगी?

इस संदर्भ में अहिंसा की नीति की बात करना भी निरर्थक है क्योंकि कल ही प्रधान मन्त्री ने कहा था कि हम अपनी सेनाओं की शक्ति बढ़ा रहे हैं तथा केवल दो ही दिन पहले श्री चव्हाण अधिक शस्त्रों के लिये लन्दन में थे। इस समय सिद्धान्तों का कोई प्रश्न नहीं उठता।

और फिर कहा जाता है कि हम डरते नहीं हैं। प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि कोई देश हमें अणु बम से डरा नहीं सकता। काश कि ऐसा ही होता। परन्तु एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मैं तो पीकिंग द्वारा एक बम गिराये जाने से लाखों व्यक्तियों का सफाया हो जाने से अत्यन्त भयभीत हूं। बंगलौर के "माइसिन्दिया" ने अपने 8 नवम्बर के अंक में लिखा है कि "अणु बम से चीन की शक्ति बहुत बढ़ गई है और उससे डरना ही हमारे लिये ठीक होगा परन्तु जब हमारे नेता कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, उससे हम कांप उठते हैं।" प्रधान मन्त्री कहते हैं कि डरना बचकाना है। बच्चों की सी बात तो तब होगी यदि हम तथ्यों से आंखें मूंद लें, यह मानने से इन्कार कर दें कि चीन में हमें डराने और तबाह कर देने की शक्ति है। मैं नहीं समझता कि बड़े पैमाने पर तबाही से डरने में शर्म की क्या बात है।

जहां तक स्वयं कुछ न करके केवल विश्व से अपील करने की नीति का सम्बन्ध है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों दल--मास्को दल तथा पीकिंग दल--भी इसी का समर्थन करते हैं। देशभक्त होने के नाते हमें सोचना है कि हम कहां तक इस नीति को उनके साथ अपना सकते हैं क्योंकि इसे अपनाये जाने से हम मास्को या पीकिंग के पिछलग्गू बन सकते हैं और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं जो कि सरकार का प्रथम कर्तव्य है।

[श्री मी० रु० मसानी]

इसके साथ ही मैं दूसरे रास्ते की ओर आता हूं और वह है बम बनाना । और बम बनाने का उद्देश्य यह न हो कि दिल्ली का नामोनिशान मिट जाने के बाद हम पीकिंग पर बम फेंकें; हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि चीन के दिल में ऐसा डर पैदा कर दें कि वह हमारी ओर आंख उठा कर देख न सके । अब सोचना यह है कि क्या हम इतनी लागत उठा सकते हैं । प्रधान मन्त्री जी ने गुन्टूर में कहा था कि बम पर 40 से 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैंने सुबह उत्तर दिया था . . .

श्री मी० रु० मसानी : यदि अखबारों में ग़लत छपा है तो मैं प्रधान मंत्री से क्षमा चाहता हूं । इस बारे में कई आंकड़े दिये गये हैं । एक अमरीकी विशेषज्ञ क्रिस्टोफर होहेनहेमसर के अनुसार हमारे आणविक कार्यक्रम पर 25 करोड़ रुपये लगेंगे और वार्षिक व्यय 10 करोड़ रुपये होगा । अमरीकी अणु शक्ति आयोग ने भी 25 करोड़ की लागत बताई है । किसी और ने एक यूरेनियम संयंत्र को स्थापित करने तथा चलाने के लिये 1,000 करोड़ रुपये का खर्च बताया है । फ्रांस ने अपने सेना बजट के लिये 3,200 करोड़ रुपया स्वीकार किया है जो हमारी चौथी योजना के कुल वार्षिक व्यय का तीन-चौथाई है । बम को बनाने पर जितना खर्च होगा उतना ही उन तैयारियों पर होगा जो उसे लक्ष्य पर फेंकने के लिये की जायेंगी । यह भी ध्यान में रखना होगा कि पीकिंग, शंघाई तथा मंचूरिया की औद्योगिक बस्तियां हम से 2,500 मील दूर हैं जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आदि तिब्बत में चीनी अड्डों से केवल 300 मील दूर हैं । इधर मार्शल चेन-यी कहते हैं कि चीनी नंगे रह कर भी अणु बम बनायेंगे । परन्तु क्या एक लोकतंत्रीय सरकार लोगों को भूखा और नंगा रख कर बम बना सकती है ?

बनायें भी तो परिणाम क्या होगा ? कृषि, भारी उद्योगों तथा उपभोक्ता वस्तुओं का झगड़ा ही समाप्त हो जायेगा, सारी विकास योजनायें ठप हो जायेंगी क्योंकि योजना का तीन-चौथाई तो प्रतिरक्षा पर खर्च हो जायेगा । लोग भुखमरी और आर्थिक संकट के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे । और इसका सबसे बड़ा लाभ होगा इस देश में पीकिंग का नाम जपने वालों को । इसलिये बम बनाने का पागलपन करके हम पीकिंग की चाल को सफल होने में सहयोग देंगे ।

बम बना लेना ही पर्याप्त नहीं, उसे गिराने में पहल करना भी आवश्यक है और क्या हमारे शान्त भाव वाले प्रधान मंत्री अथवा यहां की कोई भी सरकार उसके लिये तैयार होगी ? केवल चीनी कम्युनिस्ट ही ऐसा कर सकते हैं और उनके दिलों में डर पैदा करने के लिये उनसे दस गुना अधिक सबल होना ज़रूरी है जो कि आर्थिक, राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी पहुंच के बाहर है । व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हमें अणुबम नहीं बनाना चाहिये ।

अब हमारे सामने जो तीसरा रास्ता खुला है वह है एक दूसरे पर निर्भर करने के सिद्धान्त को मानना और आणविक मामलों में चीनी बम का यही एकमात्र उत्तर है । अमरीका और रूस दो ही ऐसी शक्तियां हैं जो चीन को धमका सकती हैं । इसलिये हमें उनके साथ अपने बचाव के लिये समझौता करना चाहिये । यदि हम अकेले ऐसा नहीं करना चाहते तो ईरान, मलयेशिया, फिलिपाइन्स, थाईलैंड, जापान आदि स्वतंत्रता-प्रिय देशों के साथ मिल कर यह समझौता कर कर सकते हैं । मेरे विचार में रूस इसे नहीं मानेगा । श्री हरिमैन ने बताया है कि एक बार उन्होंने श्री ख्रुश्चोव के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा था जो उन्होंने ठुकरा दिया था । वहां की नई सरकार से तो इसकी बिल्कुल ही आशा नहीं रखी जा सकती क्योंकि वह पीकिंग से मैत्री

बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है । अतः हम दोनों देशों के सामने यह प्रस्ताव रखें । दोनों मान लें तो अच्छा है । परन्तु यदि एक ही मानता है तो हमें उसकी सहायता का आश्वासन तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये ।

आज यदि किसी का डर माना जाता है तो अमरीका का । हम मानें या न मानें परन्तु पिछले बीस वर्षों में अमरीका ने एशिया तथा यरोप के कई देशों की प्रभुसत्ता की रक्षा की है अन्यथा स्टालिन सारे यूरोप को और माओत्सेतुंग सारे एशिया को निगल गया होता । प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम अपनी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता को गिरवी नहीं रख सकते । मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं । परन्तु आजकल स्वतंत्रता का पुराना अर्थ सार्थक नहीं रहा । ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री विल्सन ने अपने देश की प्रतिरक्षा के लिये अमरीका से बातचीत पुनः आरम्भ करने की बात कही है । क्या इसका यह मतलब है कि वह ब्रिटेन की स्वतंत्रता अमरीका के हाथों में सौंप रहे हैं ? नये जापानी प्रधान मंत्री श्री साटो ने 11 नवम्बर को कहा है कि जापान अणु बम नहीं बनायेगा परन्तु अपनी सुरक्षा के लिये अमरीकी सहायता स्वीकार कर लेगा । क्या वह जापान की प्रभुसत्ता को गिरवी रख देना चाहते हैं ? इसलिए मैं आशा करता हूं कि हम वही पुरानी रट नहीं लगाते रहेंगे क्योंकि आज तो हालत यह है कि यदि हम आणविक सहायता स्वीकार नहीं करते तो हमारी स्वतंत्रता धीरे-धीरे छिन जायेगी । राष्ट्रपति जानसन ने 18 अक्तूबर को एक वक्तव्य में कहा भी है कि जो राष्ट्र आणविक शस्त्र नहीं चाहते, वे विश्वास रख सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अमरीका उनका साथ देगा । बजाय इसके कि पहले हम पर बम गिरे और फिर हम सहायता के लिये चिल्लायें, यह अधिक अच्छा होगा कि पहले से ही इस प्रस्ताव को मान लें ताकि चीन को हम पर आक्रमण करने की हिम्मत न हो सके और हम अपनी सभी आशाओं तथा स्वप्नों को पूरा कर सकें । और इस तरह का समझौता गुप्त रूप से नहीं बल्कि खुल्लमखुल्ला किया जाये ताकि चीन को कान हो सकें कि उनका बम गिरने से पहले उन्हें मिटा दिया जायेगा ।

पूछा जाता है कि क्या यह तटस्थता की नीति के विरुद्ध नहीं होगा । हम तो इस नीति को मानते नहीं हैं परन्तु जो मानते हैं उनके लिये भी ऐसा समझौता कठिन नहीं होना चाहिये । यदि तटस्थता का यही अर्थ है कि हम दूसरे देशों से सहायता न मांगें तब पंडित नेहरू ने अक्तूबर 1962 में इसकी अवहेलना की थी और ऐसा करके उन्होंने देश के हित में तथा तटस्थता के अनुरूप ही काम किया था । अतः यदि आज कोई कहता है कि मैं ऐसा कह कर तटस्थता की नीति के विरुद्ध जा रहा हूं तो वह पंडित नेहरू की निन्दा करता है । आणविक सहायता लेना, जो देश के अस्तित्व के लिये अत्यावश्यक हो, तटस्थता ही है और वर्तमान सरकार को यह बात मान लेनी चाहिये । तटस्थता का यह अर्थ नहीं है कि सहायता तब मांगी जाये जब आधा देश तबाह हो चुका हो ।

अन्त में मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि देश को किन बातों की आवश्यकता है । हमें उन खोखली नीतियों को छोड़ देना चाहिये जिनके कारण विश्व में हमारा अपमान हुआ और न जंज़ीबार, न बर्मा और न लंका हमारा आदर करते हैं । हमें मित्रों और शत्रुओं की पहचान करनी है । शत्रु से लड़ना सीखना है और मित्र को मित्र बनाये रखना है । पड़ौसी देशों से मित्रता बढ़ानी है । पुराने हथियारों में आत्मनिर्भर होना है तथा आणविक शस्त्रों में अच्छे विश्व नागरिक ।

श्री बडे : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 पेश करता हूं ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri **Thirumal Rao** in the Chair]

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : सभापति महोदय, वैदेशिक कार्य मंत्री ने अपने भाषण में हमें बताया कि ब्रिटेन और अमरीका में सरकारें बदल गई हैं और इन नई सरकारों का दृष्टिकोण हमारे प्रति वैसा ही रहेगा, जैसा पहले था । रूस की सरकार में भी परिवर्तन हुए हैं परन्तु उसकी नीति भी हमारे प्रति वैसी ही रहेगी ।

जब माननीय मंत्री बोल रहे थे, तो स्वतंत्र दल के नेता बार-बार अन्तर्बाधा उत्पन्न कर रहे थे । यह ठीक नहीं है । उन्हें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए और इस प्रकार उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए ।

कांग्रेस दल में तर्क और उनके पीछे निहित देशभक्ति की भावना को ही प्राधान्य प्राप्त है ।

श्री मसानी ने प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बात का उल्लेख किया कि हमें डरना नहीं चाहिए । प्रधान मंत्री का यह कथन सत्य ही है । गांधी जी के नेतृत्व में हम ने यही सीखा है कि हम निडर बनें । हम ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद का सामना निडर बन कर ही किया है । अतः जब प्रधान मंत्री कहते हैं कि हमें चीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी भावना से प्रेरित होकर कहते हैं । इसी भावना के बल पर देश को आजादी मिली है ।

चीन ने अणुबम बनाया है, तो क्या आफत आ गई । हम में से कुछ लोग बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं लेकिन ऐसी विकट स्थिति में हमें साहस से काम लेना है । कठिनाइयां तो आती-जाती ही रहती हैं ।

अधिकृत सूत्रों से पता लगा है कि चीन के पास लगभग 25 लाख नियमित सेना और 15 लाख रक्षित सेना है, अर्थात कुल करीब 40 लाख सेना है । चीन के शस्त्र पुराने किस्म के हैं । माना कि अब चीन ने अणु बम बना लिया है परन्तु अभी 10 वर्षों तक वह प्रभावी ढंग से किसी देश पर अणु बम छोड़ नहीं सकता । जहां औद्योगिक प्रगति का सम्बन्ध है, हमारे देश की औद्योगिक प्रगति चीन की औद्योगिक प्रगति से किसी भी प्रकार कम नहीं है । हमारे कालेजों में देश के नवयुवक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं; लगभग 10,000 विद्यार्थी यूरोप और अमरीका में विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । अतः हम चीन जैसे शस्त्र बना सकते हैं परन्तु वस्तुतः इस समय हम देश की जनता की हालत सुधारने के प्रयत्न में लगे हुए हैं इसी कारण हम ने अपनी सेना बढ़ाने की ओर अधिक जोर नहीं दिया है ।

चीन द्वारा अणुबम का बनाया जाना संसार के लिए खतरे का संदेश है । हमारे विदेश मंत्री आस-पास के देशों में लोगों को इस खतरे से आगाह कर देंगे ताकि विश्व-शान्ति के लिए कोई खतरा न पैदा होने पाये । वह रूस जा रहे हैं । प्रधान मंत्री ब्रिटेन जा रहे हैं । प्रधान मंत्री ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ विश्व शान्ति पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे ।

1962 में जब हमारे देश पर चीन का आक्रमण हुआ, तो ब्रिटेन की महारानी, वहां के प्रधान मंत्री और संसद-सदस्यों ने जो भाषण दिये उनसे हमें बड़ी शक्ति तथा बल मिलता है । राष्ट्र मंडल के राजनयिकों ने बारबार यह बात दोहराई है कि वे भारत को चीन या अन्य किसी देश का गुलाम नहीं बनने देंगे । अतः सामान्य मिली जुली रक्षा की भावना राष्ट्र मंडल में है । श्री मसानी जो चाहते हैं वह बात भावना की दृष्टि से मौजूद है ।

चीन आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह हमारे किसी नगर पर अणु बम गिरा दे। उसके पास अभी वे उपकरण नहीं हैं जो अणु बम गिराने के लिए आवश्यक होते हैं। उसके पास पुराने किस्म के विमान हैं। अतः अणुबम बना लेने का यह मतलब नहीं कि वह उस बम द्वारा किसी देश को जीत लेंगे।

मैं श्री मसानी की इस बात से सहमत हूं कि चीन पड़ोसी देशों या विश्व जनमत को नहीं मानेगा। कितने दिनों से उससे कहा जा रहा है कि वह कोलम्बो प्रस्तावों को मान ले, परन्तु वह उन्हें मानने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत वह कहता है कि कोलम्बो प्रस्ताव बनाने वाले देशों को वह समझौता कराने वाला या मध्यस्थ नहीं मानता।

चीन द्वारा अणुबम बनाये जाने पर चारों तरफ उसकी आलोचना हुई पर चीन अपने रास्ते पर ही है। जब अमरीका, ने अणुबम का परीक्षण किया था उसके बाद जब रूस फ्रांस और ब्रिटेन ने अणुबम का परीक्षण किया, तो संसार के लोगों ने उसका विरोध किया था और हो-हल्ला मचाया था। आज चीन के मामले में हो-हल्ला समाप्त हो चुका है और हम चाहते हैं कि अमरीका या रूस भारत और विश्व की रक्षा करें। चीन के लोग बड़े हठी हैं। उन पर आलोचना या हो-हल्ला का कोई असर नहीं हुआ। आज चीन का कोई देश मित्र नहीं है। अमरीका से उसका झगड़ा है। रूस भी उससे खुश नहीं है। दक्षिण-पूर्व एशिया के लोग भी बाहर से चाहे कुछ न करें परन्तु अन्दर ही अन्दर वे भी चीन को बुरा समझते हैं। फिर भी, अकेला चीन अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है। अतः हमें भी ऐसे अवसर पर दृढ़ निश्चय से ही काम लेना चाहिए। हमारा दृढ़ निश्चय ऐसा होना चाहिए जो चीन की विचारधारा उसके, हथकण्डों और आक्रमणकारी नीतियों को काबू में रख पाये।

परन्तु यह कैसे किया जाये, यह बताना मेरा काम नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री देश भक्त हैं और वे जनता के विचारों को समझते हैं, उनमें हठधर्मी की भावना नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क तथा बातचीत के द्वारा, मुझे विश्वास है कि वह आज की विद्यमान प्रवृत्तियों के बारे में जान सकेंगे और मुझे आशा है कि आगामी कुछ महीनों में वे ऐसी नीति बना सकेंगे जोक हमें सभी प्रकार के आक्रमणों--अणुबम के या अन्य प्रकार के--से सुरक्षित रख सकेगी।

डा० मा० श्री अणे : हम लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में माननीय मंत्री का भाषण सुना। रूस की सरकार में परिवर्तन हो गया है। ब्रिटेन में भी नया दल सत्तारूढ़ हो गया है। इन दोनों परिवर्तनों का हमारे लिए बड़ा महत्व है। इसके बाद एक और खतरे की बात है कि चीन ने निशस्त्रीकरण करार में भाग नहीं लिया और उसने अणुबम बनाकर उसका विस्फोट भी कर दिया। इन सब बातों का उल्लेख उन्होंने किया है।

परन्तु मैं विशेष रूप से श्रीलंका में उत्पन्न स्थिति से चिन्तित हूं। वायसराय के शासन-काल में और उसके बाद भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्रीलंका के रहने वाले भारतीयों की देखभाल करने के काम से मेरा संबंध रहा है।

मैं सरकार से बराबर पूछता हूं कि इस मामले में श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के क्या विचार हैं। क्या वे भारत आना चाहते हैं या नहीं।

[डा० मा० श्री अणे]

आरम्भ में भारतीय नागरिक वहां मजदूरों के रूप में काम करने गये थे। कुछ लोग वहां व्यापार करने भी गये थे और उन्होंने वहां बड़े-बड़े उद्योग-व्यापार खोले।

मेरा कहना है कि पिछले 50 वर्षों में श्रीलंका में चाय बागान और रबर के बागानों में जो समृद्धि हुई है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय भारतीयों को है। इसके अलावा वहां बहुत सारा व्यापार और उद्योग भी भारतीयों के द्वारा हो रहा है।

श्रीलंका में आज़ादी की भावना आई, यह बात ठीक है। धीरे-धीरे उनमें 'श्रीलंका श्रीलंका वालों का' की भावना भी पैदा हुई और यह भावना जाति और रंग के आधार पर पैदा हुई। वहां पर भारत के मुसलमान और हिन्दू दोनों हैं। श्रीलंका वाले सोचते हैं कि जब श्रीलंका स्वतन्त्र है तो भारतीयों का वहां रहना श्रीलंका वालों के हित में नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को एक बात बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल में जब भारतीय वहां मजदूरों के रूप में भेजे गये थे, तो भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उसमें स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया था कि यद्यपि ये भारतीय एक निश्चित काल के लिए वहां भेजे जायेंगे, परन्तु उसके बाद भी यदि वे चाहेंगे, तो वहां रह सकेंगे, और वैसे ही रह सकेंगे जैसे श्रीलंका के अन्य नागरिक रहते हैं।

1943 के लगभग जब मैं वहां था और उसके पहले भी जब मैं वहां था, उस समय श्रीलंका की आजादी की लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई में श्रीलंका वासियों के साथ वहां रह रहे भारतीयों ने भी हाथ बढ़ाया। उसी समय श्रीलंका वासियों को यह कहते सुना गया था कि इंगलड की सरकार ने भारत की जनता या सरकार की ओर से श्रीलंका के साथ जो भी करार किये हैं, या जो बातें उनके बीच तय थीं, श्रीलंका उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मेरा कहना है कि श्रीलंका में या भारत में अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो सरकारें बनीं उन्हें उन पुराने करारों को मानना चाहिए—कम से कम श्रीलंका में रह रहे भारतीयों के सम्बंध में। परन्तु श्री लंका वालों का विचार इससे भिन्न है। वह चाहते हैं कि अधिकांश भारतीयों को वहां से भारत वापस भेजा जाये। कई वर्षों से यह खींचतान चलती रही है।

आगे और गलतफहमी न बढ़ने पाये, इसलिए यह निर्णय किया गया कि मेरा ख्याल है यह 1938 की बात है, अब भारतीयों को श्रीलंका में मजदूरों के रूप में भेजना बन्द कर दिया जाये। पुराने कांग्रेस सदस्यों को स्मरण होगा कि हमने इस आशय के कई प्रस्ताव भी पास किये थे और उसके बाद भारतीयों को मजदूर के रूप में वहां भेजना बन्द कर दिया गया।

श्रीलंका में ब्रिटेन की सरकार ने एक कमीशन बैठाया—संविधान बनाने के लिए। श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों ने उस कमीशन के सामने मांग की कि जो भारतीय श्रीलंका में पैदा हुये या जिनके माता-पिता वहां पैदा हुये हों, या रह रहे हों, उन्हें वहां का नागरिक अधिकार दे दिया जाये। श्रीलंका वासियों ने उस कमीशन का बहिष्कार बाहरी तौर पर किया।

लेकिन श्रीलंका वालों का कहना था इस मामले में कमीशन उस बात को ध्यान में न रखे कि भारतीय मजदूरों को किन शर्तों पर श्रीलंका में बुलाया गया। उस समय सीलोन इण्डियन कांग्रेस भी वहां थी और उनका एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भी गया ताकि वे अपनी बात ठीक ढंग से समझा सकें और अपने हितों की रक्षा कर सकें। इस शिष्टमण्डल ने कहा कि जो भारतीय वहां पहले से रहते आ रहे हैं उन्हें नई व्यवस्था में श्रीलंका का नागरिक माना जाये और उस अवधि के बाद वहां गये भारतीयों के बारे में सरकार जो चाहे निर्णय करे।

परन्तु जब कानून पास हुआ, तो भारत सरकार चुपचाप मुंह देखती रह गई। स्वर्गीय श्री गिरजा शंकर वाजपेयी को बातचीत करने के लिए भेजा गया। उन्होंने एक करार तैयार कराया परन्तु भारत सरकार ने उसे भी नहीं माना क्योंकि उसमें भारतीयों को कुछ विशेष प्रकार का कारबार करने से रोका गया था।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि श्रीलंका वासी भारतीयों की राय से यह करार किया गया है। मैं पूछता हूं कि किस स्तर पर उनसे राय की गई थी। क्या इस करार की सब बातें उन्हें बताई गई थीं ? यदि उनके सुझावों को भारत सरकार ने माना। मैं समझता हूं कि श्रीलंका वासी भारतीयों को 'बिना राज्य का नागरिक' मानना हमारी निरन्तर चलने वाली नीति के विपरीत है।

उसके बाद श्रीलंका में सरकार ने नागरिक बनाने का कानून पास किया। 10 प्रतिशत लोगों को छोड़ दिया गया और केवल 10 प्रतिशत लोगों को नागरिक बनाया। उसके बाद इन भारतीयों की समस्या आई। इन लोगों ने नये कानून के अधीन नागरिक बनने के लिए आवेदनपत्र दिये परन्तु उनके आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिये गये। इस प्रकार ये लोग 'राज्यहीन' व्यक्ति बन गये। और अब हमने यह दुर्भाग्यपूर्ण समझौता किया है। 5 लाख व्यक्तियों को हम लेने को तैयार हैं, 3 लाख व्यक्तियों को श्रीलंका अपने यहां रखेगा, लेकिन शेष जो 2 लाख व्यक्ति हैं, उनकी क्या स्थिति होगी ?

इतना ही नहीं सुना गया है कि जिन 3 लाख लोगों का श्रीलंका की सरकार अपने यहां रखने को तैयार हो गई है, उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जायेगा और उन्हें दूसरे दर्जे की नागरिकता का अधिकार दिया जायेगा। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री हमें यह न बतायें कि चूंकि यह श्रीलंका का घरेलू मामला है, अतः वह कुछ नहीं कर सकते। माननीय मंत्री उनको इस भेदभाव से बचाने का प्रयत्न करें, यह मेरा निवेदन है।

आप इस करार के संबंध में 'मानवीय दृष्टिकोण' की बात कहते हैं। मेरा विचार है कि हर सरकार और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सामने देश का हित सब से बड़ी बात होती है। 'मानवीय दृष्टिकोण' की बात देश की जनता या विश्व की जनता के कल्याण के संबंध में लागू होती है, देश का हित उससे बड़ी बात है। यदि मंत्रालय इस बात की उपेक्षा करेगा तो उसके बारे में अनेकानेक कठिनाइयां पैदा होंगी।

मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वह श्रीलंका में रहने वाले उन भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाये जाने से बचायें। जिन लोगों को हमने श्रीलंका की सरकार के हाथ में छोड़ा है, उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव हम न होने दें।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : रूस की सरकार में परिवर्तन होने के बाद हमें आश्वासन दिया गया कि रूस की नीति में हमारे प्रति कोई परिवतन नहीं होगा, इसका हम स्वागत करते हैं।

ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्तारूढ़ हो गई। यह अच्छा लक्षण है। हम इसका भी स्वागत करते हैं।

अमरीका के चुनाव में श्री जानसन विजयी हुये। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें आशा है कि अमरीका और रूस के बीच मतभेद दूर करने के लिये श्री नेहरू ने जो प्रयत्न किया था, उसे आगे बढ़ाया जायेगा।

काहिरा सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री ने अपना सम्पर्क स्थापित किया और हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री ने अफ्रीकी-एशियाई देशों के बीच मित्रता बढ़ाने का प्रयत्न किया।

इस बीच सबसे अधिक चिन्ता की बात चीन द्वारा अणुबम का परीक्षण है। यह बम प्लटोनियम से बनाया गया हो, ऐसी बात नहीं है बल्कि चीन वाले यूरेनियम 238 से यरेनियम 235 अलभ करने में सफल हो गये हैं। ध्यान रहे कि भारत में उनका निशाना केवल 300 मील की दूरी पर है जब कि चीन में हमारा निशाना 2,000 मील की दूरी पर है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में गंटूर में विदेश नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पर मैंने एक संशोधन पेश किया था जिसका आशय था कि यदि देश पर विदेशी शक्ति का आक्रमण होगा और देश की अभिन्नता, एकता और स्वतन्त्रता को खतरा होगा, तो भारत अपनी रक्षा के लिए अणु शक्ति का प्रयोग करेगा।

मेरे इस संशोधन पर बड़ा हल्ला-गुल्ला मचा। तरह तरह से मेरी आलोचना की गई।

एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री की गुटों में शामिल न होने की जो नीति थी, उसका मैं अब भी समर्थन करता हूं। मैं शान्ति का पक्षपाती हूं। और इस सम्बन्ध में हम हमेशा श्री नेहरू के साथी रहे हैं।

जब अन्तरिम सरकार थी तो हमने सेनायें कम कर दी थीं। बाद में जरूरत के मुताबिक हमने सेनायें बढ़ायीं। हम किसी प्रकार की चढ़ाई नहीं करना चाहते परन्तु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सीमाओं पर हमारे पड़ोसी हमें नष्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले हमने अपना सैनिक व्यय सीमित रखा परन्तु बाद में चीन का आक्रमण होने के बाद हमने सेनायें खूब बढ़ाईं।

आज श्री कृष्ण मेनन जैसे मेरे मित्र कहते हैं कि अणु शस्त्र युद्ध का शस्त्र नहीं बल्कि नर-संहार का शस्त्र है। बहुत समय से हम ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं। मैं पूछता हूं कि यदि यह नर संहार का शस्त्र है, तो चाहे हमारा शत्रु यह शस्त्र बनाये लेकिन फिर भी क्या हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और ईश्वर न करे यदि इस देश पर शत्रु ने अणु शस्त्र से आक्रमण कर दिया, तो हम जमीन पर पड़े-पड़े यही कहते रहेंगे कि हम शान्ति चाहते हैं और इस प्रकार देश में नर संहार हो जाने देंगे ?

इसमें कोई संशय नहीं कि हम शान्ति के हामी हैं। हम किसी देश की आजादी या उसकी धरती छीनने के लिए अणु शस्त्र या किसी अन्य प्रकार का शस्त्र नहीं चाहते परन्तु मैं चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री आज साहस के साथ यह बात कहें कि भले ही हम शान्ति के इच्छुक हैं

परन्तु यदि शत्रु हम पर आक्रमण करेगा, तो हम देश की रक्षा के लिए अणु शक्ति का भी इस्तेमाल करेंगे । क्या यह पाप है ?

हम शान्ति चाहते हैं । पर किसके लिए ? इस देश की जनता के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए । यदि हमारे नाश का सामान तैयार हो, तो हम निश्चय ही उसे रोकने के लिए अणु बम बनायेंगे । भूत में हमने कभी भी अणु बम बनाने की बात नहीं सोची । अब चीन के पास अणु बम है । वह अब ताकत के साथ बात कर सकता है । माऊ अब एशिया और अफ्रीका के देशों को धमका और घुड़का सकते हैं । विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां केवल सैनिक शक्ति को मानती हैं । हमारी स्थिति एशिया में बड़ी हेय हो जायेगी । आज लोग कहते हैं कि अणु बम बनाने से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें जो समर्थन प्राप्त है, वह नहीं मिलेगा । लोग यह भी कहते हैं कि अणु बम बनाने का बड़ा खर्च भी हमारा देश नहीं उठा सकता । हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए हैं । बड़े-बड़े देश हमारे तर्क को समझ नहीं पाये हैं । हमें चाहिए कि हम चीन को राष्ट्र संघ में स्थान दिलायें ताकि वह उसके बाद ठीक ढंग से व्यवहार करे । एक ओर हम उसे राष्ट्रसंघ में स्थान नहीं दे र हैं और दूसरी ओर हम उससे निरस्त्रीकरण करार पर हस्ताक्षर करने की मांग करते हैं । यह कोई तर्क है ? संसार के बड़े राष्ट्र हमसे कहते हैं कि हम अणु शस्त्र न बनायें और समय पड़ने पर वे हमारी रक्षा करेंगे । अतः मैं समझता हूं कि भारत को प्रयत्न करके चीन को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना चाहिए ताकि उसे तर्क से बात समझाई जा सके । अन्यथा चीन इसी प्रकार बम बना कर परीक्षण करता ही जायेगा ।

मैं अणु शस्त्र परीक्षण रोक करार की धारा 4 का उल्लेख करना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि कोई भी देश असाधारण स्थिति में, यदि वह समझता है कि इस करार से उसका राष्ट्रीय अहित हो रहा है, इससे त्याग पत्र दे सकता है । तीन महीने पूर्व सूचना देकर वह इससे अलग हो सकता है । अर्थात् जिन देशों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं, वे भी विशेष स्थितियों में इससे अलग हो सकते हैं ।

चीन अणु बम किसके लिए बना रहा है । एक तो वह एशिया और अफ्रीका के देशों को दबाने के लिए और दूसरे भारत को हड़पने के लिए अणु शस्त्र बना रहा है,—रूस, अमरीका या अन्य देशों के लिए नहीं । चीन जानता है कि राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भारत ही उसका समकक्षी और सब से बड़ा शत्रु है और सामान्य सेना से वह भारत को जीत नहीं सकता, इसीलिए उसने अणु बम बनाया है ।

हमारे रक्षा मंत्री ने लन्दन में अपने वक्तव्य में कहा था कि अणु शस्त्रों का प्रयोग कोई स्थानीय बात नहीं रहेगी बल्कि इनके प्रयोग से विश्वव्यापी युद्ध हो जायेगा और भारत को उसके सभी शक्तिशाली साथियों का सहारा है ।

क्या मित्रों की सहायता के बल पर भारत अपनी रक्षा के लिए आश्वस्त हो सकता है । क्या हम रूस पर भरोसा कर सकते हैं ? अतः श्री मसानी की बात ठीक होगी कि हमें अमरीका से आणविक-रक्षा करार कर लेना चाहिए । विश्वव्यापी युद्ध क्या है ? चीन भारत पर आक्रमण करेगा, और यदि अमरीका हमारी मदद करेगा, तो वह चीन पर आक्रमण कर देगा । इस प्रकार एशिया के इस भाग पर अणु बमों का विस्फोट होगा । विश्वव्यापी युद्ध का अर्थ यह नहीं है कि अमरीका और रूस आपस में लड़ने लगेंगे । यह युद्ध तो भारत और चीन के पठारों पर ही केन्द्रित होगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि श्री नेहरू के काल में हमने अतिस्वन सुपरसोनिक विमान तथा स्वचालित राइफलें क्यों मंगाईं ? क्या ये पुराने हथियारों से अधिक खतरनाक नहीं हैं ? क्या अब हम अपनी रक्षा व्यवस्था पर 500 करोड़ नहीं खर्च कर रहे हैं ? हमें देश की रक्षा के लिए मजबूर होकर इतना खर्च सेना व्यवस्था पर करना पड़ रहा है ।

आज के अखबार में हमारे प्रधान मंत्री का वक्तव्य छपा है जिसमें कहा गया है कि भारत शान्ति पर विश्वास करता है परन्तु हमारी शान्ति का मतलब कायरता नहीं है । उनके शब्दों पर कृपया ध्यान दें, "भारत तभी शान्ति को बढ़ावा दे पायेगा जब वह शत्रु से कह सके कि हम उसको मुंह तोड़ उत्तर दे सकते हैं ।"

मैं इस बात से सहमत हूं और इसी प्रकार हम शान्ति बनाए रख सकते हैं । हमें अपनी सेनाओं को अधिक सुदृढ़ बनाना होगा । अतः मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार यह बात स्पष्ट रूप से कहे कि यद्यपि हम शान्ति चाहते है लेकिन यदि हमारे देश की अखण्डता और आजादी पर आक्रमण हुआ, तो हम देश की रक्षा के लिए हर प्रकार से अणु शक्ति का सहारा लेंगे ।

काश्मीर के मामले में पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध और नागालैंड के सम्बन्ध में मुझे एक-दो शब्द कहने हैं । पाकिस्तान हमारी युद्ध विराम रेखा पर आक्रमण करता रहा है । हमें पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि काश्मीर भारत का अंग है और हम इस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते । अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के प्रश्न पर हम हीलाहवाला क्यों कर रहे हैं ? श्री सादिक साहब का दृष्टिकोण भी अनुच्छेद 370 के बारे में अब बदल गया है । शेख अब्दुल्ला बहकी बहकी बातें करते हैं और भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल उनके विरुद्ध नहीं किया जा रहा है । हमें स्थिति को सुधारना चाहिए । मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 370 को तुरन्त समाप्त कर दिया जाये ।

यह बात सभा में कही जा चुकी है कि नागालैंड का मामला हमारा घरेलू मामला है । इस मामले को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के हाथ से ले लिया जाये और या तो यह गृह कार्य मंत्री के या प्रधान मंत्री के अधीन रखा जाये । श्री माइकेल स्काट फिजो के प्रतिनिधि हैं । उन्होंने भारत को खंडित करने की बात कही है । उन्हें देश से निकाल दिया जाना चाहिए । श्री जयप्रकाश नारायण ने जो बातें कही हैं, वह भी उचित नहीं हैं । शान्ति वार्ता आगे बढ़ाई जाये परन्तु साथ ही ध्यान रखा जाये कि देश से उसको अलग करने या संविधान में संशोधन करने की कोई बात न कही जाये ।

हमें आशा है कि हमारी सरकार नागाओं तथा पाकिस्तान के साथ दृढ़ दृष्टिकोण अपना कर समस्याओं को हल करेगी ।

श्री नाथ पाई (राजापुर): श्रीमान्, सर्व प्रथम मैं श्री ग्रेसन किर्क द्वारा कही गई एक बात का उल्लेख करूंगा । उन्होंने कहा है कि सभी देशों में वैदेशिक मामले घरेलू मामलों की तुलना में अधिक आन्दोलन का विषय बन जायेंगे ।

मैं वैदेशिक कार्य मंत्री के साथ ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का स्वागत करता हूं । सत्ता संभालते ही उन्होंने ब्रिटेन की नौसेना और फ्रांस के साथ होने वाले कार्यक्रम को रोक दिया । उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हथियार देना बन्द कर दिया । ये बातें अच्छी हैं । मुझे आशा है कि वे स्वतन्त्रता और शान्ति को बढ़ावा देंगे ।

अमरीका में असहिष्णु और दुस्साहसी तत्वों की पराजय भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए बड़े उत्साह की बात है। रूस में भी परिवर्तन हुए हैं। भारत सरकार को पूरे साहस से इन परिवतनों के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करना चाहिए। श्री ख्रुश्चेव को भारत अपना विश्वसनीय साथी समझता था। उन्होंने स्टालिनवाद को दबाया और शान्ति तथा सह-अस्तित्व की भावना को शक्ति प्रदान की। ख्रूश्चेव के पतन पर भारतीय प्रवक्ताओं की चुप्पी अच्छी नहीं लगी।

मास्को में जो कुछ हुआ है, उसके सम्बन्ध में श्री शास्त्री की सरकार यदि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी, तो रूस के नये नेता शायद इसे पसन्द नहीं करेंगे। वैदेशिक नीति की जान केवल एक ही सिद्धान्त पर निर्भर है : और वह है साहस और निर्भयता।

हममें पर्याप्त आत्म सम्मान और आत्म स्वाभिमान होना चाहिए। रूस के नेताओं से हमें यह नहीं पूछना चाहिए था कि वह हमारे साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध रखेंगे या नहीं। जहां हम दूसरों से मैत्री भाव चाहते हैं, वहां दूसरे भी हमसे मित्रता चाहते हैं। होना यह चाहिए था कि रूस के नेता स्वयं हमसे कहते कि वे हमारे साथ मैत्री सम्बन्ध रखेंगे।

काहिरा सम्मेलन में श्री शास्त्री की महान सफलता की बात कही गई पर मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि श्री शास्त्री और उनके साथी चाहते हैं कि पड़ौसी देशों के साथ मित्रता बढ़ाई जाये।

काहिरा सम्मेलन के बारे में कहा जाता है कि भारत को इसमें बड़ी सफलता मिली। पर क्या यह बात सही है ? हमारी सरकार तो केवल प्रेस विज्ञप्तियां जारी करके ही यह समझ लेती है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह सब से बड़ी सफलता है। बहुत सी प्रेस विज्ञप्तियां जारी करते रहना इस सरकार की आदत है। लेकिन दुःख की बात है कि सरकार इन्हें सफलता की कसौटी मानती है। काहिरा सम्मेलन में जो विज्ञप्तियां जारी की गईं उनमें भारत पर आक्रमण करने पर चीन की कोई निन्दा का उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत श्री शास्त्री से इजराइल की निन्दा कराई गई। यदि अरब गणराज्य इजराइल को अपना शत्रु समझता है, तो भारत चीन को अपना शत्रु मानता है। यह तो पारस्परिक आदान-प्रदान की बात है। हमारे प्रधान मंत्री को चीन के आक्रमण की समस्या की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विज्ञप्ति में चीन के आक्रमण का तो जिक्र भी नहीं है लेकिन इजराइल की निन्दा की गई है। इससे तो हम लोगों की सद्भावना को खो बैठेंगे।

हमें विदेश नीति को दृढ़ता से चलाना है। यदि किसी देश से हमारा कोई झगड़ा नहीं है तो मैं उसकी निन्दा नहीं कर सकता। हमारे प्रधान मंत्री प्रेसीडेण्ट नासिर को तो इस बात के लिए राजी करते कि विज्ञप्ति में भारत पर चीनी आक्रमण का उल्लेख होना चाहिए। यहां तक कि उस विज्ञप्ति में भारत की किसी भी समस्या का जिक्र नहीं है। हमें बड़े साहस से अपनी नीतियों पर चलना चाहिए चाहे लोग हमारी कुछ निन्दा ही क्यों न करें।

श्री शास्त्री ने वहां प्रस्ताव रखा था कि एक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा जाये। इसका विरोध किया गया और प्रस्ताव दबा दिया गया। हमारे विदेश मंत्री को इस बात पर आग्रह करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि हम यह अपनी मातृभूमि के हितों की रक्षा के लिए आये हैं। उन्हें सम्मेलन के अध्यक्ष, से कहना चाहिए कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई, तो वह इसके विरोध में सम्मेलन का बहिष्कार करते हैं। लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने

अपने तथा देश के स्वाभिमान को नष्ट होने दिया और इतना कहने का साहस नहीं किया। दूसरे लोग जानते हैं कि भारत की कमजोरी का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

अब मैं अफ्रीका की बात लेता हूं। वहां के देश धीरे-धीरे बड़ी बहादुरी से स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं। उनको देख कर मुझे खुशी होती है। अफ्रीका से हमारे देश के लोग निकाले जायेंगे और हमारी सरकार ने बस थोड़ा सा विरोध मात्र किया है। क्या हमारी विदेशी नीति की यही सफलता है ?

मैंने जंजीबार का प्रश्न आज उठाने की कोशिश की थी। वहां भारतीयों ने एक खास जलूस में भाग नहीं लिया। बस इतनी सी बात पर उनका कारबार बन्द किया जा रहा है। कोई देश भारतीयों के साथ ऐसी ज्यादती करे, यह हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के लिए चुनौती है।

श्रीलंका के साथ जो करार हुआ है, उसका स्वागत इस दृष्टि से है कि यह समस्या काफी दिनों से अटकी हुई थी और अब हल हो गई है। किसी भी समस्या को हल करने का उचित मूल्य तो हम दें, लेकिन किसी ज्यादती को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीलंका की सरकार से हमें कहना चाहिए कि वह वहां रहने वाले भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक न बनायें। श्री स्वर्ण सिंह ने कहा कि यह उनका घरेलू मामला है और हम उनसे अपनी इच्छा के मुताबिक हर काम नहीं करवा सकते। छः या आठ लाख व्यक्तियों की इच्छा की परवाह न करके सरकार ने यह करार किया है। हमने रंगभेद की नीति का सदैव विरोध किया है; लेकिन हमें लगता है कि श्रीलंका में भारतीयों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जायेगा। हमें इस मामले में अपने सिद्धान्तों की बलि नहीं दे सकते। जहां हम अपने पड़ोसी राज्यों की प्रभुत्ता का सम्मान करते हैं, वहां हम यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाये। आज यदि ऐसा हुआ, तो कल मेडागास्कर, मौरीशस या ब्रिटिशगाइना में रह रहे भारतीयों के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम कब इतना साहस इकट्ठा कर पायेंगे कि हम दुनियां को बता सकें कि भारतीय होना कोई पाप नहीं है।

पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर रहा है, इसका उल्लेख हमारे रक्षा मंत्री और उपमंत्री दोनों कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं जानता कि चुनाव में श्री अयूब को विजयी बनाने के लिए लोगों का ध्यान भारत की ओर खींचने हेतु यह सब हो रहा है। मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता है पर हम यह दोस्ती अपना राज्य-क्षेत्र देकर नहीं बनाये रखना चाहते। यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि हम भूमि का कोई हिस्सा पाकिस्तान को देकर यह दोस्ती नहीं चाहते।

मैं इस बात का विरोध करता हूं कि नागालैंड को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन रखा जाये। नागालैंड के लोग हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री की देखभाल में रहना चाहते थे न हमारे देश के किसी भी वैदेशिक कार्य मंत्री के अधीन। जैसाकि आप गोवा के सम्बन्ध में किया है, नागालैंड को भी गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन कर दें। वर्तमान स्थिति में लोगों के मन में शंका और गलतफहमी पैदा होती है। इस देश के टुकड़े-टुकड़े होने की कहानी हम देख चुके हैं। हम सब प्रकार का समझौता चाहते हैं पर हम मातृभूमि को खंडित करने की बात नहीं मान सकते।

चीन द्वारा अणुबम विस्फोट का प्रश्न हमने 3 तारीख को सभा में उठाया था। सरकार को इसके बारे में ठीक जानकारी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय के कहने पर सरकार ने एक वक्तव्य दिया। वह वक्तव्य बिल्कुल थोथा था। सरकार ने कहा कि चीन में जो कुछ हुआ है वह चिन्ता की बात है लेकिन बम विस्फोट हमारे लिए कोई बड़ी चिन्ता की बात नहीं है। सरकार एक ही वाक्य में कहती है कि चिन्ता की बात हैं भी, और नहीं भी है। सरकार महत्वपूर्ण मामलों के सम्बग्ध में कितने गलत ढंग से सोचती है ? इतना कहनेसुनने के बाद सरकार ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। जब रूस ने अणुबम का विस्फोट किया था, तो अमरीका के प्रेसीडेण्ट ट्रूमैन ने कुछ ही घण्टों बाद वहां की कांग्रेस को इसके बारे में बताया था। हमारे देश को तो अभी यह पता भी नहीं है कि वह बम कैसा था, उसमें क्या चीजें थीं और कहां उसका विस्फोट किया गया ह।

इसके बजाय कि अब हम बैठ कर शान्त ढंग से इस बात का अध्ययन करें कि चीन की शक्ति कितनी बढ़ गई हैं, हम बकार में महात्मा गांधी, श्री नेहरू, अशोक और बुद्ध के नाम की आड़ ले रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं सरकार और इस सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर दूरदर्शिता के साथ विचार करे। भारत, एशिया और सम्पूर्ण विश्व के दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रख कर इस पर विचार करे।

चीन के मार्शल चेन ई ने कहा है कि चाहे हमें नंगे-भूखे रहना पड़े लेकिन हम बम जरूर बनायेंगे। वहां के एक अन्य मार्शल ने कहा है कि युद्ध का मुख्य उद्देश्य शत्रु को बिल्कुल नष्ट करना है। चीन केवल खिलौना नही बना रहा है वह शत्रु के लिए बम बना रहा है। चीन की विदेशी नीति का मुख्य आधार उनकी राष्ट्रीयता, युद्धप्रियता ही हैं।

श्री मसानी ने व्यर्थ ही सैद्धान्तिक बातें उठाईं। जब लार्ड पालमर्सटन से पूछा गया कि क्या टर्की उनका स्थायी साथी देश है, तो उन्होंने कहा था कि इंगलैंड का कोई स्थायी साथी: कोई स्थायी दुश्मन नहीं है बल्कि स्थायी तो उसके हित ही हैं। यही विदेशी नीति का आधार है और चीन इस नीति को खुल्लमखुल्ला मानने में कोई शर्म नहीं महसूस करता।

मैं श्री विद्या प्रकाश दत्त द्वारा लिखी हुई पुस्तक चाइनाज़ फारेन पालिसी का एक उद्धरण मैं आपको देना चाहता हूं। लेखक ने बताया ह कि चीन के नेता चीन को विश्व की महान शक्ति बनाना चाहते हैं। वे अपने देश को रूस, अमरीका और ब्रिटेन के समान बनाना चाहते हैं और इसके लिए हर संभव बलिदान व त्याग करने के लिए तैयार हैं। चीन के वर्तमान नेता माओ त्से तुंग चीन के सम्मान के संबंध में बहुत अधिक सावधान है। अत: चीन की शक्ति के संबंध में हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। चीन वाले कहते हैं कि उनका देश विश्व का केंद्रीय साम्राज्य है। यदि विश्व का नहीं तो कम से कम एशिया का तो वह अपने को प्रभाव केन्द्र मानते हैं। और अब चीन के पास अणुबम हो गया है, अत: हमें उस की शक्ति के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

श्री मसानी ने कहा कि या तो आप चीन के दबाव में आ जायें या अमरीका से अणुबमों की रक्षा सहायता स्वीकार करें—यही दो रास्ते हैं।

श्री मसानी शायद समझते हैं कि यदि हम अमरीका से अणुबम रक्षा-सहायता मांगेंगे, तो वह हमें मिल जायेगी। यदि अमरीका पर उन्हें इतना विश्वास है, तो वह अमरीका को इस बात पर राजी करें कि वह हमें एफ–104 फाइटर विमान दे, जो अमरीका ने हमें देने से

[श्री नाथ पाई]

इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान को इसमें आपत्ति थी। हमें 130 परिवहन विमानों की बड़ी ज़रूरत है क्यों न श्री मसानी अमरीका से इनकी मांग करें। पाकिस्तान के विरोध के कारण अमरीका हमें यह भी नहीं देगा। श्री मसानी शायद धोके में हैं। मेरा विचार है कि यदि हम अमरीका से मांगेंगे, तो भी हमें अणुबम नहीं मिलेगा।

चीन भारत, बर्मा तथा एशिया के अन्य देशों को इस अणुबम के बल पर धमकायेगा और अपनी बात उनसे मनवाने की कोशिश करेगा। इसका एक उदाहरण यह है।

किसी भी एशियाई राष्ट्र ने इस बात पर चीन की निन्दा नहीं की कि उसने परमाणु बम बनाया है। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है। और इधर जो भी नेता उठता है यही कहता है कि हम बम नहीं बनायेंगे। बार बार इस बात को दोहराया जाता है, मानो यह कोई धमकी हो जिस से चीन वाले डर जायेंगे। यह वैसी ही बात हुई जैसे श्री नेहरू चीन के हमले के समय कहा करते थे कि हम बातचीत करने से पीछे नहीं हटेंगे। शायद वे समझते थे कि ऐसी घोषणा करने से चीनी डर जायेंगे लेकिन कुछ हुआ नहीं और हमें करारी हार खानी पड़ी। ठीक नीति तो यह थी कि हम साफ कह देते कि हम चीन के अणुबम से डरेंगे नहीं बल्कि उसके मुकाबिले के लिए जो भी उचित होगा करेंगे।

श्री मसानी अणुबम के निर्माण के भारी खर्चे की चर्चा करके हमें डरा रहे हैं। लेकिन यदि हमें आज़ाद रहना है तो उस आज़ादी की कीमत देनी पड़ेगी। अपनी रक्षा की जिम्मेदारी हमें स्वयं निभानी पड़ेगी; उसे उम किसी और के कन्धों पर नहीं डाल सकते। यही क्या निश्चित है कि कल को अमरीका चीन के साथ समझौता नहीं कर लेगा जैसाकि उसने रूस के साथ किया है।

हमें अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए और संसार में शान्ति की आशाओं की आड़ में मुंह नहीं छिपाना चाहिए। सभी गांधी नहीं हो सकते लेकिन जो भी प्रधान मंत्री बनता है—वह गांधी बनने की भी चेष्टा करता है। गांधी तो एक शताब्दी में एक ही होता है बाकियों को हिम्मत से काम लेकर देश की रक्षा करनी है। डा० भाभा ने कहा है कि 10 लाख टन टी० एन० टी० का बम 17 लाख में बन सकता है। हमें चीन पर बम नहीं फेंकना है लेकिन उसे यह अवश्य बताना है कि हम खाली हाथ नहीं हैं। आशा है कि सभा अहिंसा के सिद्धान्त के प्रति झूठी भक्ति से प्रेरित नहीं होगी बल्कि अपनी रक्षा के कर्त्तव्य को सामने रखेगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : पिछले दो तीन महीनों में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव से स्पष्ट है कि वहां की जनता युद्ध से बचना चाहती है।

प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन के चुनाव के बाद एक वक्तव्य में कहा है कि महत्वपूर्ण मामलों में ब्रिटेन और भारत की नीति एक सी है। मैं चाहता हूं कि वे अपने इस वक्तव्य पर और प्रकाश डालें और बताएं कि इस का मतलब क्या है। मैं तो समझता हूं कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान के साथ सदा पक्षपात किया है और उस से हमारे लिए समस्या आ खड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का साथ दिया और हमें बदनाम किया।

प्रधान मंत्री हमें यह भी बताने की कृपा करें कि ऐसा क्या संकट आ पड़ा है कि संसद् के सत्र के दौरान वे ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं।

हम 1947 से ही पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने की चेष्टा करते रहे हैं। हम ने सीमा से बाहर जा कर पाकिस्तान की मित्रता प्राप्त करने की चेष्टा की है। हम ने 50 करोड़ रुपया गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान को दिया जबकि हमें उससे जो लेना था, अभी बकाया है। नहरी पानी के बारे में भी हमने उसे रियायतें दीं लेकिन वह खुश नहीं हुआ।

कश्मीर के सम्बन्ध में हमें पाकिस्तान से क्या बात करनी है? मैं श्री कृष्ण मेनन से सहमत हूं कि पाकिस्तान से यही बात करनी है कि वह कश्मीर का इलाका छोड़ दे। यह बात हमें पूर्णतया स्पष्ट कर देनी चाहिए कि क्योंकि अनिश्चित बातें कहने से भ्रम फैलता है। सरकार को अपना रवैया स्पष्ट कर देना चाहिए।

जहां तक चीन द्वारा अणुबम के विस्फोट का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं कहता कि हम डर जायं लेकिन जो हुआ है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। अणुबम के विस्फोट से तो अमरीका जैसे बड़े देश को भी चिन्ता हुई है। हमारे नेता कहते हैं कि जनता का मनोबल अणु और उद्जन बमों पर भारी है। मुझे तो ऐसे नेता दिखाई नहीं देते जो देश में वैसा मनोबल और साहस पैदा कर सकें। और फिर अणु बम के आगे कोरा मनोबल क्या करेगा? जापान को देखिए, हीरोशिमा पर गिरे बम ने उस की कमर तोड़ दी थी।

सवाल यह है कि अणुबम बना सकने वाले देश भारत को वही स्थान देंगे जो कि वे अणुबम वाले राष्ट्रों को देते हैं? हम चाहे जितनी कोशिश करते रहें कि अणुबमों का निर्माण बन्द हो जाय, इस बात की आशा नहीं है कि चीन इस बात को मान जायगा।

हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। भारत में शूरवीरों की कमी नहीं रही लेकिन अच्छे हथियारों ने उन को मात दी है। चीनी आक्रमण के समय भी हम वैसी ही बातें किया करते थे जैसी कि आज कर रहे हैं। यदि उस समय हम ने अपनी सेना को सुसज्जित करने के लिए 100 करोड़ का खर्च भी कर दिया होता तो हमारी यह हालत न होती जैसी कि हुई।

आप यह भी सोचें कि भारत पर चीनी आक्रमण का प्रभाव अन्य छोटे राष्ट्रों पर क्या पड़ा? अणुबम बना लेने से चीन इस स्थिति में हो गया है कि उन देशों के हौसले और पस्त कर सके।

कुछ मित्र कहते हैं कि हम अमेरीका पर भरोसा कर सकते हैं। मैं पूछता हूं कि यदि रूस अमरीका से कहे कि "तुम भारत-चीन विवाद में पड़े तो हमें भी उस में कूदना पड़ेगा, इसलिए तुम अलग रहो" तो क्या अमरीका हमारी खातिर रूस के साथ अणुबमों से लड़ेगा?

मास्को में अणुबमों के प्रयोग न करने के बारे में एक समझौता हुआ लेकिन रूस के विदेश उपमंत्री ने हाल ही में बंगलौर में भाषण देते हुए चीन-द्वारा बम विस्फोट की प्रशंसा की। तो क्या यह उस समझौते का उल्लंघन नहीं था? इस हालत में हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाएं तो कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि फ्रांस और रूस भी इस का विरोध करेंगे।

[श्री हरीशचन्द्र माथुर]

हमारा नैतिक कर्त्तव्य अपने देश की रक्षा करना है और इसलिए ठीक नीति वही है जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। और किसी प्रकार की नैतिकता का प्रश्न नहीं उठता है।

हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने डा० भाभा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अणुबम की लागत सम्बन्धी आंकड़े दिए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये अनुमान एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमरीकी प्रतिनिधि ने बताए थे। इसलिए हमें कोई बात छिपानी नहीं चाहिए और सारी स्थिति देश के सामने रख देनी चाहिए।

आशा है कि रूस की नई सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी और हमारे प्रति उनका रवैया पूर्ववत रहेगा।

श्री फ्रैंक एन्थोनी (नामनिर्देशित–आंग्ल भारतीय) : मैं चीन द्वारा अणुबम के विस्फोट और भारत के लिए उस के गंभीर परिणामों की ही बात करूंगा। इस विस्फोट से हमें आतंकित तो नहीं होना चाहिए लेकिन साथ ही आत्मतुष्ट हो कर भी नहीं बैठे रहना चाहिए।

मैं उन में से हूं जो यह समझते हैं कि नेफा में हमारी करारी हार इसलिए हुई कि भारत सरकार बड़े खतरनाक भ्रम में पड़ी हुई थी। मुझे पता चला है कि भूतपूर्व प्रधान सेना-पति कई वर्ष पहले प्रधान मंत्री के पास गए और कहने लगे कि भारत को आटोमैटिक हथियारों की ज़रूरत है तो उन्होंने पूछा कि कितना खर्च होगा। जब उन्हें बताया गया कि 50 से 100 करोड़ रुपये तक का खर्च होगा तो वे चिल्ला कर बोले—यदि हमें लड़ना पड़ा तो हम साहस से और लाठियों से लड़ेंगे। नेफा में हमारी हार का यही कारण था। और उस हार से हमें यही पाठ मिला है कि आज के युग में लाठियों और ·303 राइफलों से लड़ने की बात सोचना खतरनाक मूर्खता होगी।

आज चीन द्वारा अणुबम के विस्फोट से हमारे सामने वैसी ही स्थिति है जैसी कि उस भूतपूर्व प्रधान सेनापति के सामने थी। आज हम जो हथियार बना रहे हैं वे पुराने पड़ जायेंगे और हमारी सेना के जवान बलि के बकरे बन कर रह जायंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने प्लुटोनियम बम का विस्फोट नहीं किया बल्कि यूरेनियम 237 का उपयोग किया है जो कि अणुबम से कहीं अधिक घातक होता है। समाचार है कि आज चीन इस यूरेनियम का बहुत बड़ा कारखाना बना रहा है जिस से कि बड़े पैमाने पर अणुबम बन सकें। लेकिन इस से भी अधिक चिंताजनक समाचार यह है कि वह थोड़ी दूर तक मार करने वाले राकेट बना रहा है जिन में नाभिकीय वारहैड हैं। वे भारत के विरुद्ध ही प्रयुक्त होंगे, हमें यह समझ लेना चाहिए।

चीन के पास 2000 मील तक मार करने वाले विमान भी हैं और कम दूरी वाले भी ? तिब्बत में उनके अड्डे हैं और वहां से उड़ान कर के वे भारत के किसी भी नगर को नष्ट कर सकते हैं। आज चीन तोपों के गोलों में भी अणुबम की सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। इस हालत में पुराने ढंग की 10 लाख की सेना उनका क्या बिगाड़ लेगी ?

मुझे सरकार और देश की कठिनाइयों का पता है। मैं जानता हूं कि अणुबम का खर्चा हमारी कमर तोड़ सकता है। पहले ही लगभग एक हजार करोड़ रुपये के सैनिक खर्चे ने मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें साम्यवाद पनपेगा और अव्यवस्था फैलेगी।

तो इस स्थिति में हम क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और फिलोस्फी छांटते रहें। अणुबम के विस्फोट की निन्दा करते रहें और चेष्टा करते रहें कि दूसरे राष्ट्र भी वैसा ही करें? काहिरा सम्मेलन में अरब गणराज्य और घाना को छोड़ किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। बाकी राष्ट्र मुंह बाए देखते रहे। आखिर उन की चुप्पी का क्या कारण था। मैं समझता हूं कि दो कारण थे। पहला मनोवैज्ञानिक, वह यह कि काले राष्ट्रों को इस बात से सन्तोष हुआ कि अणुबम के क्षेत्र में गोरे देशों का एकाधिपत्य चीन ने तोड़ दिया और दूसरा कारण यह था कि इन राष्ट्रों का दृष्टकोण व्यावहारिक हो। वे भारत की तरह फिलोस्फी बघारने में विश्वास नहीं रखते।

कहा जाता है कि अरब गणराज्य नाजी वैज्ञानिकों की सहायता से अणुबम बनाने की कोशिश में है और इसे कुछ सफलता मिली भी है और उधर पश्चिमी जर्मनी ने ऐसा नया आविश्कार किया है जिससे—यदि उस का पता चल गया—छोटे से छोटा राष्ट्र भी आसानी से अणुबम बना सकेगा जिस में खर्च भी कुछ अधिक नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई जिम्मेदार कैसे विश्वास करेगा कि उपदेश देने से दूसरे राष्ट्र अणुबम बनाने से बाज़ आएंगे। कल फ्रांस ने बनाया, आज चीन ने तो कल और परसों अरब गणराज्य, जापान और घाना भी बम बना लेंगे। इसलिए हमें यथार्थ का सामना करना चाहिए नहीं तो हमारी हालत वैसीं ही होगी बल्कि उस से भी बुरी, जैसी नीफा में हुई।

तो अब करना क्या चाहिए? इस का उत्तर आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें अणुबम बनाने की होड़ में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि खर्चा बहुत आएगा और साथ ही हमारे पास ऐसे विमान नहीं हैं जिन से हम चीन पर वह बम फैंक सकें। अमरीका भी किसी देश की मदद के लिए तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उस के साथ सन्धि न हो। इसी कारण ब्रिटेन ने भी फैसला किया है कि अणुबम बनाने का खर्च उठाने की बजाय सुरक्षा सन्धि करना अधिक उत्तम है।

लेकिन यह सोचना गलत होगा कि सुरक्षा सन्धि का मतलब यह होगा कि उस पर हस्ताक्षर करने वाले देश अपनी प्रभुसत्ता का परित्याग कर देंगे। हमें अपनी पुरानी नीति के दल दल से निकल कर नयी दिशा लेनी चाहिए और अणुविज्ञान का विकास करना चाहिए।

आज की स्थिति में हम 18 महीनों से पहले अणुबम नहीं बना पाएंगे। उस के लिए 1000 करोड़ रुपये के खर्च की आवश्यकता होगी। हमें अपना सैनिक खर्च घटाना चाहिए और वह तभी हो सकता है जब कि हम किसी सुरक्षासंघ के सदस्य हो जायं।

मैं प्रधान मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पड़ौसी देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की नीति अपनाई है। हमें मलेशिया और जापान के साथ भी अपने सम्बन्ध सुदृढ़ करने चाहिएं। तब हम चीन के खतरे का सामना भली प्रकार कर सकते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : The first thing I would like to submit is that simultaneous interpretation system should be provided for the press gallary also so that there is no room for misunderstanding in regard to speeches in Hindi.

The Government of our country has lost all prestige; it also had to give up large chunks of our territory. What is the reason; to my mind it is the fact that we never go to the root of the matter. That is why all the proclamations of our Government have lost their value. Another thing is that the proclama-

[Dr Ram Manohar Lohia]

tions are self-contradictory. On the one hand the Ministers say that we would not enter into any agreement with China except on the basis of the return of our territory and, of course, honour. They also have no hesitation, when the occasion demands it, in saying that peace and amity does entail some give and take.

May I submit that there would not be any question of taking some thing from China. But by mentioning the question of give and take we go back on our word and nobody believes us. Not only the other countries of the world have lost faith in the word of our Government even the people of India have no faith in what is said by the Government.

The malady from which our country suffers is that there is no sanctity in what we say; that is the basic defect in our foreign policy.

Our neighbours like Nepal, Bhutan and Sikkim have been exploiting our kindness because we do not have a definite policy and our Government wants and tries to buy their loyalty by generous economic help. That is true in the case of Kashmir, NEFA and Sikkim.

I would like to reiterate that the Government have lost all principles and their policy is completely without any direction. It is clear from the fact that in spite of their having come to know of the building of the Aksai Chin road by the Chinese as far back as 1951 they continued to say that China had deceived us.

An atomic bomb might cost only Rs. 17 lakhs—in this connection various figures have been quoted—but what we have to consider is the huge cost that the construction of an atomic bomb factory would involve. We should not forget that this is the same country where four years were spent on developing a solar cooker which did not prove to be a commercial sucess. The scientists instead of investigating into the nature of the rays of the sun tried to harness them for heating purposes and even in that they failed.

We have no proper industrial base nor the will to fight. In spite of the fact that we have lost so much of territory to the Chinese the Government is vaccilating. I do not mean to say that we should make war upon China; with the type of emasculating policy that the Government had been following during the last 17 years the country totally unprepared to wage a war. But what irked one was the fact that the Government is sitting with its fingers crossed; on the other hand it is pleading the cause of China in the U.N.O. There is no likelihood of our ever manufacturing an atomic bomb; even if we did a little friendly gesture from the side of China would make us give up the bomb. We should stop pleading the cause of China and should make it clear to her that she has turned into a monster for the world just like Hitler and Mussolini.

The trouble is that we only see the black side of the Chinese monster. It has a white side too. We are liable to lose sight of the fact that China has become the spokesman of the 200 crores of coloured peoples in the eyes of the world. The Government of India has been unable to realise the dangerous potentialities of China. They must see that the mere setting up of a transmitter here and there so that we can carry on propaganda against the Chinese is not going to matter. We must go to the root of the matter. We are a country with the lowest industrial productivity in the world; unless we are able to break the industrial imperialism of the white nations we would not succeed in our aims.

India would also have to find a solution to the problem of international imperialism.

India is still industrially backward and so long as we do not have a strong industrial base there would be no meaning in talking about the manufacture of an atom bomb. The Government fails to tell us the place India has in industry; it was 18th in the world when the British were our masters.

There was not a single word in the speech of the Minister for External Affairs which might give an indication of the mind of the Government; his opening speech was a mere adumberation of what he supposed to be our achievements in the international field. There was nothing constructive in his speech. The Prime Minister said that the Government formulated policies ; what policies did he mean? The various pronouncements about what was supposed to be policy were so vague and self-contradictory that they led one to suppose that the Government was completely oblivious of realities.

There was no assurance from the new Soviet Government about continued aid to us. Whatever aid they were giving was perfunctory and delayed. In fact we are not getting any aid either from the U.S.A. or from the U.S.S.R.

The Government claims to be a revolutionary government but their revolutionary spirit was limited to copying U.S.A. in the pattern of consumption and U.S.S.R. in the matter of international policies. This type of 'touch revolution' would not do. The Government had never been revolutionary; they had been stuck up in the ideological quagmire. If we want to be revolutionary we must follow U.S.S.R. in the matter of production and consumption and imitate America in international affairs. We must bring an economic revolution in the country as it had been wrought in the U.S.S.R. To imitate America does not, in my view mean, becoming its satellite but to see that freedom and democracy was saved throughout the world.

Our foreign policy can be revitalised only when it has some firm ideological basis. A recent example is the failure of the Government, despite the promises made by the Minister of External Affairs; to raise the question of South Africa in the Cairo Conference. The Government must take a lead in the matter of disarmament. Pious declarations in favour of peace would not suffice.

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमुंद) : चीन द्वारा अणुबम का विस्फोट बिल्कुल अप्रत्याशित था लेकिन यह आशा नहीं थी कि इस के प्रति सरकार की प्रक्रिया इतनी विचारहीन होगी। गृह मंत्री के अतिरिक्त और किसी को इस मामले की सूचना ही नहीं थी और प्रधान मंत्री बोले तो उन्होंने झट कह दिया कि हम अणुबम नहीं बनायेंगे। यह बड़ी हैरानी की बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस महत्वपूर्ण मामले पर और विचार करे और उसके बाद फैसला करे।

इण्डोनेशिया ने कहा है कि वह भी अणुबम बनाना चाहता है। इसमें हैरानी की बात नहीं क्योंकि चीन की तरह छोटे छोटे एशियाई देशों में भी अणुबम बनने लगेगा। अगर पाकिस्तान ने भी अणुबम बना लिया तो सरकार क्या करेगी ? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि पाकिस्तान इसे हमारे विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करेगा। विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि अगली दशाब्दी में सभी देशों के पास अणुबम होगा। फिर हमारे लिए अणुबम बनाना अनिवार्य हो जायगा।

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

हम चीन से अपना क्षेत्र वापिस लेने की बात करते हैं लेकिन जब उसके पास अणुबम है तो हम उसके विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं। जब तक हमारे पास शक्ति नहीं होगी हम अपना इलाका कभी वापिस नहीं ले सकते। जब तक हम कुछ कर नहीं सकते, कहना भर तो अपनी और दुनिया की दृष्टि में मूर्ख बनने वाली बात है।

मैं कहता हूं कि सरकार कोरी सिद्धान्तवादी बातों में क्यों फंसी हुई है, वह तीन महीने का नोटिस दे कर अणुबम निषेध सन्धि से हट सकती है। मुझे विश्वास है कि आज श्री नेहरू जीवित होते तो अणुबम न बनाने की घोषणा कभी न की जाती।

आज प्रधान मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मंत्रिमंडल ने अभी फैसला नहीं किया कि अणुबम बनाया जाय या नहीं। तो उन्होंने फैसला किये बिना ही कैसे कह दिया कि हम अणुबम नहीं बनायेंगे।

हमारी रक्षा नीति और कूटनीति का परिवेश ही बदल गया है। गुटों में शामिल न होने की हमारी नीति का क्या आधार रह गया है? चीन के पास अणुबम के होते हुए हम इस नीति पर चल सकते हैं? यह सोचना मूर्खता होगी कि चीन और रूस हमेशा लड़ते रहेंगे, कभी न कभी वे फिर मिल जायेंगे क्योंकि वे मित्र हैं। और फिर हमें किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ेगा।

शान्ति की नीति तो ठीक है लेकिन क्या शान्ति की खातिर हम अपनी सेना तोड़ देंगे? सरकार ने इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। वह बदली हुई परिस्थिति में पुरानी नीति पर चलने की चेष्टा कर रही है।

चीन के पास अणुबम आ जाने से हमारे पड़ौसियों के साथ हमारे सम्बन्धों पर असर पड़ेगा। वे हमारा नहीं बल्कि चीन का साथ देंगे क्योंकि वह शक्तिशाली है।

अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष डा० भाभा बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अणुबम के सम्बन्ध में असली जानकारी दी। सरकार को चाहिए कि एक कमेटी बनाये जिसमें राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक हों और वह इस मामले पर विचार करे।

जो सरकारी अधिकारी कूटनीतिक प्रतिनिधि बना दिये जाते हैं उन्होंने ठीक काम नहीं किया। कारण यह है कि उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं होता और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर वे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकते। काहिरा सम्मेलन में शोम्बे के भाग लेने के प्रश्न पर हमारे अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में भी सरकारी अधि-कारियों का काम इसी प्रकार असन्तोषजनक रहा है। इसलिए कूटनीतिक क्षेत्र में उनका भाग कम करना चाहिए।

नागालैंड का मामला विदेश मंत्रालय से छीन कर गृह मंत्रालय के हाथ में दे देना चाहिए।

सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम राष्ट्र मंडल में रहें या नहीं। ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ पक्षपात करता है और उसकी कई कार्रवाइयां हमारे हितों के विरुद्ध होती हैं। अतः हमें इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिए।

Shri R. G. Dubey (Bijapur North) : Mr. Speaker, Sir, I have heard the speeches of Dr. Lohia on this Motion as also on the food debate. After having heard them it appears that his views are desparate and anarchist.

It has been said by the critics that our relations with our neighbours were not friendly . The first thing that Sardar Swarn Singh did soon after taking over as Foreign Minister was to pay friendly visits to the neighbouring countries of Nepal, Burma, Ceylon and Afghanistan. He also took concrete steps for solving the age-oldproblem of Indian nationals and people of Indian origin in Burma and Ceylon. That clearly shows how keen Government is on improving relations with our neighbours. Government has also been criticized for having taken a 'Weak attitude' in solving those problems. Now one cannot blow hot and cold in the same breath. Friendship and strong attitudes do not go together.

The House has paid sufficient attention to the question of the Chinese nu-, clear blast. The views exprssed by Dr. Lohia, Shri Nath Pai, Shri Frank Anthony and Shri Masani on the subject were, however, contradictory. After having heard them one is inclined to feel that the policy pursued by the Government was the correct one. Whereas Shri Masani admits that India's joinin g the atomic race would be disastrous, Shri Nath Pai contends we should develop our own nuclear power and not depend upon British or American nuclear umbrella. India is a poor country; it cannot afford to spend its entire budget on the development of atomic power. Though we want to defend our territorial integrity at all cost, we at the same time want that peace should prevail in the world. We want to contribute our mite towards that end. We cannot go on pleading for the test ban treaty on the one hand and manufacturing the atomic weapons on the other. We cannot talk of peace and war in the same breath. Our policy of non-alignment is a correct one. Shri Shastri's participation in the Conference of the Non-aligned Nations at Cairo has enhanced the prestige of India among the nations of Asia and Africa. China was isolated there. That was a positive achievement for our country.

Dr. Lohia talks of revolution in time and out of time. Revoluiton cannot come through a magic wand. We must patently work for it.

There have been a welcome change in the Government in U.K. Labour has come into power. It would help the anti-race hatred campaign in Africa.

The changes that have, of late, taken place in Soviet Union are an internal matter for that country. But the way Shri Khruschev has been removed unceremoniously from power there while accepting his policies is not going to enhance the cause of communism. It did not reflect well on that system.

The election of Mr. Jhonson as President of the U.S.A. also augured well for the peace of the World.

If there is any danger to world peace today, it is from China. She does not believe in peace. The Chinese leaders believe that the cause of Communism could be furthered by violence and insurrection. We should have drawn the attention of the world to this danger of neo-imperialism of China. We should take steps to face the Chinese menace but that does not mean we should join the nuclear race.

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा सम्बन्धी कोई समझौता या करार करना चाहिए । चीन और भारत के बीच लड़ाई छिड़ जाने पर यदि रूस अमरीका को आगाह कर देगा कि

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

चीन पर किसी प्रकार के हमले से उन दोनों देशों में आण्विक युद्ध छिड़ सकता है, तो अमरीका कभी भी चीन पर हमला नहीं कर सकता है। अमरीका चीन के लिए कोई रोक नहीं। भारत और अमरीका के बीच सैनिक संधि से चीनी-रूसी समझौता पुनर्जीवित हो जायगा।

रूस, चीन को भारत पर हमला करने से रोका हुआ है। चीन को भारत पर विजय पाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि भारत हार गया तो चीन समस्त अफ्रेशियाई जगत पर छा जायगा।

चीन के अणु बम विस्फोट और रूस में ख्रुश्चेव के हट जाने से विश्व स्थिति में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आया है। रूस और अमरीका के नेता एक दूसरे के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं। आण्विक गतिरोध ने अमरीका और रूस को एक बंधन में बांध दिया है। वह एक-दूसरे से युद्ध नहीं कर सकते हैं। दोनों देश चीन के साथ भी कोई सुलह नहीं कर सकते हैं क्योंकि चीन उस तरह से खत्म हो सकता है। चीन साइबेरिया, रूसी तुर्किस्तान और एशिया और अफ्रीका के बहुत से भागों को अपने असर में लाना चाहता है। रूस इसकी इजाजत नहीं दे सकता है। यही कारण है कि रूस और चीन के बीच हुए समझौते को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। इसके उलट रूस और अमरीका के बीच इस आधार पर राजनीतिक समझौता अपरिहार्य है कि अफ्रेशियाई खंड और चीन के दो प्रभाव क्षेत्रों में अर्थात अमरीकी प्रभाव क्षेत्र और रूसी प्रभाव क्षेत्र में विभक्त किया जाये। चीन न केवल रूस और अमरीका के लिए खतरा है अपितु समस्त विश्व के लिए खतरा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक समझौता चीन के मुकाबले में दोनों के सैनिक दृष्टि से कमजोर बना देगा। लड़ाई छिड़ जाने पर यदि रूस और अमरीका तटस्थ रहे तो चीन सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय पा सकता है। यदि भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के निकट आयें तो रूस को या तो तटस्थ रहना पड़ेगा या चीन के साथ गठजोड़ करना पड़ेगा।

अमरीका के हित में यह बात नहीं है कि वह भारत को पाकिस्तान के साथ सुलह करने के लिए मजबूर करे। इसके लिए पहले रूस और अमरीका में और रूस और पाकिस्तान में राजनीतिक समझौता हो जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान में समझौता केवल तभी हो सकता है जब पाकिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और मध्य एशिया संधि संगठन से बाहर आये, चीन–पाकिस्तान समझौता को रद्द करे तथा अखिल इस्लाम राज्य स्थापित करने के स्वप्न छोड़ दे।

चीन चाहता है कि रूस और अमरीका के बीच मतभेद बढ़े। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ सुलह करके उनके हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए। यदि रूस और अमरीका कमजोर पड़ें तो चीन विश्व का सब से शक्तिशाली राज्य बनेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याएं एशिया और अफ्रीका की समस्याएं हैं। अमरीका के राज्यों में संघर्ष के कारण कभी भी विश्व युद्ध नहीं हुआ है। यूरोप के देशों में झगड़ों के कारण विश्व युद्ध छिड़ जाने की भी सम्भावना नहीं क्योंकि वह उत्तर अतलांतिक संधि और वारसा संधि है। यूरोप के विभाजन के कारण गुरुत्व आकर्षण केन्द्र अब अफ्रीका और एशिया के क्षेत्र में आ गया है।

विदेश मंत्री को पड़ोसी देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश के लिए बधाई दी गई है। ह ठीक ही है। लेकिन मेरे विचार में अफ्रीकी-एशियाई देशों की एकता का लक्ष्य न सम्भव है और न ही वांछनीय। यह देश मित्र तब ही बन सकते हैं जब कि निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त हो। इन देशों की राजनीतिक एकता तभी लाई जा सकती है जब न केवल इंगलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और अमरीका इन क्षेत्रों से निकल आये अपितु रूस भी इन क्षेत्रों से निकल आये। यदि अफ्रीका और एशिया के देश एक हो जायें जोकि असम्भव दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह होगा कि सम्पूर्ण यूरोप भी एक हो जायगा और अमरीका के राज्य भी एक हो जायेंगे।

अफ्रीकी-एशियाई देश आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होंगे, वह बड़े अतलांतिक राज्य के पुछलग्गू होंगे। यदि अमरीका और रूस को अफ्रीकी-एशियाई देशों की एकता के लिए इन क्षेत्रों से निकलना पड़े तो इसका नतीज़ा यह होगा कि एशिया-अफ्रीका के कुछ भाग पर अखिल इस्लामी राज्य छा जायेगा और कुछ पर चीन। इनके निकल आने से सम्पूर्ण क्षेत्र में गड़बड़ और अराजकता फैल जायगी। अफ्रीकी नेता अफ्रीकी व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं। यह अफ्रीका और एशिया के देशों को एक ही राजनीतिक इकाई में संगठित नहीं करना चाहते हैं।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलने के लिये जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : We are discussing very important subject. There is no quorum in the House as such the discussion should not go on.

Mr. Speaker : The hon. Member may continue tomorrow.

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 24 नवम्बर, 1964/ 3 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 24, 1964/Agrahayana 3, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSII—2031 (Ai)LSD—3-3-65—600.